सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

06 मार्च, 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय,

पटना ।

सप्तदश विधान सभा   वृहस्पतिवार, तिथि 06 मार्च, 2025 ई०
चतुर्दश सत्र   15 फाल्गुन, 1946 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ।

तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं0–300 श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (आरा)

(लिखित उत्तर)

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत धान की अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य 45 लाख मे०टन के विरूद्ध निर्धारित अंतिम तिथि–15.02.2025 तक 6732 क्रय केन्द्रों (पैक्स/व्यापार मंडलों) के माध्यम से 4.63 लाख किसानों से 39–23 लाख मे०टन धान की अधिप्राप्ति की गई है, जो निर्धारित लक्ष्य का 87.17% है।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, अमरेन्द्र बाबू ।

(व्यवधान)

बैठ जाइए । भाषण दे चुके आप । हो गया बजट । आज बजट पर ही भाषण है । बैठ जाइए, महबूब जी । बैठ जाइए । पूरक पूछिये अमरेन्द्र बाबू।

(इस अवसर पर सी0पी0आई (एम0एल0) (एल0) के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

किसी पोस्टर की अनुमति नहीं है, पोस्टर ले लिया जाय, पोस्टर हटाइए, हटा लीजिए । दे दीजिए महबूब साहब । बैठ जाइए अपने स्थान पर । बैठ जाइए महबूब साहब । बैठ जाइए न, बोल चुके न आप । कल बजट पर भाषण तो हुआ ही न । आज भी होने वाला है । बैठ जाइए न, बैठियेगा तब न होगा । वेल में कही गई कोई भी बात प्रोसीडिंग में नहीं जाने वाली है । बैठ जाइए, अपने स्थान पर जाएं । प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए । आप क्या चाहते

हैं, गोपाल रविदास जी का क्वेश्चन न हो ? गोपाल रविदास जी का क्वेश्चन नहीं होने देना चाहते हैं ? झगड़ा है आपकी पार्टी के अंदर ? आपकी पार्टी में आपस में झगड़ा है क्या ? गोपाल जी का क्वेश्चन समाप्त करना चाहते हैं ? आप जान लीजिए अभी जो एक से दस नंबर तक क्वेश्चन है उसमें 7 क्वेश्चन विरोधी दल के लोगों का है । आप क्यों उनके क्वेश्चन को बाधित करना चाहते हैं ? अपने स्थान पर जाइए ।

(व्यवधान जारी)

आपके दल के गोपाल रविदास जी का भी क्वेश्चन है । आप क्यों उनके क्वेश्चन को बाधित करना चाहते हैं ? बैठ जाइए । अमरेन्द्र बाबू, पूरक पूछिये।

(व्यवधान जारी)

बैठ जाइए न । यहां से कोई भाषण होता है क्या ? अपने स्थान पर जाइए। पूरक पूछिये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । मैं उससे सहमत नहीं हूं । महोदय, प्रश्न पूछने का मूल उद्देश्य मेरा यही है कि 15 नवंबर से जनवरी मध्य तक पैक्सों और व्यापार मंडलों के द्वारा किसानों से धान की खरीददारी एक–तिहाई हुई, तो करीब 25 दिनों में लक्ष्य कैसे और कहां से पूरा कर लिया ? इसके पीछे का सत्य जानने का क्या माननीय मंत्री जी ने प्रयत्न किया है पहला ?

दूसरा, क्या यह सही है कि लक्ष्य पूरा बिचौलियों और मिलरों से धान खरीदकर पूरा किया जाता है ? एम0एस0पी0 का पैसा किसानों की जेब में जाने के बजाय बिचौलियों और मिलरों की जेब में जाता है, यह सही है, यह सत्य जानने का प्रयत्न किया है ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइए न । गला बझ जाएगा आपका । बैठ जाइए न । हमको आपके गले की चिंता लगी रहती है । बैठ जाइए ।

माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत धान की अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य 45 लाख मे॰टन के विरूद्ध निर्धारित अंतिम तिथि–15.02.2025 तक 6732 क्रय केन्द्रों (पैक्स/व्यापार मंडलों) के माध्यम से 4.63 लाख किसानों से 39–23 लाख मे॰टन धान की अधिप्राप्ति की गई है, जो निर्धारित लक्ष्य का 87.17 प्रतिशत है।

अध्यक्ष : एक और पूरक पूछिये, दो पूरक पूछ लिये हैं आप ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : जब किसान अपना धान लेकर जाता है तो उस समय यह खरीददारी होती नहीं है । जब किसानों का धान औने–पौने दाम में बिक जाता है तो खरीददारी शुरू होती है । महोदय, मैंने कहा, अभी भी यह उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : पूरक मेरा यही है कि उसके पीछे का सच बताएं और नहीं मालूम है तो जानने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पिछले वित्तीय वर्ष में अधिप्राप्ति 66 परसेंट हुआ था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में, चालू वित्तीय वर्ष में हमलोगों ने 87 परसेंट धान की प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त किया है । ये नीतीश कुमार की सरकार किसानों की सरकार है । गरीबों की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार हम सबों के नेतृत्व में आज किसानों को 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे में चार लाख 63 हजार किसानों के खाते में राशि भेजने का काम किया गया है । उनका कोई और सवाल है तो निश्चित तौर पर सरकार विचार करेगी ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय...

अध्यक्ष : तारकिशोर जी, बोलिए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, यह बात सही है कि माननीय मंत्री जी ने जो बातें कही हैं कि सरकार की मंशा किसानों के धान खरीद के प्रति पूरी ईमानदारी है लेकिन महोदय, वास्तव तथ्य यह है कि हम माननीय मंत्री जी...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि सिर्फ आंकड़ों के आधार पर आप यह धारणा नहीं बनाएं कि किसानों के धान की खरीददारी हो चुकी है । कटिहार सहित पूरे राज्यों में अतिरिक्त राशि पैक्स के द्वारा वसूल की जा रही है ।

अध्यक्ष : तारकिशोर जी, पूरक पूछिये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : क्या माननीय मंत्री जी इस तरह की चीजों को रोक लगाकर प्रत्येक जिलों में आप वरीय अधिकारी से जांच कराकर स्पष्ट तौर पर देखें कि जो मूल किसान है, जो धान बेचना चाहता है, क्या उसका धान पैक्स तक

पहुंच पाया ? अगर पहुंचा तो उसको जो उचित राशि सरकार के द्वारा दी जाती है वह दी गई है ? यही जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य तारकिशोर जी ने जो सवाल उठाया है ये स्पेसिफिक बता दें कि कहां गड़बड़ी हुई है हम निश्चित तौर पर एक हफ्ते के अंदर में जांच कराकर वैसे पदाधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम करेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : श्री गोपाल रविदास ।

तारांकित प्रश्न सं0–301 श्री गोपाल रविदास (फुलवारी)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

आपके शोरगुल के कारण आपके एक मेंबर का क्वेश्चन नहीं हुआ । आप अपने स्थान पर बैठ जाइए । अपने स्थान पर चले जाइए । आपके एक मेंबर का क्वेश्चन नहीं हुआ । आपका उनसे झगड़ा है ? गोपाल रविदास जी से आपका झगड़ा है क्या ? आप नेता हैं अपने पार्टी के, दल के नेता हैं और अपने मेंबर का क्वेश्चन मार रहे हैं आप । बैठ जाइए अपने स्थान पर । श्री प्रमोद कुमार सिन्हा ।

तारांकित प्रश्न सं0–302 श्री प्रमोद कुमार सिन्हा (रक्सौल)

(लिखित उत्तर)

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक । नगर परिषद् रक्सौल क्षेत्रान्तर्गत रेलवे कॉलोनी परिसर में एक छोटा पार्क/उद्यान अवस्थित है ।

एक अन्य पार्क/नगर उद्यान का निर्माण कराने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्, रक्सौल द्वारा अंचल अधिकारी, रक्सौल से पत्रांक–115, दिनांक–28.02.2025 द्वारा भूमि की मांग की गयी है । भूमि उपलब्ध होने के उपरांत पार्क/उद्यान निर्माण कराने की कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, रक्सौल एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शहर है, मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि वह पर्यटकीय दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा शहर है, वहां रक्सौलवासी पर्यटक नहीं होने से केवल रोड पर टहलते हैं, इसलिए वहां पर जितनी जल्द हो सके वहां पार्क बनाने की शुरुआत की जाय ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, वही सरकार की भी चिंता है और इसके लिए अंचलाधिकारी से जमीन मांगी गई है, दूसरे महीने, 28.02.2025 को, पत्रांक–115 के द्वारा अंचलाधिकारी से जमीन मांगी गई है । जमीन मुहैया होते ही एक अन्य विस्तृत पार्क बनाने की योजना विभाग की है । हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि ये भी वहां थोड़ा सहयोग करके जल्दी से जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया करवा लें तो हम तुरंत इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : बहुत–बहुत धन्यवाद मंत्री जी ।

अध्यक्ष : श्री अजय यादव ।

तारांकित प्रश्न सं0–303 श्री अजय यादव (अतरी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह । विपक्षी विधायक का क्वेश्चन आप रूकवा रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0–304 श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (नबीनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय सरावगी, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक ।

2. स्वीकारात्मक ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि गत वित्तीय वर्ष–2023–24 के लिए भू–राजस्व संग्रहण (भू–लगान, सेस, सैरात एवं विविध) का निर्धारित लक्ष्य 550 करोड़ के विरूद्ध कुल–410.05 की वसूली हुई है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में भू–राजस्व संग्रहण (भू–लगान, सेस, सैरात एवं विविध) का निर्धारित लक्ष्य 600 करोड़ के विरूद्ध दिनांक–25.02.2025 तक कुल–450.74 करोड़ की वसूली हुई है, जबकि भू–लगान मद में दिनांक–24.02.2025 तक कुल संग्रहित राशि रुपया–312.6 करोड़ है । वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए

भू–राजस्व संग्रहण का जिलावार एवं माहवार लक्ष्य का निर्धारण कर सभी जिलों को विभागीय पत्रांक–1479(9), दिनांक–11.06.2024 एवं पत्रांक–1415(9), दिनांक–03.06.2024 द्वारा संसूचित है ।

उल्लेखनीय है कि राजस्व संग्रहण की प्रगति की नियमित समीक्षा विभाग स्तर पर की जाती है । साथ ही, इसकी समीक्षा मुख्य सचिव, बिहार के स्तर पर भी समय–समय पर की जाती है । राजस्व संग्रहण की वसूली निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ससमय सुनिश्चित किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक–2510(9), दिनांक–09.09.2024 तथा पत्रांक–339(9), दिनांक–31.01.2025 द्वारा सभी जिला समाहर्त्ता को वांछित दिशा–निर्देश संसूचित किये गये हैं । एतद्‌र्थ, ऑनलाईन भू–लगान जमा करने की कार्रवाई हेतु सभी अंचल कार्यालय स्तर पर CSC (Common Service Centre) की सुविधा देते हुए इसे अधिकृत किया गया है । हितबद्ध भू–धारियों/नागरिकों को इसकी सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए उक्त CSC का स्थानीय स्तर पर प्रचार–प्रसार के लिए भी निदेश संसूचित किये गये हैं । इसके अतिरिक्त, राजस्व कर्मचारी के स्तर पर हल्कावार कैम्प का आयोजन किये जाने, रैयतों को बकाया लगान भुगतान हेतु प्रेरित करने तथा सभी जमाबंदियों में अंतिम लगान का विवरण दर्ज किये जाने ताकि इन जमाबंदियों से भू–राजस्व संग्रहण की कार्रवाई की जा सके, के लिए भी सभी जिला समाहर्त्ताओं को विभाग स्तर से दिशा–निर्देश सम्प्रेषित किये गये हैं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, विजय जी ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने स्वीकार किया है कि पिछले छह वर्षों में कभी भी राजस्व संग्रह लक्ष्य के अनुरूप नहीं हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या लक्ष्य के अनुरूप राजस्व की वसूली नहीं किये जाने के कारणों का पता लगाया गया है और उसके द्वारा कराये गये उपायों का क्या किया गया है ?

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तृत जवाब दिया है और मैंने बताया है, इनका था 600 करोड़ के विरुद्ध 296 करोड़ की वसूली हुई है । अध्यक्ष महोदय, इसमें 312 करोड़ की वसूली हुई है और दो माह अभी बाकी भी हैं। विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है । अध्यक्ष महोदय, नीचे जो राजस्व कर्मचारी स्तर पर हैं हल्कावार कैंप लगाया जा रहा है और रैयतों को बकाया लगान भुगतान हेतु प्रेरित करने के लिए सभी जमाबंदियों में अंतिम लगान का विवरण दर्ज किया जा रहा है । विभाग लगातार प्रयास में है कि लक्ष्य निर्धारित कर लें और प्रयास करेंगे कि निश्चित रूप से जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया जाय ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइए । अभी सदन 28 मार्च तक चलने वाला है । बैठ जाइए ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऑनलाईन और ऑफलाईन दोनों तरह से राजस्व की वसूली सरकार करना चाहती है कि नहीं ? क्योंकि अभी तक जितने जमाबंदी हैं वह ऑनलाईन नहीं हो पाई है, उसके चलते बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं ।

(क्रमशः)

टर्न–2 / आजाद / 06.03.2025

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : (क्रमशः) दूसरा मेरा एक और पूरक है, अभी तक जागरूकता के लिए ....

अध्यक्ष : एक मिनट, अपने स्थान पर बैठिए । माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हमलोगों की बातों का संज्ञान लें .....

अध्यक्ष : ये खड़े क्यों हैं ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वही कह रहे हैं न । इस सदन में किन बातों का संज्ञान लिया जायेगा और किनका नहीं लिया जायेगा, यह आपके नियमावली में दर्ज हैं । ये अपनी बातों को नियमानुसार आपकी इजाजत से उठायेंगे तो सरकार संज्ञान लेगी...

अध्यक्ष : बिल्कुल ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वैसे सदन के नियम के विपरीत सरकार भी कैसे संज्ञान में ले सकती है ?

अध्यक्ष : अब बैठ जाईए, अब कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही है । बैठ जाईए । आपके खड़े होने से नहीं होगा । माननीय सदस्य श्री विजय जी ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक राज्य में कितने कैम्प लगाये हैं ...

अध्यक्ष : विजय जी, बैठिए ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : ऐसे बोल रहे हैं तो यहां सुनायी नहीं पड़ता है । अगर आपको कोई समस्या है तो आप लिखकर हमको दे न दीजिए, हम उसको देखेंगे, जाकर बैठिए । आप काहे के लिए खड़े हैं ।

अध्यक्ष : अब हो गया, चलिए जाकर बैठिए । बैठ जाईए ।

(इस अवसर पर सी0पी0आई0(एम0एल0) (एल0) के माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी सीट पर चले गये)

महबूब साहेब, अब बैठिए । महबूब साहेब, आपको देखकर के कभी–कभी जब आप यह सब करते हैं तो मुझे एक बात ध्यान में आता है कि अगर आपके नाम के आगे एक पाई खींच देते महबूबा हो जाता तो आपको तीन तलाक मिल जाता, जितना आप लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं ।

बोलिए माननीय सदस्य ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि अभी तक पूरे राज्य में कितने जगह कैम्प लगाकर किसानों के जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया है, दूसरा है कि पूरे राज्य भर में पंचायत में पंचायत सरकार भवन बना हुआ है या निर्माण हो रहा है लेकिन एक भी कर्मचारी आपका पंचायत सरकार भवन में उपलब्ध नहीं रहता है, वह सीधा ब्लॉक या अंचल में मौजूद रहता है, इसके चलते बहुत ज्यादा परेशानी और राजस्व की हानि हो रही है । इसलिए हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी, इसपर अपना जवाब स्पष्ट करें ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है वह भू–लगान के लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में है और मैंने विस्तृत जवाब दिया है कि भू–लगान जमा, भू–लगान जमा करने की कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा सभी सी0एस0सी0 सेंटर पर अध्यक्ष महोदय, सभी सी0एस0सी0 सेंटर पर सुविधा देते हुए अधिकृत किया गया है और ज्यादा से ज्यादा लगान आये, उसके लिए कर्मचारी स्तर पर हल्कावार जो है, कैम्प लगाया जा रहा है ताकि सभी जगहों पर ज्यादा से ज्यादा राजस्व आये और उसका लक्ष्य का प्राप्ति हो । महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि हल्का कर्मचारी .....

अध्यक्ष : आप कभी–कभी अपने को विधायक ही मान लेते हैं । ठीक है, समय लगेगा एकाध दिन ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : थोड़ा समय लगेगा सर । महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है पंचायत सरकार भवन पर जो है, हल्का कर्मचारी नहीं रहते हैं, उसके लिए हमलोग देख रहे हैं । इस प्रश्न में नहीं है लेकिन आम जनता का प्रश्न है,

पिछले दिनों कुछ कर्मचारियों की बहाली भी हुई थी और भी बहाली हमलोग कर रहे हैं तो पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंचायतों में जितने कर्मचारी होने चाहिए, उतने कर्मचारी नहीं हैं । लेकिन जहां–जहां कर्मचारी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि जहां उनका कार्यालय है, जहां उनका स्थल है, उसपर निश्चित रूप से रहें और एक अभियान चलाकर जिला पदाधिकारी को निर्देशित भी किया जायेगा कि जहां–जहां हल्का कर्मचारी स्थल है, उस स्थल पर निश्चित रूप से बैठें और आम जनता को वहां पर सुविधा मिले लेकिन हल्का कर्मचारी हल्का एरिया से दूर जाकर बैठें तो निश्चित रूप से माननीय सदस्य की जो चिन्ता है, उसको हमलोग कर रहे हैं ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : अब आपका तीन हो गया, अब आप बैठ जाईए ।

तारांकित प्रश्न सं0–305(श्री बिजय सिंह, बरारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बिजय सिंह । माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग । बरारी प्रखंड में गंगा नदी के कटाव से पीड़ित परिवार फुलवरिया चौक से काढ़गोला घाट तक भूमि अधिग्रहण के संबंध में है ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब अगली तिथि को ।

अध्यक्ष : ठीक है, इसका जवाब अगली तिथि को आयेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0–306(श्री छत्रपति यादव,खगड़िया)

(लिखित उत्तर)

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : उत्तर अस्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि खगड़िया प्रखंड अन्तर्गत रक्सौल पंचायत 20वीं पशुगणना के अनुसार पशुओं की संख्या 3987 एवं माडर दक्षिण तथा माडर उत्तर में पशुओं की संख्या 4591 है ।

खगड़िया प्रखंड अन्तर्गत कुल 26 पंचायत है तथा पूर्व से ही 4 पशु चिकित्सालय क्रमशः अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय, खगड़िया प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, नन्कू मंडल टोला, रामनगर मठ एवं बेला पूर्व से संचालित है ।

अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय, खगड़िया रसौंक पंचायत की दूरी लगभग 6 कि0मी0 एवं माडर दक्षिण तथा माडर उत्तर की दूरी लगभग 5 कि0मी0 है । अतः विभागीय मानक के अनुसार नये पशु चिकित्सालय का निर्माण विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य छत्रपति जी, पूरक पूछिए ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, हमने जो प्रश्न किया, उसका जवाब सही–सही नहीं आया है और यह बार–बार ऐसे ही लगातार तीन साल से हो रहा है । हमने कहा है कि जो रसौंक पंचायत माडर उत्तरी व माडर दक्षिणी पंचायत में पशु अस्पताल का स्थापना करना है, जहां पशु की संख्या अधिक है । ये अपने उत्तर में लिखा है कि अस्वीकारात्मक है और वस्तुस्थिति बता रहे हैं कि गणना के हिसाब से 3987 और 4591 पशुओं की संख्या बता रहे हैं और बता रहे हैं चार पशु अस्पताल के बारे में जिक्र किये हैं कि चार पशु चिकित्सालय, अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय, खगड़िया प्रथमवर्गीय चिकित्सालय, नन्कू मंडल टोला .....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए न, वह तो उत्तर में लिखा हुआ है ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष जी, जरा सुना जाय । वहां पर आज तक अस्पताल का भवन नहीं है, इसका हमने मांग भी किया है लगातार तीन साल से और सरकार लगातार गोल–मटोल सरकारी अधिकारी रिपोर्ट देते हैं । यह पंचायत तन्दूरी नगर पंचायत में पड़ती है खगड़िया पशुपालन अस्पताल सर, वहां जाने में काफी कठिनाई होती है सर .....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, हम चाहते हैं कि सरकार इस पंचायत में कब तक पशु अस्पताल की स्थापना करना चाहती है या नहीं चाहती है, अगर नहीं चाहती है तो क्यों नहीं चाहती है ?

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर अस्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि खगड़िया प्रखंड अन्तर्गत रक्सौल पंचायत 20वीं पशुगणना के अनुसार पशुओं की संख्या 3987 एवं माडर दक्षिण तथा माडर उत्तर में पशुओं की संख्या 4591 है ।

खगड़िया प्रखंड अन्तर्गत कुल 26 पंचायत है तथा पूर्व से ही 4 पशु चिकित्सालय क्रमशः अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय है, खगड़िया प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय,नन्कू मंडल टोला, रामनगर मठ एवं बेला पूर्व से संचालित है ।

अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय, खगड़िया रसौंक पंचायत की दूरी लगभग 6 कि0मी0 एवं माडर दक्षिण तथा माडर उत्तर की दूरी लगभग 5 कि0मी0 है । अतः विभागीय मानक के अनुसार 10 कि0मी0 के बाहर ही कोई भी नया पशु चिकित्सालय का निर्माण होता है । माननीय सदस्य की चिन्ता है लेकिन यह मात्र 5 कि0मी0 के अन्दर है और वहां पर पहले से चार–चार पशु अस्पताल चल रहे हैं,जबकि वहां पर प्रथमवर्गीय चिकित्सालय भी है । अतः इस मानक के अनुसार नये पशु अस्पताल का निर्माण विचाराधीन नहीं है ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, यह सरकारी रिपोर्ट है ...

अध्यक्ष : सरकार ही न रिपोर्ट देती है ।

श्री छत्रपति यादव : एक मिनट अध्यक्ष जी, ग्रामीण स्थिति को समझिए, जहां से ये दूरी बता रहे हैं, वहां के अंतिम छोर से 11 कि0मी0 दूरी पड़ता है और वहां से नन्कू मंडल टोला 20 कि0मी0 पड़ता है, रामनगर मठ वहां से 25 कि0मी0 पड़ता है और जो नगर का अस्पताल बता रहे हैं, वहां से 9 कि0मी0 पड़ता है । वर्तमान स्थिति में 20वीं पशुगणना बता रहे हैं, आज हमारे बिहार में पशुपालक परिवार की संख्या ज्यादा है, अगर सरकार विचार नहीं करेगी तो पशुपालक की हालत क्या होगी, इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि इसपर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष : आपको पूरक पूछना है तो पूछिए ।

श्री छत्रपति यादव : पूरक है कि अस्पताल बनाया जाय,

अध्यक्ष : इसपर उन्होंने बताया कि 10 कि0मी0 मानक के अन्दर अस्पताल है ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, इसमें मानक नहीं देखा जाय सर, वर्तमान समय की परिस्थिति देखा जाय, 20वीं पशुगणना नहीं देखा जाय, सरकारी विभाग की कमिटी बना दी जाय और उसकी जॉच करा ली जाय, अगर गलत होगा तो अस्पताल नहीं बनाया जाय, अगर जॉच के बाद बनता है तो बनाया जाय, यही हमारी आपसे मांग है ।

अध्यक्ष : ठीक है, इसको आप एक बार फिर से देखवा लीजिए ।

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : ठीक है अध्यक्ष जी, हम इसको देखवा देंगे । इसमें सबसे बड़ी बात है माननीय अध्यक्ष जी....

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : खगड़िया में आप कहां हैं, कहां मधुबनी और कहां खगड़िया, आप बैठिए । यह जेनरल नहीं, यह एक पार्टिकुलर प्रखंड का है । माननीय सदस्य श्री दिलीप राय जी ।

टर्न–3/पुलकित/06.03.2025

तारांकित प्रश्न सं0–307 (श्री दिलीप राय, सुरसंड)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : स्वीकारात्मक । यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर प्रखंड के बरहेत्ता पंचायत में पैक्स का गोदाम नहीं है ।

अध्यक्ष, बरहेत्ता पैक्स, प्रखंड–रून्नीसैदपुर, श्री अभय कुमार सिंह द्वारा दिनांक 09.01.2025 को अपने आवेदन के साथ प्रबंधकारिणी की बैठक दिनांक 25.12.2024 में पारित प्रस्ताव की प्रति संलग्न करते हुए पैक्स में 1000 मे0टन गोदाम निर्माण की मांग की गई है । अध्यक्ष बरहेत्ता पैक्स से प्राप्त आवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक–72, दिनांक 11.01.2025 द्वारा अंचलाधिकारी, रून्नीसैदपुर से 1000 मे0टन गोदाम निर्माण के लिये 30 डी0 सरकारी भूमि की मांग की गई है । अंचलाधिकारी, रून्नीसैदपुर से सरकारी भूमि उपलब्ध होने अथवा सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में लीज की भूमि समिति द्वारा उपलब्ध कराने पर पैक्स के लिये गोदाम निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री दिलीप राय : महोदय, पूछता हूं ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिये ।

श्री दिलीप राय : महोदय, रून्नीसैदपुर प्रखंड के बरहेता पंचायत में पैक्स का गोदाम नहीं है, जिसके कारण अनाज एवं खाद आदि के रख–रखाव में काफी परेशानी होती है । सरकार से हम जानना चाहते हैं कि सरकार गोदाम का निर्माण कबतक करायेगी, इसकी समय–सीमा बता दी जाए ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : उत्तर स्वीकारात्मक । यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर प्रखंड के बरहेत्ता पंचायत में पैक्स का गोदाम नहीं है ।

अध्यक्ष, बरहेत्ता पैक्स, प्रखंड–रून्नीसैदपुर, श्री अभय कुमार सिंह द्वारा दिनांक 09.01.2025 को अपने आवेदन के साथ प्रबंधकारिणी की बैठक दिनांक 25.12.2024 में पारित प्रस्ताव की प्रति संलग्न करते हुए पैक्स में 1000 मे0टन गोदाम निर्माण की मांग की गई है । अध्यक्ष बरहेत्ता पैक्स से प्राप्त आवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी के

पत्रांक–72, दिनांक 11.01.2025 द्वारा अंचलाधिकारी, रून्नीसैदपुर से 1000 मे0टन गोदाम निर्माण के लिये 30 डी0 सरकारी भूमि की मांग की गई है । अंचलाधिकारी, रून्नीसैदपुर से सरकारी भूमि उपलब्ध होने अथवा सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में लीज की भूमि समिति द्वारा उपलब्ध कराने पर पैक्स के लिये गोदाम निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है, सकारात्मक जवाब है ।

तारांकित प्रश्न सं0–308 (श्री हरिभूषण ठाकुर ''बचोल'', बिस्फी)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय सरावगी, मंत्री : स्वीकारात्मक है । समाहर्त्ता, मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार विभागीय पत्रांक–168(9), दिनांकः–20.01.2025 के आलोक में ''परिमार्जन प्लस'' पोर्टल के ई–जमाबंदी मॉडयूल के तहत प्रश्नगत त्रुटियों का सुधार अंचल स्तर से किया जा रहा है । उक्त सुधार 30 दिनों के अंदर कर लिया जायेगा ।

उल्लेखनीय है कि बिहार भूमि पोर्टल पर डिजिटाईज्ड किये गये जमाबंदी में मौजा संबंधी परिलक्षित त्रुटियों का सुधार किये जाने के संबंध में उक्त पत्र द्वारा दिशा–निदेश संसूचित है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिये ।

श्री हरिभूषण ठाकुर ''बचोल'' : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जमाबंदी में 10 की जगह 19 लिखा गया है और उस त्रुटि को एक सेकंड में ठीक किया जा सकता है लेकिन उस त्रुटि सुधार करने के लिए 30 दिन का समय लिया गया है । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि किसानों की समस्या के समाधान के लिए इसको सरकार या मंत्री जी अविलम्ब ठीक करा दें ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, परिमार्जन प्लस पोर्टल के ई–जमाबंदी मॉडयूल के तहत प्रश्नगत त्रुटियों का सुधार अंचल स्तर से किया जा रहा है । मैंने बात भी की है और दूरभाष से भी मेरे सामने मेरे विभाग के अधिकारियों ने बात भी किये हैं, उसमें 30 दिन लिख दिया गया है लेकिन जितना जल्दी होगा उतना शीघ्रातिशीघ्र इसको करा दिया जाएगा । मैंने इस संबंध में सकारात्मक जवाब दिया है।

अध्यक्ष : बचोल जी यह टेक्नीकल चीज है ।

श्री हरिभूषण ठाकुर ''बचोल'' : महोदय, वहां के किसानों को कोई कठिनाई न हो ।

अध्यक्षः मंत्री जी, चिंता करेंगे ।

श्री हरिभूषण ठाकुर ''बचोल'' : ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0—309 (श्री छोटे लाल राय, परसा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक । नगर पंचायत, परसा बाजार के सामान्य बोर्ड की बैठक दिनांक—09.01.2025 को सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया है । सी०सी०टी०वी० कैमरा के क्रय हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है । क्रय की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत विभिन्न चिन्हित स्थलों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा अधिष्ठापित किया जाएगा ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिये ।

श्री छोटे लाल राय : महोदय, परसा बाजार में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाना है । हम यही जानना चाहते हैं कि कब तक सी0सी0टी0वी0 कैमरा लग जाएगा ?

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब स्पष्ट दिया है कि 09.01.2025 को सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने का प्रस्ताव नगर पंचायत, परसा बाजार के सामान्य बोर्ड की बैठक के द्वारा पारित कर दिया गया है । सी०सी०टी०वी० कैमरा के क्रय हेतु जो निविदा की प्रक्रिया हैं वह प्रक्रियाधीन है। क्रय की प्रक्रिया पूर्ण होते ही हम सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा देंगे । आप एकदम निश्चिंत रहिये 90 दिन के अंदर वहां सी0सी0टी0वी0 फंक्शनल हो जाएगा ।

श्री छोटे लाल राय : धन्यवाद मंत्री जी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0—310 (श्री अजीत शर्मा, भागलपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : (1) आंशिक स्वीकारात्मक । नगर आयुक्त—सह—प्रबंध निदेशक भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भागलपुर शहर में स्मार्ट रोड नेटवर्क के तहत—299.30 करोड़ की स्वीकृत राशि (विभागीय संकल्प संख्या ज्ञापांक—3653, दिनांक—03.08.2023 संलग्न) की लागत से कोई 28.93 किलोमीटर (पी0क्यू0सी0 सड़क— 14.96 किलोमीटर एवं Bituminous Concrete सड़क— 13.97 किलोमीटर) लम्बी सड़क स्मार्ट रोड नेटवर्क का कार्य किया गया है ।

स्मार्ट सिटी नेटवर्क के कार्य में अन्य अवयव भी समाहित है, जैसे कि– नाला निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन, हाई मास्ट लाईट का अधिष्ठापन, पेवर ब्लॉक, चेकर्ड टाईल्स, विभिन्न पथों पर साईन बोर्ड के अधिष्ठापन ओवरहेड साईन बोर्ड के अधिष्ठापन, ग्रीनजोन एवं तिलकामांझी से जीरोमाईल पथ पर पौधा लगाने, डॉल्फिन एवं तिलकामांझी मूर्ति के अधिष्ठापन, विभिन्न पथों एवं अन्य संरचनाओं पर 3डी0 पेंटिंग, घंटाघर चौक एवं तिलकामांझी चौक का जीर्णोद्धार एवं डॉल्फिन चौक का निर्माण एवं दो अद्द वर्टिकल गार्डन का अधिष्ठापन का कार्य इत्यादि ।

(2) अस्वीकारात्मक । संवेदक द्वारा ऑपरेशन मेंटनेंस का कार्य किया जा रहा है । साथ ही इस योजना के अंतर्गत अवयवों का आवश्यकतानुसार मेंटेनेंस का कार्य किया जाता रहेगा ।

(3) उपर्युक्त खंडो में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिये ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है । माननीय मंत्री जी को मैं चुनौती देता हूँ जो उनका जवाब हैं वहां न सिर्फ सड़क का मेनटेनेंस नहीं किया जा रहा बल्कि जिन और अवयवों नाला, लाईट आदि की बात कही गयी है उनका भी मेनटेनेंस नहीं हो रहा है । मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसको आप जांच कराकर देखें, जो मैंने बात उठायी हैं और जो जवाब आप दिये हैं वह सही नहीं है । अगर माननीय मंत्री जी नहीं करते हैं तो अध्यक्ष महोदय से मैं मांग करता हूं कि इस मामले की जांच सदन की विशेष समिति बनाकर कराई जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए ।

अध्यक्ष : पहले मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अधीर न हो, सरकार काम कर रही है और आपकी जो अपेक्षा है अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक उदाहरण है जहां यह मेनटेनेंस का काम नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास सारे फोटोग्राफ्स हैं इसके कि मेनटेनेंस का काम हो रहा है । लेकिन अगर किसी ने गलत जानकारी दी है मेनटेनेंस का काम अगर नहीं हो रहा है । माननीय सदस्य काफी सीनियर सदस्य हैं और शहर की चिंता कर रहे हैं तो अगर कोई भी जानकारी इससे संबंधित हो किसी ने गलत जानकारी अगर दी होगी तो मैं उसपर कार्रवाई भी करेंगे और जो यथोचित कार्रवाई है आगे मेनटेनेंस के लिए हैं वह भी यथाशीघ्र प्रारम्भ करेंगे ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : आपका जवाब पूरा हो गया ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि गलत जानकारी दी होगी । हम कह रहे हैं कि वहां सड़क का मेनटेनेंस नहीं हो रहा है, मैं उसी शहर से विधायक हूँ और वहीं रहता हूँ इसलिए माननीय मंत्री जी इसको सही ढंग से जाँच कराइये । वरना हम तो आग्रह किये हैं अध्यक्ष महोदय से कि समिति बनाकर जाँच कराइये ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी का ऐसा लग रहा है कि विभाग जो काम करेगा उसपर कम भरोसा और समिति की जॉच पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रमाण के तौर पर सारे फोटोग्राफ्स लाया हूँ कि मेनटेनेंस हो रहा है । इसके बावजूद मैंने सदस्य को आश्वस्त किया कि आपके पास कोई स्पेसिफिक जानकारी हो किसी जगह शहर का कोई कोना छूटा हुआ हो तो आप शहर के जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, वहां के विधायक हैं । आपकी मांग भी रखी जाएगी और हम विभाग के द्वारा हर हालत में काम करेंगे आप निश्चिन्त रहिये ।

श्री अजीत शर्मा : धन्यवाद ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–311 (श्री नारायण प्रसाद, नौतन)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : 1. आंशिक स्वीकारात्मक । नगर आयुक्त, नगर निगम, बेतिया के पत्रांक 505 दिनांक 25.02.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत समय–समय पर माईकिंग कराकर सड़क एवं नालों पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जाता है । पुनः अतिक्रमण करने पर सामान जब्त किया जाता है तथा अर्थ दण्ड के साथ अतिक्रमण हटाया जाता है । सड़क के किनारे अतिक्रमणकारियों को स्थायी रूप से दुकान बनाकर आवंटित करने हेतु वेंडिंग जोन के निर्माण के लिए सरकारी जमीन की खोज की जा रही है । जमीन उपलब्ध होते ही वेंडिंग जोन का निर्माण कर छोटे व्यवसायियों यथा सब्जी विक्रेता, मछली विक्रेता आदि को जगह आवंटित किया जाएगा, ताकि इन व्यवसायियों के द्वारा पुनः सड़क पर अतिक्रमण नहीं किया जा सके ।

2. अस्वीकारात्मक । अतिक्रमण हटाने का कार्य जिला प्रशासन के सहयोग से नगर निगम के कर्मियों के द्वारा ही किया जाता है ।

3. उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिये ।

श्री नारायण प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यहां प्रश्न है कि कभी–कभी जब हमारे प्रधानमंत्री आते हैं तो उसकी सफाई की जाती है । हवाई अड्डा से लेकर डी0एम0 ऑफिस तक पूरा रोड जाम रहता है जबकि 08 किलोमीटर में हमलोग चलते हैं तो आठ मिनट लगता है । महोदय, दो किलोमीटर चलने में 30 मिनट लगता है इसलिए उसका परमानेंट निदान होना चाहिए ताकि अतिक्रमण वाले व्यक्ति फिर दोबारा वहाँ नहीं लगा लें या कोई दण्ड ऐसा होना चाहिए जिससे उनको महसूस हो कि यहां अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक बार अतिक्रमण मुक्त कर देने के बाद अगर दोबार अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो उसको दोबारा आर्थिक दण्ड के साथ अतिक्रमणमुक्त किया जाता है और यह प्रक्रिया माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है वहां की गयी है और हम उसका स्थाई समाधान ढूंढ रहे हैं । हमने वहां वेंडिंग जोन बनाने के लिए जगह मांगी है । किसी तरह वहां लोगों की रोजी–रोटी चल रही है, वे गरीब लोग हैं जो शहर के किनारे अपनी रोजी–रोटी चला रहे हैं । महोदय, मैं स्थायी समाधान के लिए वहां के अंचलाधिकारी से इसके लिए जमीन मांगी है । जमीन मिलते ही हमारी पूरी योजना है कि हम वेंडिंग जोन बनाकर के इन सभी दुकानदारों को वहां शिफ्ट करेंगे ताकि माननीय सदस्य और नगरवासियों को वहां किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हों ।

श्री नारायण प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जब जमीन मिलेगी तब आप उसको अतिक्रमण मुक्त कराइयेगा । तब तक हमलोग को आने–जाने में घर से और जिला में जाने के लिए आधा घंटा लगता है इसलिए स्थायी निदान करने के लिए अभी कोई ट्रैफिक नियम के तहत वहां कब्जा नहीं हो, इसकी व्यवस्था क्या माननीय मंत्री जी करा सकते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी स्थायी निदान तो कर ही रहे हैं । स्थायी निदान तो वही है।

श्री नारायण प्रसाद : महोदय, अभी जो अतिक्रमण हो जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है । अप्रैल में अतिक्रमणमुक्त किया गया था तब आसानी से हमलोग पांच मिनट में चले जाते थे लेकिन फिर अप्रैल के बाद कोई ऐसा काम नहीं किया गया कि अतिक्रमण हटे ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य से कहा कि हम स्थायी निदान वहां ढूंढ रहे हैं । माननीय सदस्य ने जो कहा तत्काल के लिए तो ये अस्थायी उपाय ढूंढ रहे हैं । अगर इससे संबंधित कोई सुझाव उनके पास हो तो विभाग को वे बतायें हम उस पर काम करेंगे ।

अध्यक्ष : तत्काल एक इन्स्ट्रक्शन दे दीजिए कि अभी अस्थायी के लिए कोई स्पेशल ड्राईव चलाये, कोर्ट का भी आदेश रहता है और स्थायी के लिए जरूर प्रयास करिये ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, मैं उसको करवाता हूँ ।

तारांकित प्रश्न सं0–312 (श्री राजवंशी महतो, चेरिया बरियारपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–313 (श्री रामप्रवेश राय, बरौली)

श्री रामप्रवेश राय : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं निकाल पाये । माननीय मंत्री जी से आग्रह हैं कि वे जवाब पढ़ दें ।

अध्यक्ष : जवाब आप देखें नहीं होंगे । माननीय मंत्री, जवाब पढ़ दीजिए ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक । नगर परिषद्, बरौली, जिला गोपालगंज अन्तर्गत ऑटो, ई–रिक्शा तथा बस पड़ाव हेतु कार्यालय पत्रांक–94, दिनांक–02.02.2019 द्वारा अंचलाधिकारी, बरौली से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था । अंचलाधिकारी, बरौली के पत्रांक–138, दिनांक–09.02.2019 द्वारा सरकारी भूमि चिन्हित कर प्रतिवेदित किया गया, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–

क्र० सं०	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा	जमीन का किस्म
1.	भडकुईया	423	393	2701	38डी0	गैरमजरूबा मालिक परती कदीम
2.	भडकुईया	423	104	2700	1 एकड़ 96 डी0	गैरमजरूबा मालिक परती कदीम

उक्त भूमि पर स्थानीय नागरिकों द्वारा पूर्व से ही व्यवहार न्यायालय में हकियत वाद संख्या–44/1988 एवं 393/2004 दायर किया गया है, जो अभी विचाराधीन है ।

कार्यालय पत्रांक–592, दिनांक–10.07.2024 एवं 1114 दिनांक–18.10.2024 द्वारा अंचलाधिकारी, बरौली से पुनः बस स्टैंड निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । अंचलाधिकारी, बरौली के पत्रांक–2060, दिनांक–16.12.2024 द्वारा नयी भूमि चिन्हित कर प्रतिवेदित किया गया है । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् बरौली के पत्रांक–375, दिनांक–03.03.2025 द्वारा अंचलाधिकारी को भूमि हस्तांतरण करने हेतु स्मारित

किया गया है एवं अंचलाधिकारी से समन्वय भी किया जा रहा है । भूमि उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा ।

टर्न–4 / अभिनीत / 06.03.2025

श्री रामप्रवेश राय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने वर्षों से वहां बस स्टैण्ड और टैक्सी स्टैण्ड के नाम पर निविदा निकाली जाती है, डाक किया जाता है, अभी तक बरौली नगर परिषद में ई–रिक्शा और बस स्टैण्ड के नाम पर कितने रुपये राजस्व की वसूली हुई है और पूरा सड़क जाम रहता है, पूरा शहर जाम रहता है लेकिन अभी तक बस स्टैण्ड, टैक्सी स्टैण्ड की कोई व्यवस्था नहीं हुई है । जरा माननीय मंत्रीजी बतायें कि कितने वर्षों से वहां डाक की व्यवस्था है ? कितना राजस्व अभी तक सरकार को प्राप्त है ? और अभी तक बस स्टैण्ड, टैक्सी स्टैण्ड क्यों नहीं बनाया गया है ?

अध्यक्ष : रामप्रवेश जी, आप तो पुराने आदमी हैं । कई बार वहां से जीते हैं । माननीय मंत्री ने तो बड़ा साफ कहा है कि जो भूमि पहले ली गयी थी उसमें कोर्ट में केस हो गया । अभी विचाराधीन है, उस पर नहीं हो सकता है ।

श्री रामप्रवेश राय : डाक की व्यवस्था तो समाप्त कर दी जाय..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए न, बैठिए ।

श्री रामप्रवेश राय : बिना स्टैण्ड के डाक क्यों निकलता है ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए न । फिर नई भूमि के लिए इन्होंने कोशिश की तो नई भूमि के बारे में भी रिपोर्ट आ गयी है । अब सी0ओ0 से कॉर्डिनेशन हो रहा है तब निर्माण होगा । बाकी जो दूसरा सवाल है बताइये । राजस्व की बात आप कर रहे हैं ?

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, राजस्व के लिए इन्होंने सवाल किया नहीं है । राजस्व अलग विषय है, बस स्टैण्ड बनाने की बात इन्होंने की है । अलग से सवाल जब राजस्व का लायेंगे तो विभाग उसकी भी जानकारी देगा ।

श्री रामप्रवेश राय : समय तो बताइये कि वहां पर टैक्सी स्टैण्ड, बस स्टैण्ड की व्यवस्था कब तक करा देंगे ? पूरा बाजार जाम रहता है, शहर जाम रहता है ।

अध्यक्ष : रामप्रवेश जी, बैठ जाइये । राम प्रवेश जी, बैठिएगा तब न जबाव देंगे ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैंने विस्तार से जवाब दिया है । माननीय सदस्य वहां अंचलाधिकारी से थोड़ा कॉर्डिनेट करके जितनी जल्दी जमीन हस्तांतरित कर देंगे, विभाग तैयार है, पैसे की माननीय मुख्यमंत्री

जी के नेतृत्व में कोई कमी नहीं है इस विभाग के अंदर, हम यथाशीघ्र इस काम को करा देंगे । अगर इसी वित्तीय वर्ष ये करा दें तो हम इसी वित्तीय वर्ष में निविदा की प्रक्रिया करके उसको स्टार्ट करा देंगे ।

अध्यक्ष : जल्दी करा लीजिए । ठीक है बैठिए ।

श्री रामप्रवेश राय : अध्यक्ष महोदय, हम करा देंगे जमीन की व्यवस्था । राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जी से कहें, वे करा देंगे । अब बताइये हमारे पॉकेट में जमीन है ।

अध्यक्ष : नहीं–नहीं आपको भी सहयोग करने के लिए कह रहे हैं । रामप्रवेश जी, आपको केवल सामान्य विधायक नहीं समझते हैं जिवेश जी, आप बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं । कई बार वहां से विधायक रहे हैं, प्रभावशाली आदमी अब हैं, आप भी अपना सहयोग करिए ताकि आपका काम जल्दी हो जाये, यह कह रहे हैं ।

माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या–314 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह, मनिहारी)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय सरावगी, मंत्री : उत्तर अस्वीकारात्मक ।

समाहर्त्ता, कटिहार का पत्रांक–373/रा0, दिनांक–25.02.2025 के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि अमदाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत जंगलाटाल, मौजा–भवानीपुर, थाना नम्बर–351, खाता संख्या–121, खेसरा संख्या–405, रकवा 2.30 एकड़ भूमि खतियान में सर्वसाधारण आम बिहार सरकार है एवं भूमि का किस्म रास्ता है। स्थलीय जांच में पाया गया कि वर्तमान समय में भूमि परती है एवं अतिक्रमण से मुक्त है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, प्रथम खंड में बताया गया है कि यह जमीन सर्वसाधारण आम बिहार सरकार है । यह तो सही है लेकिन दूसरे खंड में बताया गया कि उसमें वर्तमान में वह परती है और अतिक्रमण मुक्त है । महोदय, यह उत्तर सही नहीं है । उसमें अभी भी मक्के की फसल लगी हुई है । महोदय, इस तरह का गुमराह करने वाला उत्तर देने के लिए पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला समाहर्त्ता ने पत्रांक 373, दिनांक–25.02.2025 के अनुसार प्रतिवेदित किया है, वह सही है, स्वीकारात्मक है कि

वह बिहार सरकार, भूमि है, रास्ता है, रिपोर्ट में यही है कि अतिक्रमण मुक्त है । अगर माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त नहीं है, अतिक्रमण है तो मैं जांच करा लेता हूं । निश्चित रूप से जांच कराकर फलाफल से माननीय सदस्य को अवगत भी करा दूंगा ।

अध्यक्ष : ठीक है, जांच करा लीजिए ।

माननीय सदस्य श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या–315 (श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, जहानाबाद)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय सरावगी, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक ।

समाहर्त्ता, मधुबनी के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि घोघरडीहा अंचल अंतर्गत बसुआरी पंचायत के पिपरा कलमपुर गाँव का खेसरा–(पुराना)–180 गैर मजरूआ आम खाते की भूमि है, जिसका किस्म पईन है। इस भूमि पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण करने हेतु पंचायत को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया गया है। इस भूमि को अंचल अमीन से सीमांकन करवाकर कुल 02(दो) व्यक्तियों को अतिक्रमणकारी के रूप में चिन्हित किया गया है। अतिक्रमण मुक्त कराने कि दृष्टि से अंचल कार्यालय, घोघरडीहा में अतिक्रमण वाद–2/2024–25 संधारित करते हुए दिनांक–20.07.2024 एवं दिनांक–19.11.2024 को अतिक्रमणकारियों को नोटिस निर्गत किया गया है।

अतिक्रमित भूमि को एक महीने के अन्दर अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, उत्तर नहीं देख पाये हैं । माननीय मंत्रीजी से चाहेंगे कि उत्तर पढ़ दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित है ।

अध्यक्ष : सुदय जी, पंचायती राज विभाग में ट्रांसफर हुआ है । अगली बार आयेगा ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : जी ठीक है महोदय ।

तारांकित प्रश्न संख्या–316 (श्री विजय शंकर दूबे, महाराजगंज, सीवान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे । पूरक पूछिए ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री सहकारिता विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । पैक्सों की कार्य विविधताओं तथा तकनीकी आवश्यकताओं के तहत पैक्सों में कुशल एवं योग्य कर्मियों की नियुक्ति तथा उनके वेतन मानदेय भुगतान करने में विभाग की भूमिका की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए कार्यालय पत्रांक–1263, दिनांक– 23.12.2024 द्वारा समिति का गठन किया गया है । उक्त समिति द्वारा सभी पहलुओं का अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे अवैतनिक लोगों को या जिनको मानदेय नहीं मिल रहा है उनको इस वर्ष में अनेक विभागों के ऐसे कार्यरत कर्मियों के लिए या तो मानदेय का या उनको रेगूलर करने की व्यवस्था की है । मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आपने पीत पत्र लिखा विभाग को कि इनको मानदेय या नियमित करने पर विचार करने के लिए उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कर्मी प्रबंधक अवैतनिक रूप से कितने दिनों तक काम करेंगे ? और उन पर सरकार द्वारा, उनका काम बढ़ा भी दिया गया है । सारे ऋण का काम, कॉपरेटिव में ऋण का काम, किसानों को ऋण देने के काम में आप इनका उपयोग करते हैं, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इनको मानदेय या वेतन देने में आपको क्या आपत्ति है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, समिति गठित की गयी है, समिति की रिपोर्ट आ जाने के बाद सरकार विचार करेगी ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, यह प्रश्न में ही मैंने दिया है कि ऐसे तो पत्र जारी किया, कई बार विभाग ने कहा और कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती है । आपकी नीयत क्या है ? आपकी नीयत उन कर्मियों के प्रति उदार नहीं है, करना नहीं चाहते हैं । आप स्पष्ट बतायें कि उनको मानदेय या उनको नियमित करने पर सरकार को विचार करने में क्या आपत्ति है ?

अध्यक्ष : सरकार तो विचार करने के लिए कह रही है । रिपोर्ट आयेगी तो विचार करेंगे ।

श्री अजय कुमार : महोदय..

अध्यक्ष : एक मिनट ठहरिए, बैठ जाइये । बोलिए अजय जी ।

श्री अजय कुमार : महोदय, माननीय मंत्रीजी से सिर्फ इतना जनना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने बताया कि एक समिति का गठन हमने कर दिया है । वह समिति की रिपोर्ट कब आयेगी । कितने दिनों में जिसकी मांग माननीय सदस्य कर रहे थे, उनको मानदेय या उनको वेतन, मैं कहना चाहता हूं कि जब आप तमाम जो संविदा पर थे उनको आपने किया है, जो जूनियर इंजीनिर थे उनको आपने वेतन, उनको रेगूलर कर दिया है...

अध्यक्ष : अजय जी, कहिए नहीं पूछिए ।

श्री अजय कुमार : महोदय, वही मैं पूछना चाहता हूं कि आप उनको कितने दिनों के अंदर तमाम प्रक्रिया पूरा करके इसको आप लागू करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, रिपोर्ट आने के, मेरा प्रयास होगा कि तीन महीने के अंदर रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद सरकार अविलंब कार्रवाई करेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री युसुफ सलाहउद्दीन ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–317 (श्री युसुफ सलाहउद्दीन, सिमरी बख्तियारपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : अस्वीकारात्मक ।

वर्ष 2004 सितम्बर माह में अतिवृष्टि व कोसी बराज से अधिकतम जल निकासी होने के कारण बाढ़ की समस्या से सहरसा जिलांतर्गत सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के सिमरी बख्तियार, सलखुआ एवं महिषि प्रखंड के किसानों की खरीफ फसलों की क्षति हुई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में विभागीय निदेशानुसार ऑनलाईन पोर्टल पर प्रभावित कृषकों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर कृषि इनपुट अनुदान से संबंधित सभी आवेदनों का ससमय निष्पादन कर दिया गया था । उक्त अवधि में कृषि इनपुट अनुदान भुगतान हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं रहा है ।

सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के सिमरी बख्तियारपुर, सलखुआ एवं महिषि प्रखंड में कृषि इनपुट अनुदान वितरण की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

क्र0	प्रखंड का नाम	कुल आवेदन	लाभान्वित कृषकों	अंतरित राशि

			की संख्या	(रू0)
1.	सिमरी, बख्तियारपुर	3036	2733	2,64,47,930
2.	सलखुआ	8021	6972	5,87,15,615
3.	महिषि	9353	7649	5,90,35,773

ऑनलाईन आवेदन समय पर जमा नहीं कर पाने वाले वंचित कृषकों द्वारा इनपुट अनुदान हेतु कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है जिस कारण पुनः अनुदान संभव नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, हम पूरक पूछना चाहेंगे कि जो अन्नदाता किसान कृषि इनपुट अनुदान से वंचित रह गये थे जानकारी के अभाव में वैसे किसानों से ऑफलाईन आवेदन लेने हेतु विभाग द्वारा एक पत्र जारी हुआ था जो पत्र मेरे पास भी है परंतु इसके बावजूद सहरसा सहित अन्य जिलों में भी कृषि विभाग ने किसानों से आवेदन नहीं लिया और जवाब में कहा गया कि ऑफलाईन आवेदन पत्र कार्यालय को प्राप्त ही नहीं हुआ है जिस कारण अनुदान संभव नहीं है, तो क्या ऑफलाईन किसानों से आवेदन लेकर सरकार वंचित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, उत्तर खंड– अस्वीकारात्मक है ।

वर्ष 2004 सितम्बर माह में अतिवृष्टि व कोसी बराज से अधिकतम जल निकासी होने के कारण बाढ़ की समस्या से सहरसा जिलांतर्गत सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के सिमरी बख्तियारपुर, सलखुआ एवं महिषि प्रखंड के किसानों की खरीफ फसलों की क्षति हुई थी, जिसके...

..क्रमशः..

टर्न–5 / हेमन्त / 06.03.2025

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : (क्रमशः) परिप्रेक्ष्य में विभागीय निदेशानुसार ऑनलाईन पोर्टल पर प्रभावित कृषकों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर कृषि इनपुट अनुदान से संबंधित सभी आवेदनों का ससमय निष्पादन कर दिया गया था। उक्त अवधि में कृषि इनपुट अनुदान भुगतान हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं रहा है।

सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के सिमरी बख्तियारपुर, सलखुआ एवं महिषी प्रखंड में कृषि इनपुट अनुदान वितरण की स्थिति निम्न प्रकार है:–

क्र०	प्रखंड का नाम	कुल आवेदन	लाभान्वित कृषकों की संख्या	अंतरित राशि (रू०)
1	सिमरी बख्तियारपुर	3036	2733	2,64,47,930
2	सलखुआ	8021	6972	5,87,15,615
3	महिषी	9353	7649	5,90,35,773

ऑनलाईन आवेदन समय पर जमा नहीं कर पाने वाले वंचित कृषकों द्वारा इनपुट अनुदान हेतु कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, जिस कारण पुनः अनुदान संभव नहीं है।

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : जिन्होंने ऑनलाईन जमा किया उनका तो भुगतान हो गया है, लेकिन हमारे पास वह चिट्ठी भी है, 18 नवम्बर की चिट्ठी है जिसमें विभाग द्वारा यह लिखा गया था कि जिनका ऑनलाईन छूट गया है वह ऑफलाईन भी जमा कर सकता है ।

अध्यक्ष : कोई ऑफलाईन किया नहीं न, यह तो मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि जो छूट गये, जवाब में अंतिम पंक्ति देखिये आप यही कहा गया है कि अनुदान हेतु कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है । वह यही तो कह रहे हैं ।

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : विभाग कह रहा है कि ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया था ।

अध्यक्ष : विभाग यह नहीं कह रहा है, विभाग कह रहा है कि ऑनलाईन आवेदन समय पर जमा नहीं कर पाने वाले वंचित कृषकों द्वारा इनपुट अनुदान हेतु कोई ऑफलाईन आवेदन पत्र कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है । यानी कोई आवेदन ही नहीं आया, तो कैसे पेमेंट करेंगे । बैठ जाइये ।

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसा एक्स्टेंशन मिल सकता है, जिनका छूट गया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, दिखवा लेते हैं । यदि संभव होगा, तो निश्चित तौर पर सरकार विचार करेगी ।

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : धन्यवाद ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–318 (श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, कुचायकोट)</u>

(लिखित उत्तर)

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : प्रखंड पंचदेवरी अंतर्गत सिकटिया खास में पशु चिकित्सालय है। वर्तमान में प्रखंड–पंचदेवरी के सिकटिया खास में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, सिकटिया खास मुख्यालय में अन्य सरकारी भवन में संचालित है।

पशु चिकित्सालय, सिकटिया खास में पशु चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारी पदस्थापित हैं। पशु चिकित्सक द्वारा माह–अप्रैल 2024 से जनवरी–2025 तक कुल 3075 पशु चिकित्सा कार्य किया गया है।

उक्त पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक–891 (नि०), दिनांक 03.03.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध होने पर पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये पाण्डेय जी ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, पंचदेवरी प्रखण्ड के पशुपालकों को पशु चिकित्सालय नहीं होने से प्रखण्ड मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी तय कर जिला मुख्यालय इलाज कराने जाना पड़ता है । कभी–कभी तो साधन उपलब्ध नहीं होने से पशु घर पर ही मर जाते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पंचदेवरी में पशु चिकित्सालय हो जाने से पशुओं को काफी सुविधा मिलेगी, कब तक बनवाने की कृपा आप प्रदान करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रखंड पंचदेवरी अंतर्गत सिकटिया खास में पशु चिकित्सालय है। वर्तमान में प्रखंड–पंचदेवरी के सिकटिया खास में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, सिकटिया खास मुख्यालय में अन्य सरकारी भवन में संचालित है।

पशु चिकित्सालय, सिकटिया खास में पशु चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारी पदस्थापित हैं। पशु चिकित्सक द्वारा माह–अप्रैल 2024 से जनवरी–2025 तक कुल 3075 पशु चिकित्सा कार्य किया गया है।

उक्त पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक–891 (नि०), दिनांक 03.03.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। मैं माननीय सदस्य से भी कहना चाहूंगी कि अगर 140×120 फीट जमीन उपलब्ध करवा दें, तो निश्चित रूप से अगले वित्तीय वर्ष में इनका चिकित्सा भवन बन जायेगा और दूसरी बात है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि हर प्रखण्ड में हमारा चलंत पशु चिकित्सालय घूम रहा है । कोई भी 1962 पर

अगर फोन करता है, तो वह चिकित्सा उनके घर पर पहुंच जाती है, मेरा डॉक्टर जाता है और जाकर इलाज करके आ जाता है ।

माननीय विधायक जी से मेरा अनुरोध है कि हमने जो पत्र लिखा है डी0एम0 को जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में, आप उपलब्ध कराइये, अगले वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से चिकित्सालय बन जायेगा ।

अध्यक्ष : उपलब्ध कराने में मदद करिये, यह बोलिये मंत्री जी ।

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : जमीन उपलब्ध करवाने में मदद कीजिए ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, जमीन उपलब्ध हम कैसे करा सकते हैं, हम उसमें सहयोग कर सकते हैं ।

अध्यक्ष : मंत्री जी वही कह रही हैं ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : जहां तक माननीय मंत्री जी के द्वारा बताया गया कि सिकटिया में चलता है, तो इसको प्रखण्ड मुख्यालय में होने से काफी सुविधा मिलेगी, क्योंकि सबको जानकारी रहती है । यह प्रखण्ड मुख्यालय में होना चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में आप प्रखण्ड में ही पशु चिकित्सालय बनाने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : ठीक है । आग्रह उन्होंने सुना है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–319 (श्री अमर कुमार पासवान, बोचहां)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–320 (श्री विजय कुमार, शेखपुरा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत अरियरी प्रखंड में कुल 10 पंचायत है। जिसमें तीन पशु चिकित्सालय पूर्व से स्थापित हैं, यथा प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, अरियरी, प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, करकी एवं प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, ससबहना है। सबसे निकटम पशु चिकित्सालय, ससबहना से गाँव लटकाना की दूरी मात्र 2.5 कि0मी0 है एवं ग्राम–लटकाना में कुल पशु की संख्या लगभग–500 के आसपास है। विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार वर्तमान में ग्राम–लटकाना में नये पशु चिकित्सालय खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष : मुकेश जी, पूछिये आप ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत अरियरी प्रखंड के ऐफनी पंचायत के अधीन ग्राम लटकाना है, जहां पशु अस्पताल का निर्माण नहीं कराया गया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, एक मिनट सुन लिया जाय । जिस पंचायत में अस्पताल नहीं है वहां पर जमीन उपलब्ध है । माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वहां पर अस्पताल का निर्माण करायें ताकि पशुओं के चिकित्सा की व्यवस्था हो, तो वहां पर पूर्ण किया जाय।

अध्यक्ष : आपका आग्रह सुन लिया माननीय मंत्री जी ने ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, यहां पर जमीन उपलब्ध है..

अध्यक्ष : आपने पूछा ही नहीं न।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय,...

अध्यक्ष : महोदय नहीं । सुनिये न मेरी बात ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : मैं पूछता हूं महोदय ।

अध्यक्ष : हां, यह ठीक है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, यहां पर जमीन उपलब्ध है, तो क्या सरकार अस्पताल का निर्माण कराना चाहती है या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत अरियरी प्रखंड में कुल 10 पंचायत है। जिसमें तीन पशु चिकित्सालय पूर्व से स्थापित हैं, यथा प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, अरियरी, प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, करकी एवं प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, ससबहना है। सबसे निकटम पशु चिकित्सालय, ससबहना से गाँव लटकाना की दूरी मात्र 2.5 कि0मी0 है एवं ग्राम–लटकाना में कुल पशु की संख्या लगभग–500 के आसपास है। विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार वर्तमान में ग्राम–लटकाना में नये पशु चिकित्सालय खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, अगर वहां पर जमीन उपलब्ध है, निर्माण करा दिया जाता तो अच्छा रहता, चूंकि वहां पर काफी दूरी तय करके जिला मुख्यालय में जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए । विकास का मानक दो तरह का होता है क्या कि जो सत्ता पक्ष के माननीय विधायक हैं उनके लिए और है कि भूमि उपलब्ध करा दीजिए हम बना देंगे और क्या विपक्ष के लोग अगर सवाल उठायेंगे, तो उसके लिए अलग मानक है कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, किसी के लिए रूल अलग नहीं होता है । पूछते भी नहीं हैं, बैठ जाइये।

श्री मुकेश कुमार रौशन : यह सही नहीं है महोदय ।

अध्यक्ष : आप उठ ही नहीं रहे हैं, तो बैठिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या–321 (श्री अजय कुमार सिंह, जमालपुर, मुंगेर)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय सरावगी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि :–

1. बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा–05, 06 एवं 07 के प्रावधानों के तहत भूतपूर्व मध्यवर्ती एवं उनके भू–स्वामित्व के दावों के निराकरण के संबंध में प्रावधान किये गये है।

गैरमजरूआ मालिक एवं बकास्त भूमि पर रैयती दावों के निष्पादन के संबंध में विभागीय संकल्प सं0–925(6)/रा0, दिनांक–11.11.2014 के द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है, जिसके आधार पर रैयत के दावों/स्वामित्व का निष्पादन किया जाता है।

2. उपरोक्त में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

3. उपरोक्त में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

अध्यक्ष : अजय कुमार जी, पूरक पूछिये ।

श्री अजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अजय बाबू । आपको तो चार–साढ़े चार साल हो गया ।

(व्यवधान)

पूछना न चाहिए था। खाली कह रहे हैं आग्रह कर रहे हैं, आग्रह सुन लिया उन्होंने । खाली शोरगुल करने से नहीं होता है, प्रोसेस सीखना पड़ता है । बोलिये अजय बाबू ।

श्री अजय कुमार सिंह : मेरा यह कहना है माननीय राजस्व मंत्री जी से, मैंने सवाल उठाया है कि खतियान में अगर बकास्त या किसी रैयत का नाम नहीं है और खेवट में उस रैयत की हिस्सेदारी या खेवट उस बकास्त जमीन में उस रैयत के नाम को डिफाइन करता है, तो खेवट का महत्व क्या होगा, मैंने यह पूछा । लेकिन जवाब में आया है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 05, 06, 07 जिसका खेवट और खतियान से कोई मतलब नहीं है । गैरमजरूआ मालिक एवं बकास्त भूमि रैयतों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार का संकल्प है ।

अध्यक्ष : आप पूछना क्या चाहते हैं ?

श्री अजय कुमार सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि खतियान में बकास्त है, लेकिन खेवट में उस रैयत को काबिज कर लिया है, तो वह जमीन खेवट वाले रैयत की ही होगी । मैं यह राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो सकारात्मक है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है । खेवट दस्तावेज के संबंध में उन्होंने प्रश्न किया है, उन्होंने पूछा है कि बकास्त है उसे सरकार की जमीन मानी जाती है, सही में वह बकास्त सरकार की ही जमीन हुई । इनका यह प्रश्न है कि खेवट दस्तावेज में रैयत घोषित हो तो भूमि खेवट के अनुसार रैयत की होती है ।

(क्रमशः)

टर्न–6 / धिरेन्द्र / 06.03.2025

...क्रमशः...

श्री संजय सरावगी, मंत्री : महोदय, इस संबंध में विभाग का यह कहना है कि जहाँ तक वैसी भूमि जिसके खेवट दस्तावेज में रैयत का नाम घोषित हो वैसी भूमि को रैयती माने जाने का प्रश्न है तो उस भूमि के संबंध में है जब जमींदारी के अंतर्गत पड़ने वाले जमीनों का एवं रैयतों के लगान वसूली का विवरण जब दर्ज होता है तभी वह रैयत की मानी जायेगी । अध्यक्ष महोदय, उस समय जमींदारी था, जब जमींदारी खत्म हुई तो जो भूमि रह गई उसमें जमींदारों ने विवरणी दर्ज की, विवरणी दर्ज करने के बाद लगान वसूली होनी प्रारंभ हो गई, उसको खेवट कहा जाता है अगर लगान वसूली प्रारंभ हो गयी तो उस पर विभाग का दिशा–निर्देश भी है ।

श्री अजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को खेवट और खतियान दोनों की ठीक से जानकारी नहीं है । हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट का यह फैसला है कि अगर गलती से रैयत का नाम खतियान में छूट गया है

और खेवट में उसका नाम दर्ज है तो वह जमीन खेवट में दर्ज रैयत की होगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री अजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा–5, 6, 7 का कोई मतलब खेवट से नहीं है और गैर–मजरूआ मालिक और बकास भूमि में जो संकल्प है, यह जो बकास जमीन अगर मध्यवर्ती की रसीद कट गयी है तो मध्यवर्ती का जो वारिश है वह उसका रैयत होगा । मैं यह कह रहा हूँ कि खेवट में रैयत दर्ज है तो माननीय मंत्री जी आप खतियान और खेवट दोनों को समझने की कोशिश कीजिये और विभाग में इस पर निर्देश दीजिये ।

अध्यक्ष : बैठिये । माननीय मंत्री जी, मेरा आग्रह होगा कि एक बार माननीय सदस्य को विभाग में बुला लीजिये और वहाँ एक अधिकारी को भी बैठा दीजिये, ये जो रैयत और खेवट है हमको भी समझ में नहीं आ रहा है तो बैठा कर पूरे विषय को समझ लीजिये और समझ कर निदान करा दीजिये ।

(व्यवधान)

हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ठीक है ।

अध्यक्ष : इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा विषय ठीक से समझ लीजिये और उसका निदान करा दीजिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या–322 (श्री अखतरूल ईमान, अर्मार)

अध्यक्ष : श्री सुर्यकांत पासवान जी को प्राधिकृत किया गया है । आप पूरक पूछिये ।

श्री सुर्यकांत पासवान : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूर्णियां जिला अंतर्गत बैसा प्रखंड के रौटा पंचायत के वार्ड संख्या–04 में 125 घरों में जलापूर्ति की जा रही है । वार्ड संख्या–04 के शेष घरों में जलापूर्ति हेतु छूटे हुए टोला अंतर्गत एक नयी योजना का प्रावधान किया गया है जिसकी निविदा प्रक्रियाधीन है । निविदा निष्पादन उपरांत कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा ।

श्री सुर्यकांत पासवान : महोदय, मेरा प्रश्न है रौटा पंचायत के वार्ड न॰–04 में पेयजल की आपूर्ति पिछले 06 महीने से बाधित है तथा इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों के बार–बार शिकायत करने पर भी पेयजल की व्यवस्था नहीं की गयी है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, निश्चित रूप से । अगर कोई भी अधिकारी दोषी पाये जायेंगे इस प्रक्रिया को डीले करने में, उनपर सरकार कार्रवाई करेगी ।

श्री सुर्यकांत पासवान : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब क्या ? पूछने वाला भी दूसरा, जवाब देने वाला भी दूसरा। हो गया, माननीय सदस्य । अब श्री अवध विहारी बाबू को पूछने दीजिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या–323 (श्री अवध विहारी चौधरी, सिवान)

श्री जिवेश कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक।

सिवान जिला के सिवान सदर प्रखण्ड एवं नगर परिषद अन्तर्गत कुल 2679 अदद चापाकल है, बड़हरिया प्रखण्ड अन्तर्गत कुल 5026 अदद सभी चापाकल चालू स्थिति में है। वर्तमान में सभी प्रकार के चापाकलों की मरम्मति हेतु प्रमण्डलीय स्तर से संवेदक निर्धारित है । किसी भी बन्द पड़े चापाकल की सूचना मिलने पर उसको त्वरित कार्रवाई करके चालू करा लिया जाता है ।

सिवान सदर अन्तर्गत कुल नल जल योजनाओं की संख्या 245 है, जिसमें से 237 अदद कार्यरत है तथा 08 में विशेष मरम्मति का कार्य प्रगति पर है । प्रखण्ड बड़हरिया अंतर्गत कुल नल जल योजनाओं की संख्या 392 है । जिसमें 379 कार्यरत है तथा 13 में विशेष मरम्मति का कार्य प्रगति पर है । विशेष मरम्मति अंतर्गत नई बोरिंग, नई स्टेजिंग एवं स्टेजिंग की मरम्मति, नये वाटर टैंक, विद्युत पोल की आवश्यकता है एवं नये पाईप लाईन बिछाने एवं नये कनेक्शन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है । जिसे एक महीने के अन्दर पूर्ण करा दिया जाएगा ।

नगर परिषद सिवान में जलपूर्ति कार्य नगर परिषद सिवान के द्वारा किया जाता है । जिसके लिए इस कार्यालय के पत्रांक–464 दिनांक–05.03.2025 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित की जा रही है।

इस प्रकार सिवान सदर प्रखण्ड नगर परिषद सिवान एवं बड़हरिया प्रखण्ड में पेयजल की समस्या नहीं है।

श्री अवध विहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा मेरे प्रश्न का जवाब उपलब्ध कराया गया है और यह पेय जल से संबंधित मेरा प्रश्न है । जल ही जीवन है परन्तु नल का जल, प्यासों की प्यास बढ़ाने का काम कर रहा है, प्यास बुझाने का काम नहीं कर रहा है । महोदय, इसलिए मैंने प्रश्न दिया है कि पूर्व से आज तक जो भी चापाकल पंचायतों में लगाये गये हैं, उसमें से बहुत सारे चापाकल बंद पड़े हुए हैं । उन चापाकलों को अगर चालू करा दिया जाता है तो वहाँ पर्याप्त तरीके से जो पानी का अभाव है वह पूरा हो जायेगा, पेयजल संकट दूर हो जायेगी परन्तु जो मुझे विभाग के द्वारा रिपोर्ट दी गयी है, महोदय, मैंने स्वयं क्षेत्र में, गाँव में, पंचायतों में घूमने का काम किया है और मैंने देखा कि हर जगह....

अध्यक्ष : मैं भी घूमने का काम किया हूँ गाँव–गाँव ।

श्री अवध विहारी चौधरी : जी, महोदय । हर जगह लोगों ने कहा कि जो नल का जल है वह फंक्शनिंग नहीं है, कार्यरत नहीं है । चापाकल पहले से है इसको अगर चालू करा दिया जाय तो हमलोगों का पेयजल संकट दूर हो जायेगा परन्तु ऐसा न कर के जो मेरे प्रश्न का जवाब विभाग के द्वारा दिया गया है उसमें चापाकल के अदद का जो हमें रिपोर्ट दी गयी है, यह पूरा सर्वेक्षण कर नहीं दिया गया है और जो नल का जल के संबंध में है उसके बारे में भी मैं कहूँगा कि वह भी जो प्रतिवेदन है कि वह चालू है, हम इसको मानते नहीं कि यह सही रिपोर्ट है । इसलिए आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि आप जब माननीय मंत्री जी थे तो उस जमाने में भी, उस समय में भी सदन के द्वारा घोषित किया गया था कि माननीय विधायकों की अनुशंसा पर प्रत्येक पंचायत में पाँच–पाँच चापाकल लगाये जायेंगे परन्तु वे लगाये भी गये होंगे....

अध्यक्ष : लेकिन आपका प्रश्न तो चापाकल की मरम्मति पर है । आपका प्रश्न केवल चापाकल की मरम्मति पर है ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, वही तो मैं कह रहा हूँ । मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं दूसरा कुछ नहीं कह रहा हूँ ।

अध्यक्ष : यह बहुत दूर से चल के आ रहे हैं ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जो चापाकल की रिपोर्ट है 2669 अदद चापाकल है, यह गलत है और मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि सिवान प्रखंड में, मैं अपने ही क्षेत्र में जहाँ के लिए प्रश्न किया हूँ, सिवान प्रखंड में, बड़हरिया प्रखंड में बंद चापाकलों की संख्या क्या है या जो चापाकल लगे हुए हैं उसकी संख्या क्या है ? यह मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक बार फिर से जाँच करा दीजिये । माननीय सदस्य को लगता है कि रिपोर्ट में कुछ कमी रह गयी है । फिर एक बार जाँच करा दीजिये।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, ठीक है । माननीय सदस्य सीनियर हैं जैसा उनका आदेश होगा, सरकार करेगी ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, एक चीज.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गया । आपका जो आदेश था उसका मैंने पालन किया ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, आसन का जो आदेश है उसको मैं मानता हूँ । मैं कहना चाहता हूँ कि सिवान प्रखंड के एक जियाय में जलापूर्ति योजना बिल्कुल तैयार है लेकिन वह चालू आज तक नहीं हो सका है । जाँच करायेंगे तो उसको भी उसमें शामिल कर लीजियेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, दिखवा लेते हैं सब ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–324 (श्री पवन कुमार यादव, कहलगांव)</u>

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिला के कहलगाँव प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम प्रशस्तडीह में पशु चिकित्सालय ना होकर कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र अवस्थित था, जो वर्तमान में अक्रियाशील है ।

भागलपुर जिला के कहलगाँव प्रखंड अंतर्गत कुल 29 पंचायत है तथा 04 पशु चिकित्सालय क्रमशः कहलगाँव, मथुरापुर, धनौरा एवं अंतीचक पूर्व से संचालित है ।

गोराडीह प्रखण्ड में 15 पंचायत है एवं 02 पशु चिकित्सालय क्रमशः गोराडीह एवं नदियावाँ संचालित है। ग्राम प्रशस्तडीह से प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, नदियावाँ की दूरी मात्र 05 कि०मी० है जहाँ से ग्राम प्रशस्तडीह के सभी पशुओं का चिकित्सा कार्य किया जाता है।

सबौर प्रखण्ड में भी प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, सबौर पूर्व से संचालित है।

वर्तमान में ग्राम प्रशस्तडीह में पशु चिकित्सालय बनाने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है ।

उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

अध्यक्ष : पवन जी, पूरक पूछिये ।

श्री पवन कुमार यादव : आदरणीय माननीय अध्यक्ष महोदय, खुद पशुपालक होने के नाते पशु का दर्द समझते हैं.....

अध्यक्ष : क्या बोलें ?

श्री पवन कुमार यादव : महोदय, पूरक पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष : पवन जी, आपने पूर्व पशुपालक कहा ?

श्री पवन कुमार यादव : नहीं, महोदय । खुद पशुपालक कहे हैं । खुद पशुपालक होने के नाते पशु का दर्द समझते हैं । आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से आग्रह है कि कहलगाँव प्रखंड अंतर्गत ग्राम प्रशस्तडीह में पशु चिकित्सालय का निर्माण होने से कहलगाँव गोराडीह एवं सबौर प्रखंड के कई पंचायतों के पशु एवं पशुपालकों को काफी सुविधा होगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग । जवाब नहीं पढ़िये, केवल जितना पूछे हैं उतना ही बताइये ।

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिला के कहलगाँव प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम प्रशस्तडीह में पशु चिकित्सालय ना होकर कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र अवस्थित था, जो वर्तमान में अक्रियाशील है ।

भागलपुर जिला के कहलगाँव प्रखंड अंतर्गत कुल 29 पंचायत है तथा 04 पशु चिकित्सालय क्रमशः कहलगाँव, मथुरापुर, धनौरा एवं अंतीचक पूर्व से संचालित है ।

गोराडीह प्रखण्ड में 15 पंचायत है एवं 02 पशु चिकित्सालय क्रमशः गोराडीह एवं नदियावाँ संचालित है। ग्राम प्रशस्तडीह से प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, नदियावाँ की दूरी मात्र 05 कि०मी० है जहाँ से ग्राम प्रशस्तडीह के सभी पशुओं का चिकित्सा कार्य किया जाता है ।

सबौर प्रखण्ड में भी प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, सबौर पूर्व से संचालित है ।

वर्तमान में ग्राम प्रशस्तडीह में पशु चिकित्सालय बनाने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है ।

उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

टर्न–7 / संगीता / 06.03.2025

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उन्होंने पूरक नहीं पूछा है, उन्होंने केवल कहा है कि अगर यहां भी होगा तो अच्छा होता इसलिए उसका विचार करिए ।

अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायें । अब कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–06 मार्च, 2025 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:–

1. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, स0वि0स0, श्री अजीत कुमार सिंह, स0वि0स0, श्री अजय कुमार, स0वि0स0, श्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी, स0वि0स0, श्री सत्यदेव राम, स0वि0स0, श्री महबूब आलम, स0वि0स0, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स0वि0स0, श्री शमीम अहमद, स0वि0स0, श्री मुकेश कुमार यादव, स0वि0स0, श्री सउद आलम, स0वि0स0, श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0, श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0, श्री मुहम्मद अंजार नईमी, स0वि0स0 ।

2. श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0 ।

आज दिनांक– 06 मार्च, 2025 को सदन में वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक पर सामान्य विमर्श, सरकार का उत्तर तथा वित्तीय वर्ष 2024–2025 के आय–व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय–विवरण के उपस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–171 (1) नियम–176 (3) एवं नियम– 47 (2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

इतने लोग कैसे खड़े हो गये ? इतने लोग कैसे खड़े हो गए, बैठिए । कोई एक आदमी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप ?

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : महोदय, बिहार में नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू नहीं रहने के कारण बड़ी संख्या में यहां के लोग जो सरकारी नौकरियां–रिक्तियां निकल रही हैं उससे वंचित हो रहे हैं और अन्य...

अध्यक्ष : आप पढ़िए, पढ़ने के लिए खड़ा किए हैं, इधर–उधर कहां जा रहे हैं आप ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : जी धन्यवाद । अध्यक्ष महोदय, बिहार में नौकरियों में डोमिसाइल नीति नहीं होने से राज्य की बहालियों में राज्य के युवक–युवतियों को समुचित अवसर नहीं मिल पा रहा है । विदित हो कि बिहार में बेरोजगारी एवं पलायन चरम पर है और यहां इसकी दर देश भर में सभी राज्यों से अधिक है ।

अतः दिनांक–06.03.2025 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित करते हुए राज्य के लिए एक डोमिसाइल नीति बनाने पर विमर्श हो । जिससे कि बिहार के सभी प्रकार की नियुक्तियों में कम से कम 90 प्रतिशत बिहार राज्य के निवासियों की ही नियुक्ति हो सके ।

अध्यक्ष : श्री अजीत शर्मा ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आज के लिए सारे कार्यों को स्थगित कर राज्य में बेतहाशा बढ़ चुके प्रदूषण को नियंत्रित करने पर चर्चा हो । उल्लेखनीय है कि प्रदूषण मुक्त स्वच्छ वातावरण में जीना नागरिकों के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है परन्तु प्रदूषण के कारण बिहार के शहरों की स्थिति रहने लायक नहीं रह गई है । बिहार के प्रमुख शहरों का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 250 के लगभग बना हुआ है जो बहुत ही खराब की श्रेणी में आता है और जानलेवा है । बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद गठित है परन्तु निर्देश जारी करने के अलावा कोई काम नहीं करता है । प्रदूषण के मुख्य कारणों में निर्माण कार्य, बालू ढुलाई, कूड़ा–कचरा, मेडिकल कचरा आदि है । निर्माण कार्य और बालू ढुलाई बिना ढके और मानकों का पालन किए बिना हो रही है। इसी तरह से कूड़ा–कचरा, मेडिकल कचरा आदि के निष्पादन की कोई कारगर व्यवस्था नहीं है जिसके कारण राज्य के शहरों की हवा जहरीली हो गई है ।

अतः आज के लिए सूचीबद्ध सारे कार्यों को स्थगित कर राज्य में बेतहाशा बढ़ चुके प्रदूषण को नियंत्रित करने पर चर्चा करायी जाय ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे । श्रीमती भागीरथी देवी पढ़िए ।

<u>शून्यकाल</u>

श्रीमती भागीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष जी, बेतिया जिलान्तर्गत रामनगर विधान सभा की आबादी लगभग 4 लाख है, किन्तु एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है ।

मैं सरकार से मांग करती हूं कि जनहित में एक डिग्री कॉलेज खोला जाए।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर, दरभंगा, कटिहार सहित अन्य जिलों में यूरिया की किल्लत एवं कालाबाजारी से किसान त्राहिमाम हैं । किसान 450–500 रुपये महंगे दामों पर यूरिया खरीदने को मजबूर हैं, जबकि कीमत 266.50 रुपये है ।

मैं सरकार से पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराने व कालाबाजारी रोकने एवं दोषियों पर कार्रवाई की मांग करता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : रामबली जी क्या कह रहे हैं बोलिए, क्या कह रहे हैं । क्या सूचना है आपकी ?

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बड़ी दुखद खबर आयी है कि बिहारशरीफ के चंडी थाना में एक महिला को...

अध्यक्ष : सूचना क्या है बोलिए ।

श्री रामबली सिंह यादव : नौ कील ठोककर के मार दिया गया है महोदय...

अध्यक्ष : श्री मोहम्मद अंजार नईमी ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नईमी साहब, इन्होंने एक बात कही है, मौका दिया जाय सुनिए । मेरी बात सुनिए । 8 तारीख को महिला दिवस है, 8 तारीख को सदन नहीं चलने वाला है, शनिवार है इसीलिए महिला दिवस पर कल पहले महिलाओं के ही क्वेश्चन लिये जायेंगे । अब बोलिए नईमी साहब ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत निशन्द्रा–असूरा पुल का निर्माण स्वीकृत स्थान में ही बने उक्त स्थान के दोनों छोड़ में प्रधानमंत्री सड़क है । एक बड़ी आबादी का आवागमन इन्हीं घाटों से है । अन्य स्थान में पुल बनाना लोकहित में नहीं होगा तथा दो पक्षों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधामन प्रखंड के चिकनी से बाबुल टोला मजकुड़ी जाने वाली सड़क और कल्वर्ट बाढ़ से कई वर्ष पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया है । जिससे आमजनों को यातायात में परेशानी हो रही है।

अतः मैं सरकार से उक्त सड़क की मरम्मती और नए कल्वर्ट बनवाने की मांग करता हूं ।

श्री सउद आलम : माननीय अध्यक्ष जी, किशनगंज जिलांतर्गत दिघलबैंक प्रखंड के डाकुपारा, पलसा गांव को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु कॉल कनकइ नदी पर एवं आठगाछिया और करुआमनी पंचायत को आपस में जोड़ने हेतु गोरुमारा घाट पर उच्चस्तरीय आरसीसी पुल निर्माण की मांग सदन से करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, जीविका दीदि के रूप में कार्यरत कर्मी शौचालय सर्वे, स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण स्वच्छता, पेड़पौधा लगाने सहित विभिन्न कार्य करते हैं अस्तु संकुलस्तर पर काम करने वाले को 25000/– ग्राम संगठन पर 21000/– स्वयं सहायता समूह पर 20000/– रुपये मानदेय देने की मांग सरकार से करता हूं।

श्री इजहारूल हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र नहीं रहने के कारण आग लगने पर जिला मुख्यालय से सहायता आने तक काफी जानी व माली नुकसान हो चुका होता है । जिससे आमजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अतः मैं पोठिया प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र स्थापित करवाने की मांग करता हूं ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अन्तर्गत कहलगांव नगर के कागजी टोला से सैतपुरा कुलकुलिया तक गंगा नदी से हो रहे कटाव को

रोकने हेतु तटबंध/बोल्डर ठोकर आदि कटाव निरोधक कार्य कराए जाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत वर्ष 1972 में गठित सिकरहना अनुमंडल के चार प्रखंडों में मात्र एक डिग्री कॉलेज घोड़ासहन में है । जिस कारण छात्र/छात्राओं को व्यापक परेशानी होती है ।

सरकार शीघ्र अनुमंडल मुख्यालय ढाका में वित्तीय वर्ष 2025–26 में डिग्री कॉलेज की स्थापना करावे ।

टर्न–08/सुरज/06.03.2025

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज–2 के अंतर्गत बिहार राज्य के 8053 पंचायतों में कार्यरत स्वच्छता पर्यवेक्षकों एवं स्वच्छता कर्मियों का मानदेय ससमय नहीं होने से उनका परिवार भूखमरी के कगार पर है ।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि स्वच्छता कर्मियों के लंबित मानदेय का भुगतान शीघ्र करावें ।

श्रीमती निक्की हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, कटोरिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बौंसी प्रखंड के एफ0सी0आई0 गोदाम से ए0जी0एम0, बौंसी द्वारा अवैध रूप से अनाज बेचे जाने की शिकायत प्राप्त है । ए0जी0एम0 द्वारा डीलरों को आवंटित अनाज का वजन भी कम करके दिया जा रहा है ।

अतः संबंधित पदाधिकारी की जांच कराकर कार्रवाई की मांग करती हूं ।

श्री महानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, भारी संख्या में गरीब परिवार पक्का मकान योजना से वंचित हैं । गरीब परिवार का नाम सूचीबद्ध करने में काफी धांधली की जा रही है, गरीबों से रुपये वसूले जा रहे हैं । धांधली पर रोक लगाने एवं सभी गरीब परिवारों को पक्का मकान की गारंटी की मांग करता हूं ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, बिहार के प्रत्येक युवा को रोजगार की गारंटी करने और बेरोजगारों को 5000/– रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला के मोदनगंज प्रखंड अंतर्गत झुनकी मेला के पास पुलिस ओ0पी0 स्थापित करने की मांग करता हूं ।

श्री अनिल कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा बुजुर्ग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये कार्यान्वित की गयी ''मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना'' की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 से 2000 रुपये प्रतिमाह करने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड की आबादी पांच लाख से अधिक है, समुचित मात्रा में विद्युत पावर सब–स्टेशन नहीं रहने से किसानों के बोरिंग पर बिजली नहीं पहुंचने से खेती करने में कठिनाई होती है ।

अतः परिहार प्रखंड के नरंगा एवं बेला में पावर सब–स्टेशन लगाने की मांग सरकार से करती हूं ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, जमुई विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बरहट प्रखंड में बरियारपुर पंचायत के पतौना गांव में छात्रों और विशेषकर छात्राओं को पढ़ने के लिये काफी दूर स्थित उच्च विद्यालय जाना पड़ता है ।

अतः बरहट प्रखंड में बरियारपुर पंचायत के पतौना गांव में उच्च विद्यालय खोलने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूं ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत प्रखंड आमस के ग्राम पंचायत–रामपुर के ग्राम–नवगढ़ में जी0टी0 रोड से मिश्रबिगहा होते हुये पहाड़पुर रोड झरना आहर तक सड़क का निर्माण कराने की मांग करती हूं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, चम्पारण में सिकरहना, मुजफ्फरपुर में बागमती और कटिहार में महानंदा तटबंध का निर्माण हजारों गांवों को डूब क्षेत्र में बदल देने वाला है । तीनों जगह विनाशकारी बांध के निर्माण कार्य पर अविलंब रोक लगाने और विरोध करने वाले लोगों पर हुये मुकदमें की वापसी की मांग करता हूं ।

श्रीमती कविता देवी : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत फलका प्रखंड अंतर्गत रहटा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में चल रही है । जबकि तीन पंचायत के बीच लगभग 30 हजार आबादी के बीच यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है ।

अतः मैं उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन बनवाने की मांग करती हूं ।

श्रीमती निशा सिंह : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत आजमनगर प्रखंड के अरिहाना पंचायत में अस्पताल नहीं रहने के कारण स्थानीय लोगों को चिकित्सीय कार्य

हेतु काफी दूर जाना पड़ता है, जिसके कारण आमजनों में काफी रोष व्याप्त है ।

अतः मैं उक्त पंचायत में उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराने हेतु सरकार से मांग करती हूं ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज विधान सभा के एन0एच0 57 रेणु गेट से सिमराहा बाजार के पास रेलवे लाईन के दोनों तरफ चौतरफा गुजरने वाले सड़क मार्ग पर जाम की समस्या के निदान हेतु रेलवे ढाला पर रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण का प्रस्ताव रेल मंत्रालय भारत सरकार को भेजने की मांग सदन से करता हूं ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, हमारा नहीं आया है ।

अध्यक्ष : आपका राज्य सरकार की सीमा से बाहर का सूचना था इसलिये आप बैठ जाइये ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, बिहार शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग से कार्यरत डी0पी0एम0यू0, बी0पी0एम0यू0 कर्मियों की सेवा 31 मार्च 2025 को समाप्त कर दी जायेगी, जिससे इनके परिवारों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी । सेवा समाप्ति पर रोक लगाने तथा उनकी सेवा स्थाई करने की मांग करता हूं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य में लाखों दलित गरीबों का लंबे समय से बिजली का बिल बकाया है, जिसका भुगतान करने में वो सक्षम नहीं हैं ।

अतः सभी का बिजली बिल माफ करने व प्रति माह गरीबों को दो सौ यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग करता हूं ।

श्री मो0 इसराईल मंसूरी : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत एन0एच0 28 दामोदरपुर रेलवे गुमटी के पास एवं एन0एच0 57 दरभंगा रोड के शनि मंदिर के पास स्पीड ब्रेकर नहीं रहने के कारण काफी दुर्घटना होती है, जिससे काफी मौतें हो गयी है ।

अतः शून्यकाल के माध्यम से उक्त दोनों स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग करता हूं ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : अध्यक्ष महोदय, जमुई जिलान्तर्गत प्रखंड खैरा के पंचायत खैरा को जिसकी आबादी घनी है, उच्च माध्यमिक विद्यालय भी है, बाजार भी विस्तृत रूप ले लिया है ।

अतः खैरा पंचायत को नगर पंचायत बनाने की मांग करता हूं ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के उच्च विद्यालय प्रखंड के उच्च विद्यालयहीन नवादा एवं नया गांव पंचायतों में मध्य/प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित कर प्रति पंचायत एक–एक उच्च विद्यालय के निर्माण की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, रोसड़ा विधान सभा अंतर्गत शिवाजी नगर प्रखंड के जाखर धर्मपुर में क्रिकेट एवं फुटबॉल मैदान के लिये पर्याप्त जगह है । स्टेडियम बनाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, युवाओं में स्वास्थ्य एवं खेल के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिये मैं सरकार से भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखंड के इण्टरस्तरीय उच्च विद्यालय ईशीपुर तथा कहलगांव प्रखंड के इंटरस्तरीय उच्च विद्यालय रामपुर के क्रीड़ा मैदान में स्टेडियम निर्माण करवाने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जायेंगी ।

(सदन की सहमति हुई)

अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी ।

<u>ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य</u>

श्री पवन कुमार यादव, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार <u>(सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री पवन कुमार यादव । आपकी सूचना पढ़ी हुई है । माननीय मंत्री सहकारिता विभाग ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पैक्स प्रबंधक पैक्स के कर्मी हैं, जिनके वेतनादि के भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित पैक्स को है ।

उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य में सहकारी समितियां, बिहार विधान मंडल द्वारा पारित बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 एवं तद्नरूप गठित बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली, 1959 के तहत संचालित एवं विनयमित होती है ।

टर्न–9 / राहुल / 06.03.2025

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : (क्रमशः) पंचायत स्तर पर गठित प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी (पैक्स) बिहार सहकारी समितियां सोसाइटी, 1935 की धारा–11 के तहत निबंधित एक सहकारी समिति है । उक्त अधिनियम की धारा–44 'क,फ' एवं धारा–66 'ख' के आलोक में पैक्स को सभी वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामले (कार्मिक नीति, कर्मचारी की भर्ती, पदस्थापन, वेतनमान एवं मुआवजा) में स्वायत्ता प्रदत है । पैक्सों का कार्य संचालन निर्वाचित प्रबंध समिति द्वारा पैक्स के निबंधित उप विधि के अनुरूप किया जाता है । पैक्स कम्प्यूटरीकृत योजनांतर्गत पैक्सों की कार्य विविधता तथा तकनीकी आवश्यकताओं के कारण पैक्सों में कुशल एवं योग्य कर्मियों की नियुक्ति एवं उनके वेतन / मानदेय भुगतान करने में विभाग की भूमिका की संभावनाओं के अध्ययन के लिए कमिटी का गठन किया गया है । अन्य राज्यों में पैक्स कार्मिकों की नियुक्ति, उनके वेतन / मानदेय भुगतान हेतु लागू प्रावधान का अध्ययन कर राज्य अन्तर्गत पैक्स कार्मिकों हेतु वर्तमान प्रावधान के आलोक में विस्तृत प्रतिवेदन कमिटी द्वारा उपलब्ध कराया जाना है, कमिटी द्वारा इसका अध्ययन किया जा रहा है ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, कब तक रिपोर्ट आयेगी और पैक्स प्रबंधक का वेतन तय किया जाय । वे भुखमरी के कगार पर हैं और...

अध्यक्ष : बैठिये । पूछे हैं तो जवाब देने दीजिये न । माननीय मंत्री ।

डॉ0 प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, नंबर एक हमारी सरकार में कोई व्यक्ति बिहार में भुखमरी के कगार पर नहीं है, दूसरा जो इन्होंने कहा है तो सरकार विचार कर रही है, समिति की रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं । हम प्रयास करेंगे तीन महीने के अंदर में समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार निश्चित तौर यथोचित कार्रवाई करेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय मंत्री जी को धन्यवाद ।

श्री अजीत शर्मा, मो0 आफाक आलम एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (खेल विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा 'मेडल लाओ–नौकरी पाओ' योजना शुरू की गयी । इस योजना के तहत राजपत्रित पदों तक बहाली का प्रावधान है। बिहार की बेटी सुश्री मोनिका ने खो–खो वर्ल्ड कम, 2025 में गोल्ड मेडल जीता है । भारतीय खो–खो संघ द्वारा दिनांक–04.02.2025 को इसकी सूचना देते हुए महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को तथा माननीय मुख्यमंत्री बिहार को सुश्री मोनिका को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सरकारी नौकरी तथा अन्य देय सहायता दिये जाने का अनुरोध किया गया है । सुश्री मोनिका

का घर भागलुपर जिला में है, उनका परिवार अत्यंत गरीब है । उनके पास रहने के लिए ढंग का घर नहीं है । यहां तक कि उनके परिवार के पास गैस कनेक्शन भी नहीं है । अत्यंत ही गरीबी में जी रही सुश्री मोनिका को सहारा दिया जाना आवश्यक है, ताकि आगे आने वाले दिनों में वह इसी लगन से प्रदर्शन कर सकें।

अतः खो–खो वर्ल्ड कप, 2025 में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली बिहार की बेटी सुश्री मोनिका को सरकारी नौकरी सहित अन्य सहायता दिये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में ''मेडल लाओ–नौकरी पाओ'' योजना के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु ''बिहार उत्कृष्ट खिालाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023'' का गठन किया गया है जिसके नियम–3 में ओलंपिक गेम्स/एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल खेल विद्याओं में वैसे उत्कृष्ट खिलाड़ी की नियुक्ति का प्रावधान है जो ओलंपिक खेल/एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक प्राप्त किये हो या सहभागिता की हो या नेशनल गेम्स/सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप/ जुनियर नेशनल चैम्पियनशिप में स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक प्राप्त किये हो । उक्त खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति वेतनस्तर–1 (ग्रेड पे–1800), 2 (ग्रेड पे–1900), 6 (ग्रेड पे–4200), 7 (ग्रेड पे–4600), 9 (ग्रेड पे–5400) में की जा रही है तथा नियम–7(i) में वर्णित प्रावधानानुसार उक्त खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता/सहभागिता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों से आवेदन विहित प्रपत्र में प्राप्त कर आवेदनों की स्क्रूटनी कर सीधे तौर पर महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की अनुशंसा पर सीधी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत खिलाड़ियों की नियुक्ति की जानी है । चूंकि खो–खो खेल विद्या में ओलंपिक गेम्स/एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल खेल विद्याओं में शामिल नहीं है, फलस्वरूप खो–खो खेल विद्या के खिलाड़ियों की नियुक्ति विचारणीय नहीं है । चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल दिवस या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य दिवस पर खेल सम्मान योजना के तहत पुरस्कृत किया जायेगा ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, यह तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहां देखते हैं कि सारे लोग, सरकार बोलती है कि महिलाओं का सम्मान, बच्चियों के लिए और जो विश्वकप में गोल्ड मेडल लेकर आयी, आखिर भारत सरकार ने ही खेलने के लिए भेजा है, उस बच्ची को इसका लाभ क्यों नहीं मिलेगा ? इसलिए जो खेल मंत्री जवाब दिये हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं । तब तो आप नहीं चाहते हैं कि पूरे बिहार में बच्चियां और महिलाएं आगे बढ़ें । इसी बिहार की एक लड़की खो–खो के विश्वकप में हिस्सा ली है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि महिलाओं को नहीं देना है । माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि खो–खो इस योजना में शामिल नहीं है...

श्री अजीत शर्मा : क्यों नहीं है सर ? वह भी देश में खेला जा रहा है...

अध्यक्ष : क्यों नहीं है यह सवाल पूछ सकते हैं आप । यह महिलाओं की उपेक्षा की बात नहीं है ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से आग्रह है उसको इंक्लूड करें और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आग्रह करेंगे, वे हैं नहीं । इसको इंक्लूड करके इनको नौकरी देने का काम कीजिये । बिहार की जनता इसको देख रही है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

सर्वश्री अजय कुमार, समीर कुमार महासेठ एवं अन्य पांच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (पंचायती राज विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : श्री अजय कुमार जी अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज–2 ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक–ग्रा0 15/2020–36सी, दिनांक–20.12.2021 के आलोक में सभी 8061 ग्राम पंचायत से स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन किया गया है । बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक–1353664, दिनांक–08.11.2022 के द्वारा स्वच्छता पर्यवेक्षक को संविदा के आधार पर नियोजित किया गया है । मुख्य सचिव, बिहार के विभागीय पत्रांक–24/प0स0म0, 9–10/2022/8728/प0स0, दिनांक 09.09.2022 के आलोक में स्वच्छता पर्यवेक्षक (ग्रामीण विकास विभाग) को पंचायत सरकार भवन/पंचायत भवन से काम करने का निर्देश होने के बावजूद स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी सुबह से शाम तक प्रत्येक दिन घर–घर से कचरा का उठाव, कचरे को डब्लू0पी0यू0 सेंटर पर ले जाना और अलग–अलग करवाना एवं स्वच्छता शुल्क भी संग्रह करते हैं जिसके बदले में स्वच्छता पर्यवेक्षक को मात्र 5000 से 7500 रुपये एवं स्वच्छता कर्मी को 1500 से 3000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है जो सरकार के न्यूनतम मजदूरी दर से भी काफी कम है जबकि पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत पत्र 6पं0/रा0/अ0–14/2019/325/पं0सं0, दिनांक–15.10.2021 के आलोक में सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय प्रतिमाह 20,000/– रुपये है । अतः स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी को उचित मानदेय देने एवं सेवा स्थायी करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री सूर्यकांत पासवान : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : बैठिये, क्यों खड़े हो रहे हैं सूर्यकांत जी । बैठिये न । बोलने तो दीजिये, आप तो बोलते ही रहते हैं । अब शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जायेंगी । श्री सूर्यकांत पासवान जी ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : मैंने आपको कहा न आपकी सूचना चूंकि राज्य की सीमा के बाहर का विषय था इसलिए उसको अमान्य किया जाता है । श्री सूर्यकांत पासवान जी, बोलिये ।

श्री सूर्यकांत पासवान : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिलांतर्गत बखरी प्रखंड में थाना बाजार से बाहर होने से अपराधिक घटनाओं को रोकने में नाकाम है, कई व्यापारियों की दुकान का दरवाजा काटकर चोरी हो चुकी है । अतः बखरी बाजार में एक सहायक थाना स्थापित करने की मांग सरकार से करता हूं ।

टर्न–10 / मुकुल / 06.03.2025

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा थाना अन्तर्गत एरका गाँव निवासी जमींदार पासवान के 12 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार का 23.02.2025 को अपहरण हुआ । दिनांक–26.02.2025 को उसकी लाश मिली । मैं सरकार से इस काण्ड में पुलिस की लापरवाही की जांच एवं दोषियों पर कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखंड के फरही पंचायत वार्ड संख्या–5 स्थित शिवधर यादव घाट से कुशीयैत टोला होते भंगही नहर क्वार्टर पुल तक पक्कीकरण सड़क निर्माण की माँग सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : महोदय, वैशाली जिला के अपने विधान सभा क्षेत्र के तीनों प्रखंडों राजापाकर, देसरी और सहदेई बुजुर्ग में भूमिहीन एवं आवासविहीन महादलितों को बासगीत पर्चा उपलब्ध कर जमीन पर कब्जा दिलाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की मॉग सरकार से करती हूं ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज के कर्मी लगातार पन्द्रह वर्षों से पठन–पाठन कराने के साथ–साथ सरकारी अन्य सभी कार्यों को करते आ रहे हैं। इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा, सम्बंधित विद्यालयों में समायोजन तथा अनुकम्पा का लाभ प्राप्त हो । सदन से इसकी मांग करता हूं ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : महोदय, रोहतास जिला के सासाराम में बेदा से लेकर एस०पी०जैन कॉलेज तक 03 कि०मी० जी०टी० रोड पर आए दिन जाम लगा

रहता है, जिस कारण शहरवासी को काफी कठिनाई होती है । सरकार से बेदा से लेकर एस०पी०जैन कॉलेज तक फ्लाईओभर निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री शमीम अहमद : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के जल संसाधन विभाग कार्य प्रमण्डल रक्सौल के अधीन छौड़ादानो प्रखंड के छौड़ादानो प्रखंड चौक से स्टेशन की तरफ जाने वाली सड़क में जी०बी०सी० कैनाल के ऊपर पुल जर्जर अवस्था में है, उक्त पुल कभी भी ध्वस्त हो सकती है । आमजनों के हित में उक्त कैनाल पर नया पुल निर्माण की माँग करता हूं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मधुबनी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अपराध पर नियंत्रण हेतु रामपट्टी के पास तथा कोतवाली चौक के आगे रेलवे क्रॉसिंग के बाद दो ओ०पी० खोले जाने की माँग करता हूं ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, 65 प्रतिशत आरक्षण के प्रति इस सदन की प्रतिबद्धता है सदन ने इससे संबंधित कानून बनाकर ऐतिहासिक काम किया है । अगर मुख्यमंत्री अपने द्वारा लिए निर्णय के प्रति ईमानदार हैं तो विधानसभा का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिलने की गारंटी करें । संसद में पास कराकर इसे 9वीं अनुसूची में डालें ।

श्री शिव प्रकाश रंजन : महोदय, शिक्षा विभाग में ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाई (बी0पी0एम0यू0) और जिला प्रबंधन इकाई (डी0पी0एम0यू0) कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के निर्णय के विरूद्ध तत्काल हस्तक्षेप एवं नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करता हूं ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, मखदुमपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत जमनगंज, भैरव डकरा, मकरपुर पंचायत में पेयजल संकट दूर करने हेतु फल्गु नदी से पानी लिफ्ट कराकर पंचायतों में पहुंचाने की सदन से मांग करता हूं ।

श्रीमती नीतू कुमारी : महोदय, नवादा जिला के मेरे विधान सभा क्षेत्र के तीनों प्रखण्डों हिसुआ, नरहट और अकबरपुर में हल्का कर्मचारियों द्वारा जमीन की दाखिल–खारिज परिमार्जन और जमाबंदी में अवैध रिश्वत की मांग पूरी नहीं होने पर गरीब जनता का कार्य बाधित होने की निगरानी जाँच एवं कार्रवाई की मांग सरकार से करती हूं।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत प्रखण्ड रतनीफरीदपुर के पंचायत नारायणपुर के बौद्ध स्थल घेजन में बलदईया नदी पर वर्षों पहले पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । अभीतक सम्पर्क पथ का निर्माण नहीं होने के कारण ग्रामीणों को लगभग 15 कि०मी० घूमकर बौद्ध स्थल घेजन जाना पड़ता है। अतः सम्पर्क पथ निर्माण की माँग करता हूं ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, कन्या मध्य विद्यालय सबलपुर, खगड़िया जमीन का खाता–627, खेसरा–1388, जमाबंदी–23, रकवा एवं बीघा चौदह कट्ठा सत्रह धुर पर अनधिकृत तरीका से अन्य विभाग द्वारा निर्माण कार्य नियमानुकूल नहीं है । अतः जिलाधिकारी खगड़िया विद्यालय जमीन पर निर्माण कार्य रोक लगाने हेतु निर्देश देने की मांग करता हूं ।

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, दरभंगा जिला के केवटी प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम रनवे पुरानी टोल एवं केवटी के बीच से ग्राम समैला के दिधिफिल्ड होते हुए समैला रतन यादव की दुकान तक कच्ची सड़क का पक्का निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के पूर्वी केबिन और पश्चिम केबिन पर रेलवे क्रॉसिंग के पास आर0ओ0बी0 बनाने की मांग सरकार से करता हूं।

श्री महबूब आलम : महोदय, सरकारी नौकरियों और अन्य सरकारी अवसरों में डोमिसाइल नीति लागू करने से बिहार के स्थानीय लोगों को राज्य के भीतर ही काम का अधिकार और रोजगार के अवसरों का लाभ मिल सकेगा । अतः मैं बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–11 / यानपति / 06.03.2025

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष–2025–26 के आय–व्ययक पर दिनांक–05 मार्च, 2025 से जारी सामान्य विमर्श अब प्रारंभ होगा । माननीय सदस्य श्री भूदेव चौधरी, अपना पक्ष रखिए । आपका समय 18 मिनट है ।

श्री भूदेव चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझको बजट पर विरोधी दल की तरफ से बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, इस लोकतंत्र के मंदिर के दीवारों पर एक बहुत ही अच्छे शब्द का उल्लेख किया गया है कि संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार के ही अंग माने जाते हैं । मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे और सभी माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि मेरी बात से अगर कहीं किसी को कोई कष्ट हो तो उसे नजरअंदाज कर देंगे । जब लोकतंत्र की चर्चा होती है......

अध्यक्ष : ऐसी बात क्यों बोलते हैं कि नजरअंदाज करने के लिए आग्रह करना पड़े ? ऐसी बात बोलिए जो सब ग्राह्य कर लें । बोलिए ।

श्री भूदेव चौधरी : मेरी कोशिश होगी कि मैं अदब के साथ ही आपके साथ पेश आऊं । जब लोकतंत्र की चर्चा होती है महोदय तो कुछ अतीत काल की भी याद आने लगती है । यह देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ लेकिन आजादी के पहले यह देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के चंगुल में था । इस देश की तकदीर और मुकद्दर का फैसला करने वाला इस देश में नहीं बैठता था बल्कि विदेशों में, लंदन में, ब्रिटेन में, अमेरिका में और वहीं से इस देश की तकदीर और मुकद्दर का फैसला करता था । आपको और सबको मालूम है, मैं उस अतीत की ओर ध्यान नहीं ले जाना चाहता हूं लेकिन यह बात सही है कि आजादी दिलाने के क्रम में कई जवान साथियों के खून बहे हैं । इस देश को आजाद करने में 7–7 लाख नौजवानों के लाल–लाल खून बहे हैं । कितनों के मां की गोद खाली हो गई कितनों के भाई–भाई से बिछड़ गए और कई कांड तो ऐसे हैं जिसको देखने से, सुनने से ही सिहरन पैदा हो जाती है । चाहे वह 13 अप्रैल, 1919 की घटना हो, जालियांवाला बाग की घटना हो या 25 अप्रैल, 1925 का काकोरी कांड हो या फिर 1928 की वह लाहौर की धरती हो जहां साइमन कमीशन वापस जाओ और अंग्रेजी हुकूमत की लाठियों से हंसराज और लाला लाजपत राय की मौत हुई थी । 1947 में मेरा देश आजाद हुआ और 1952 में लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा को अक्षुण्ण रखने का हिंदुस्तानियों ने कसम खाया । इस लोकतंत्र के मंदिर में जब पहुंचते हैं तो सबों के मुखारबिंद से इसकी मर्यादा, इसका आदर्श, इसका सम्मान अक्षुण्ण रखने का संकल्प लेते हैं, कसमें खाते हैं । मैं विगत दिनों से देख रहा हूं, आप तो मुझको जानते हैं, मैं 25 वर्ष पहले पहली दफा इस लोकतंत्र के मंदिर में आया था । कई साथियों को तो मैं देख रहा हूं, कई साथी गुजर गए हैं, वह हैं नहीं लेकिन मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं कि इस देश को चलाने के लिए संकल्प लिया गया । पता नहीं इस मंदिर में पहुंचने के बाद उस संकल्प को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं । बजट प्रस्तुत हुआ है, हर साल बजट प्रस्तुत होता है और जब बजट प्रस्तुत होता है तो सत्ता पक्ष के सम्मानित सदस्यों ने थपथपाहट के साथ उस बजट का स्वागत किया है । मैंने भी बजट को ध्यान से पढ़ा है महोदय लेकिन जब ध्यान से पढ़ने के बाद मैं निष्कर्ष पर पहुंचा तो मुझको लगा कि जब सत्र प्रारंभ होता है और बजट की चर्चा होती है तो जो 14 करोड़ बिहार की आबादी है उसकी नजर इसपर पड़ती है । वह बहुत ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ और बहुत गंभीरता से इस बजट को सुनना चाहता है । नतीजा निकलने के बाद बड़ी ही निराशा हाथ लगी है । इस बजट में सिर्फ और सिर्फ जो पुराने बजट की व्याख्या पूर्व में की गई थी उसी को थोड़ा सा सजा दिया गया

है । पहले 2 लाख 52 हजार के आसपास बजट था इस बार 36 हजार बजट बढ़ाया गया है और इसी में सत्ता पक्ष के लोग निश्चित तौर पर बहुत खुश हैं, खुश होना भी चाहिए लेकिन जिन लोगों के लिए बजट की भूमिका होती है, जिसके हित में यह बजट प्रस्तुत होता है वह लोग निराश हैं । यहां बजट की किसी भी पंक्ति में बेरोजगारी दूर करने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है । भुखमरी, लाचारी, बेबसी इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया । आप को मालूम है इस बिहार की स्थिति क्या है । सब लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा बीमार अगर कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम है बिहार । आपको मालूम है आजादी के दिनों में, 1917 में जब पूज्य बापू महात्मा गांधी देश के दौरे पर निकले और सभी जगह से वह वापस आए और अपने गुरू गोखले के सामने जब उपस्थित हुए तो गोखले ने उनसे कहा कि कहो गांधी देश का क्या हालचाल । निकले थे वह कि आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी लेकिन देश में चारों तरफ घूमने के बाद वह निराश होकर अपने गुरू गोखले से मिले । गोखले ने उनसे पूछा कि देश में तो आपने सभी शहरों का दौरा किया बताओ कहां के लोगों ने तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे हौसले को बढ़ाया । वह निराश हो गए, चुप हो गए उन्होंने कहा देश में तो मैं घूमा लेकिन कहीं के लोग इस ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसकी ताकत अपरंपार है, दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर सत्ता ब्रिटिश के हाथ में, कहा जाता है कि उनके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था । अगर हिन्दुस्तान में सूरज डूबता था तो सऊदी में उगता था, सऊदी में डूबता था तो अफ्रीका में उगता था । यानी इतनी मजबूत ताकत, इतनी मजबूत सत्ता के विरोध में हिन्दुस्तान का कोई भी हिम्मत नहीं करता था । जब गुरू गोखले ने उनसे बिहार के विषय में कहा तो कहा कि मैं बिहार नहीं गया हूं, कहे जाओ बिहार और बिहार की धरती पर पूज्य बापू महात्मा गांधी आए तो यहां के लोगों ने उनको इतना साहस दिया, इतना भरोसा दिया कि उनकी हिम्मत ताजा हो गई और उन्होंने गुरू गोखले से जाकर कहा कि बिहार ही इस देश में ऐसी ताकत, ऐसी मिट्टी में ऊर्जा है वहां के नौजवनों में, इतना साहस है । उसके कंधे को जब मैंने सहलाया तो उसके अंदर यह अनुभूति जगी और मैं कह सकता हूं कि अब जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं जा सकती है बल्कि जीती भी जा सकती है, इसी मिट्टी की ताकत ने उनको जान दी । लेकिन बिहार की स्थिति क्या है, आज भी बिहार की स्थिति बद से बदतर है । आज गांव में जाइये जहां मैं जाता हूं, जीवन में दो चीज बहुत ही जरूरी है वह है शिक्षा और स्वास्थ्य । शिक्षा की स्थिति क्या है, हां मंजिलें बनी हैं, भवनें बनी हैं, टेबल कुर्सी लगा है, समरसेबुल गड़ा है, खाने में अच्छी व्यवस्था है लेकिन जिस हेतु हम खाना देते हैं, मध्याह्न भोजन चलाते हैं, टेबल कुर्सी की व्यवस्था करते हैं, किताब की व्यवस्था करते हैं, पोशाक की व्यवस्था करते हैं उस हेतु में

हमें सफलता नहीं मिल रही है । जो भी अफसर जाते हैं स्कूल, जो भी पदाधिकारी जाते हैं वह पढ़ाई की बात नहीं करते हैं, वह पूछते हैं आज खाना में क्या बना था, आज मध्याह्न भोजन में क्या खाया । मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है चीफ सेक्रेट्री एजुकेशन विभाग के एस0 सिद्धार्थ जी आजकल ऑनलाइन ही शिक्षकों से बात करते हैं । मुझको लगा कि हां कुछ फायदे होंगे लेकिन आपलोगों को पता है कि चीफ सेक्रेट्री साहब, प्रिंसिपल सेक्रेट्री साहब जब बात करते हैं शिक्षक से तो पूछते हैं, पढ़ाई के विषय में नहीं पूछते, किसी बच्चे से हालचाल नहीं पूछते, वह पूछते हैं शिक्षक से कि मध्याह्न भोजन में आज क्या बना । वह बताता है कि मध्याह्न भोजन में क्या बना ।

(क्रमशः)

टर्न–12 / अंजली / 06.03.2025

(क्रमशः)

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हालत यह हो गई है कि अब माँ–बाप उठते हैं और माँ–बाप पूछते हैं कि आज तुम स्कूल गया था, अगर वह बोलता है कि हाँ मम्मी मैं स्कूल गया था तो उससे यह नहीं पूछता है कि पढ़ाई हुई कि नहीं हुई, उसको पूछता है कि आज भोजन में क्या बना ? यानी वह विद्यालय भोजनालय में परिणत हो गया क्या जीवन में होगा ? आज गांव में जाइए, आपको 83 प्रतिशत युवा बेरोजगार है । जानकर आपको दुख भी होगा कि इस देश में, इस बिहार में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, बैंगलोर, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बंगाल और असम का नौजवान नहीं दिखता है । कहीं नहीं दिखता है, न तो खेतों में, न खलिहानों में, न दुकानों में, न होटलों में, कहीं नहीं दिखता है । लेकिन क्या वजह है कि आज भी इस बिहार का 2 करोड़ 50 लाख नौजवानों से अधिक जिनके हाथों में काम करने की भी ताकत है, क्षमता है, वह बूढ़ी माँ को छोड़कर, बूढ़े बाप को छोड़कर, बिलखते पत्नी को छोड़कर, बिलखते बच्चे, अबोध बच्चों को छोड़कर बिहार के बाहर दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में । अभी हाल की बात है मेरे क्षेत्र में एक आवेदन आया, आज ही आया है । महोदय, वह मेरे धोरैया प्रखंड के कुमारडीह गांव का है, स्वतंत्रता सेनानी उनके पिताजी थे, वह मर गए, मौत हो गया, नतीजा हुआ कि दिल्ली कमाने के लिए वे अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ दिल्ली गया । जिस दिन दिल्ली में वह ट्रेन से उतरा, उसी दिन ट्रेन के हादसे का शिकार हो गया ।

अध्यक्ष : 4 मिनट ही आपका समय बचा है ।

श्री भूदेव चौधरी : उनकी पत्नी और दो बच्चियां वहीं मर गईं, मौत हो गई, वह दरवाजे पर दस्तक दिए, बिहार सरकार से उन्होंने आरजू विनती की, केंद्र के रेलवे मिनिस्टर से मिला लेकिन आज तक उनको कोई सहायता राशि नहीं मिली है, यह स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार का हश्र है । बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, यह कहने में मुझकों कोई संकोच नहीं है । मैं गांव में रहता हूं और सुदूर क्षेत्रों में रहता हूं, आज सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं किसी ऑफिस में रहती है तो वह अंचलाधिकारी के ऑफिस में रहती है, सी0ओ0 के ऑफिस में रहती है । वहां का नजारा यह है कि आपने जो भूमि सर्वेक्षण का मसला उठाया है, किसान, मजदूर वहां जाता है, वह सही खतियान देता है, सही केवाला देता है, लेकिन उसके बाद भी परिमार्जन के नाम से जो डाटा ऑपरेटर बैठता है, जो कर्मचारी बैठता है, वह झूठा उसको लिख देता है, कहीं 381 है तो 382 लिख देता है, कहीं 38 खाता नंबर है तो 83 लिख देता है, नतीजा होता है कि बेचारा वह 4 दिन, 5 दिन दौड़ते रहता है और उसको तब सुकून मिलता है जब बाहर में रहने वाले जो निजी लोग हैं, जो प्राइवेट, जिसको हम ब्रोकर कहते हैं, अगर उनसे वह संबंध स्थापित करता है तो पैसे का लेन–देन होता है और तीन हजार से पांच हजार रुपए जब उस ऑफिस के दलालों को मिलता है तभी उसका काम होता है । मैं आपसे और आपके माध्यम से सरकार के मंत्रियों से भी आरजू विनती करना चाहूंगा कि इसकी जांच कराएं, आप शिविर लगाएं, पंचायतों में शिविर लगाएं और वहां उसकी जांच कराएं । गरीब, किसान, मजदूर जो मेहनतकश है, जो 300 रुपया, 400 रुपए वह दिन में किसी तरह अर्जित करता है, कमाता है लेकिन वहां चार हजार, पांच हजार रुपए देने को मजबूर हो जाता है । उसी तरह से गरीब लाचार है बिजली के चलते, एक किसान लाचार है बिजली के चलते, आप कहते हैं बिजलियां तो गांव–गांव पहुंच गईं, आप कहते हैं कि किसानों को मात्र 70 पैसे यूनिट में बिजली देते हैं लेकिन आप किसानों को देखे हैं, चार घंटे बिजली किसानों के लिए मिलता है और वह भी दिन भर में चार घंटा । कभी दो घंटा चला, कभी एक घंटा चला और फिर वह चार घंटे के बाद बिजली जाएगी, नतीजा यह हुआ कि वह फसल उगा नहीं सकता है, उसके फसल उग नहीं सकते हैं, अपेक्षित नहीं उग सकते हैं ।

अभी बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री भाई सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज का निर्माण करेंगे । धन्यवाद देता हूं आपको कि आप डिग्री कॉलेज जरूर खोलिए क्योंकि शिक्षा की बहुत जरूरत है । राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर गरीबी से निजात पाना चाहते हो, भुखमरी से मुक्ति पाना चाहते हो तो उसका एक ही इलाज है, एक ही हथियार है उस हथियार का नाम है शिक्षा । लेकिन मैं कहना चाहता हूं वित्तमंत्री जी को कि

वित्तमंत्री जी करीब–करीब ब्लॉकों में आइसोलेटेड कॉलेज है, आप पता लगाइए, हमारे धोरैया में भी दो कॉलेज है । एक धोरैया में, एक रजौन में...

अध्यक्ष : भूदेव जी, आप बढ़िया बोल रहे हैं लेकिन दो ही मिनट आपके पास है, क्योंकि आपकी पार्टी ने जो समय दिया है वह दो मिनट में समाप्त हो जाने वाला है । जो समय है उसी हिसाब से बोलिए ।

श्री भूदेव चौधरी : मैं बोल रहा हूं, वही बता रहा हूं । मुझको मालूम है कि समय कम है लेकिन महत्वपूर्ण समय है । मैं वित्तमंत्री को कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि वहां डिग्री कॉलेज बने, उसके सभी मकान अच्छे बने हुए हैं, तीन मंजिला मकान बना हुआ है, जमीन भी पर्याप्त है, खेल का भी मैदान है, शिक्षक भी वहां हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कम खर्चे में वह डिग्री कॉलेज बन जा सकता है । इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है, अनुरोध है कि अगर आप डिग्री कॉलेज खोलना चाहते हैं तो आप पता लगाएं कि किन प्रखंडों में आइसोलेटेड कॉलेज लंबे दिनों से चल रहा है, अगर वह संसाधन से पूरी तरह से पूर्ण है तो क्यों नहीं उसको अधिग्रहण करके आप डिग्री कॉलेज की शुरुआत कर सकते हैं ।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं स्वास्थ्य विभाग की बात, स्वास्थ्य विभाग में भी स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत ताल ठोककर बोलते हैं कि अब तो कोई कमी नहीं हैं, मैं धोरैया में रहता हूं, वहां डॉक्टरों का अभाव है, आप कहते हैं एक्स–रे हैं, मैं मानता हूं कि एक्स–रे है, पैथोलॉजी है, एम0आर0आई0 की मशीन है लेकिन उसको चलाने वाला कोई विशेषज्ञ नहीं है । छोटी–छोटी भी बीमारी होती है तो सीधे–सीधे ठेस लगने पर भी वह कह देता है कि जाओ भागलपुर में इलाज कराओ । वहां कोई ऑपरेटर नहीं है । कौन ऑपरेटर की बहाली करेगा ? यह सही बात है, 17 महीने जब श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी यहां डिप्टी सी0एम0 रहें और स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी उनको मिली तो हर पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन बन गया, बना भवन लेकिन डॉक्टर नहीं है, कोई ए0एन0एम0 वहां नहीं है । मैंने कई जगह देखा है मनिहाट में, हसाई में, श्रीपाथर में इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर स्वास्थ्य विभाग सही तरीके से इस बजट का उपयोग करना चाहता है तो इन तमाम बातों पर ध्यान दीजिए ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री भूदेव चौधरी : महोदय, आज भी इस राज्य में 68 प्रतिशत ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भवती के समय में खून की कमी की वजह से उनके बच्चे जितने वजन का पैदा होना चाहिए वह नहीं हो रहा है । आज भी 78 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं।

अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, भूदेव जी ।

श्री भूदेव चौधरी : मैं अधिक आपका समय नहीं लेना चाहता हूं शिक्षा के विषय में भी यही कहना चाहता हूं कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो मिडिल स्कूल हैं जिनको आपने भवन दिया है, क्रीड़ा स्थल उसमें चयन कीजिए । वहां खेल की महत्ता को बढ़ाइए । चहारदीवारी का निर्माण कराइए, सबमर्सिबल है, आपने टेबल–कुर्सी दिया है, आप जरा जांच करके देख लीजिए जो बाजारों में 500 में मिलता है वह 5000 का बिल बना हुआ है ।

अध्यक्ष : भूदेव जी समाप्त कीजिए । श्री राणा रणधीर ।

श्री भूदेव चौधरी : महोदय, बस एक मिनट । एक छोटा–सा शेर सुनाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : मैं क्या करूं, आपकी पार्टी ने 18 मिनट ही आपको दिया है ।

श्री भूदेव चौधरी : मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं, आप तो सुनते हैं ।

''जिसका गुमां नहीं था, वही बात हो गई,

यह शहर, शहर न रही, रात हो गई,

अच्छे दिन तो इस शहर में आए नहीं,

मगर एन0डी0ए0 के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई ।''

महोदय, आपने मुझको समय दिया है उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री राणा रणधीर । आपका समय 10 मिनट है ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, मैं दस मिनट में ही समाप्त करूंगा, अवसर देने के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद । मैं अपने सदन नेता, हमलोग के नेता यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, अपने उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी के प्रति, अपने सचेतकों के प्रति और सबसे ज्यादा मधुबन की महान जनता के प्रति जिसके आशीर्वाद के बदौलत आज मैं यहां खड़ा हूं और बजट के आय–व्ययक विमर्श पर अपना मंतव्य रख रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि चर्चा शेर से शुरू हुई है तो मैं शेर से ही शुरू करता हूं –

''कहते हैं कि मंजिले और लक्ष्य बड़े जिद्दी होते हैं,

हासिल कहां नसीब से होते हैं,

और वहां तुफां भी हार जाते हैं,

जहां कस्तियां जिद्द पर होती हैं ।''

अध्यक्ष महोदय, बिहार की सरकार ने और नीतीश कुमार की सरकार ने जहां से शुरुआत की थी, मैं और हम सब बड़े उम्मीद में थे कि नेता प्रतिपक्ष जो एकाध बार तो पूरे बजट सत्र से भी गायब रहें, इस बार बजट पर अपना विचार रखेंगे, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार रखेंगे तो कुछ बढ़ियां विषय, अच्छा विषय हमलोगों को मिलेगा लेकिन कुछ चर्चा उन्होंने की है, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं 2005 से चर्चा शुरू करता हूं, आय–व्ययक पर विमर्श है इसलिए शुरू करता हूं और चर्चा इसलिए शुरू करता हूं कि 2005–06 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर वह निगेटिव थी, –1.69 प्रतिशत थी।

(क्रमशः)

टर्न–13 / पुलकित / 06.03.2025

(क्रमशः)

श्री राणा रणधीर : जो अर्थव्यवस्था की गिरावट का प्रतीक था, नीतीश कुमार जी की सरकार ने, एन0डी0ए0 की सरकार ने वहां से शुरूआत की और बिहार के हालात कैसे थे ? जैसे बिहार ठहरा हुआ प्रदेश हो, जैसे गुमनामी अंधेरा और बिहार में जीवन कैसा था ? जीवन मानों कि वहां जीवन और दुर्गती दोनों साथ–साथ चलती थी और वहां से शुरू करके 2006–07 में बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 16.18 प्रतिशत हुई । उसके बाद 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2011–12 और फिर 2018–19 एवं 2019–20 में बिहार की आर्थिक दर की वृद्धि जो हैं, अभी एन0डी0ए0 की सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को जो हमलोगों के नेता हैं, आदर्श हैं, भारत रत्न देने का भी काम किया और इसी सदन में कर्पूरी ठाकुर जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां भी मैं दोहराना चाहता हूं । कर्पूरी जी ने एक बार कहा था कि –

बहुत दिन चला हूँ, किनारे–किनारे,
अब जी चाहता है कि मौजों से खेलूं ।
मौजें, तूफां मेरी लाज रखना,
भले साहिल ने ठुकराया है मुझे ।।

जहां से बिहार ने शुरू किया था, उसी बिहार ने अपने राज्य की आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रीय वृद्धि दर से ज्यादा कर ली और फिर 2019–20 में राज्य की वृद्धि दर 10.5 प्रतिशत रही । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने यह बात रखना चाहता

हूं कि जो वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक थी और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि–

''हौंसला बुलंद हो तो सफलता चलकर आती है ।
समुद्र राह देखता है, चट्टाने थरथराती है ।।''

कोविड का दौर पूरी दुनिया के लिए और देश के लिए गंभीर दौर था । उस कोविड–19 के समय उत्पन्न त्रासदी में भी 2020–21 में जब भारत सरकार की आर्थिक वृद्धि दर निगेटिव हो गयी थी, नकारात्मक थी, फिर भी बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एन0डी0ए0 के नेतृत्व में बिहार राज्य की वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत रही । अध्यक्ष महोदय, यह बिहार की आर्थिक वृद्धि दर के बारे में संभावित चालक क्या कहते हैं, देश के जो बड़े अर्थशास्त्री हैं श्री अरविन्द विरमानी अपने लेख में कहते हैं, एक किताब उन्होंने लिखी कि बिहार ग्रॉथ लर्निंग फॉर एक्पीरियेन्स । वे बिहार की आर्थिक वृद्धि को तेज करने वाले सेक्टर आधारित चालकों की ओर ध्यान दिलाते हैं और विरमानी साहब ने कहा है कि दो अवधि की तुलना करते हुए 1993–94 से लेकर 2004–05 तक जब देश की सालाना आर्थिक वृद्धि औसतन 6.8 प्रतिशत थी तथा 2004–05 से लेकर, यह दो खंडों में है 2011–12 तक देश की सालाना आर्थिक वृद्धि 8.3 फीसदी थी । पहली वाली मियाद में बिहार की औसत वृद्धि सालाना 5.3 फीसदी थी और बाद वाली मियाद में अभूतपूर्व ढंग से सालाना 11.7 फीसदी पर पहुंच गयी । दूसरी मियाद में आर्थिक वृद्धि दर पहले की वृद्धि दर से दोगुनी से भी ज्यादा हो गयी । विरमानी कहते हैं कि यह वृद्धि दर जो राष्ट्रीय औसत से महज 80 प्रतिशत थी, बढ़कर राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर से 1.7 गुना हो गयी और इस तरह बिहार की बाकी दुनिया के बराबरी में आने के सिलसिले की शुरूआत हुई । मैं आज याद करना चाहता हूँ अपने नेता स्वर्गीय सुशील मोदी जी को जिन्होंने 30 हजार, जब 2005 में वित्त मंत्री के रूप में यहां कमान संभाली थी, उप मुख्यमंत्री बने, वित्त मंत्री बने तो 23 हजार करोड़ के बजट को नीतीश कुमार जी के साथ में मार्गदर्शन में उन्होंने 2 लाख 23 हजार करोड़ तक करने का काम स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने किया था और उस गति को आगे बढ़ाते हुए बिहार की सरकार, हमारे उपमुख्यमंत्री जी के नेतृत्व इस बार 3 लाख 16 हजार करोड़ रूपये का बजट आया है । अध्यक्ष महोदय, यह बिहार की सरकार है जो कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है । यह चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए जानी जाती है । यह नये विजन के साथ काम करने वाली सरकार है और इस सरकार ने तय किया है । मैं तो चम्पारण की धरती से आता हूं, गांधी बाबा की धरती से आता हूँ, जहां गांधी बाबा ने 100 साल पहले, हम चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष भी मनाये, पंडित

राजकुमार शुक्ल की धरती रही है और चम्पारण की धरती ने ही मोहनदास कर्मचन्द गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी और उन्होंने कहा था शिक्षा पर बात चलती है, स्वास्थ्य पर बात चलती है तो आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा पर, शिक्षा का बजट हमारे बजट में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा को दिया है ।

अध्यक्ष : केवल तीन मिनट आपके पास शेष है ।

श्री राणा रणधीर : महोदय, तीन मिनट है । मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर दूँगा । कृषि के मामले में कहते हैं कि क्या हुआ ? सोच देखिये, अध्यक्ष महोदय, जब हम समस्या पर बात करते हैं तो हमें बहाने मिलते हैं । अभी हमारे नेता विरोधी दल ने चर्चा की 1960 से 1991 तक की राजनीतिक अस्थिरता की बात की, समस्याओं पर चर्चा की लेकिन यह नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है जो समाधान पर बात करती हैं। जब आप समस्या पर बात करते हैं तो आपको बहाने मिलते हैं । आप समाधान पर बात करते हैं तो आपको रास्ते मिलते हैं और कैसे मुख्यमंत्री ने वह रास्ता तय किया अध्यक्ष महोदय, वह मैं कहना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र में जो विकास हुआ वह कृषि रोड मैप के माध्यम से हुआ । हम सब मानते हैं और इसमें विश्वास करते हैं कि–

''तेरे शहर का पेट, मेरे गांव की मिट्टी से पलता है ।
गौरतलब रहे कि देश अपना गांव में बसता है ।।''

महोदय, कृषि रोड मैप बनाकर किस तरह से अभी बिहार को पांच–पांच, बिहार को पांच कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं, कृषि मैप के विचार से कैसे इतनी बड़ी चीजें खड़ी हो सकती है, उसका प्रमाण है कि बिहार राज्य खाद्यान्न के क्षेत्र में, ईख में, अंडा में, मछली उत्पादन में, मीट में, फलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई । दुग्ध उत्पादन में 57.67 मीट्रिक टन से बढ़कर 120 मीट्रिक टन हमारा आज दुग्ध का उत्पादन है । बिहार राज्य को पांच कृषि कर्मण पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं ।

महोदय, पथ की चर्चा करते हैं क्योंकि विकास के रास्ते में हमारे भारत रत्न प्रधानमंत्री श्री अटल विहारी वाजपेयी जी का जो विजन था और आज जिस विजन के बदौलत न केवल हम फोर लेन सड़कें हमारे पूरे बिहार में दिखती है बल्कि गांव में पी0एम0जी0एस0वाई0 वाली सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कितना बड़ा काम हुआ है और कैसे हमारे वर्ष 2005 में आपको बता देता हूं यह जानना चाहिए ग्रामीण पथों की लम्बाई के बारे में ग्रामीण कार्य मंत्री ने कहा था कि वर्ष 2005 में ग्रामीण पथों की लम्बाई जो

केवल 3,112 किलोमीटर थी और आज नीतीश कुमार जी और एन0डी0ए0 सरकार के नेतृत्व में ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क 1,17,000 किलोमीटर हो गयी है । महोदय, आर0सी0डी0 के बारे में बता दूं, आर0सी0डी0 का मंत्रालय आपने भी संभाला है और आपके कुशल नेतृत्व में भी क्या हुआ वह भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि वर्ष 2005 से लेकर अबतक पथ निर्माण विभाग ने 81,992 किलोमीटर सड़क तथा करीब–करीब 7 हजार पुलों का निर्माण कराया है । यह जब कोई सरकार और विचार के साथ काम करती है और कैसे आप विचार के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम सब इसमें विश्वास करते हैं कि जीवन जो हैं वह आसान नहीं होता ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री राणा रणधीर : जी । जीवन को आसान बनाना पड़ता है और कभी भी कोई समय उत्तम नहीं होता, हम सबको मिलकर उत्तम समय बनाना पड़ता है । महोदय, डबल इंजन की सरकार ने बिहार के समय को उत्तम बनाने का काम किया है, बिहार के लोगों के समय को उत्तम बनाने का काम किया है । मैं अंत में अध्यक्ष महोदय, आपने अवसर दिया मैं आपको धन्यवाद देता हूं और चंद पंक्तियां पढ़कर अपनी वाणी पर विराम दूंगा कि यह बिहार जो हैं यह कैसे 2047 तक विकसित भी बनेगा और आत्मनिर्भर भी बनेगा और क्यों बनेगा ? कहते हैं कि –

''विकसित होकर रहेगा अपना बिहार, विकसित होकर रहेगा अपना बिहार।
क्योंकि मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व करता है नीतीश कुमार ।।''

बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री विनय कुमार चौधरी, आपका समय दस मिनट हैं ।

श्री विनय कुमार चौधरी : सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं अपने मुख्य सचेतक आदरणीय श्रवण बाबू के प्रति भी मैं सम्मान व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पार्टी की ओर से मुझे बोलने का मौका दिया । महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में कहा था कि पढ़कर के आने के लिए, इसलिए मैं आज पढ़कर आया हूँ । महोदय, उन्होंने जो पुस्तकें दी थीं थैंक्स टू गॉड, कि उन्होंने उस समय में उनके माता–पिता जी के शासन काल में एक लालू चालिसा छपी थी । यह हमलोगों को पढ़ने के लिए नहीं कहे हैं, इसके लिए धन्यवाद भगवान को भी देते हैं और उनको भी कहते हैं कि कम से कम उन्होंने उसको पढ़ने के लिए दिया । आप किसी अर्थशास्त्री का

पुस्तक पढ़कर आते और तब आकर बताते । आपको तो पढ़ने–लिखने से कभी वास्ता नहीं रहा ।

(क्रमशः)

टर्न–14 / अभिनीत / 06.03.2025

..क्रमशः..

श्री विनय कुमार चौधरी : आप मौलिक पुस्तक कोई समझे नहीं । अर्थशास्त्री की पुस्तक अगर पढ़कर आते बजट पर और उनका जो पत्र रहता, उनका जो आर्टिकल रहता उस पर अगर आप कहते हमलोगों को पढ़ने के लिए तो अच्छा लगता, तो दिक्कत है कि इन्होंने तो पढ़ा नहीं, पढ़ाई–लिखाई से इनको वास्ता नहीं रहा..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए । बैठिए, अपनी बात समय पर रखिएगा । आपकी पार्टी को मौका मिलेगा । बैठिए ।

श्री विनय कुमार चौधरी : और ये हमको कहते हैं पढ़ने के लिए । आप आइये, मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी हूं आपको आकर पढ़ाउंगा ।

अब मैं बजट पर आना चाहता हूं । मैं अपने उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के प्रति आभार प्रकट रता हूं कि उन्होंने बजट, जो कभी एक जमाने में बिहार का बजट 2004–05 में 23 हजार करोड़ के लगभग था आज उन्होंने बढ़कार 03 लाख 17 हजार करोड़ तक कर दिया इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं और यह बताता है, इतना ही नहीं पिछले वित्तीय वर्ष से भी उन्होंने 38 हजार 169 करोड़ रुपये से ज्यादा का बनाया है । यह परिलक्षित करता है कि बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एन0डी0ए0 बिहार को कहां ले जा रहा है और किसी जमाने में जब 23 हजार करोड़ रुपये का आप बजट बनाते थे तब का बिहार कैसा होता था, यह समझने की बात है । जहां एक ओर वर्तमान सम्राट चौधरी वित्त मंत्री ने राजस्व बजट 2024–25 में 1121.41 करोड़ से बढ़ाकर अपने बजट बचत को वर्ष 2025–26 में 8831.18 करोड़ रुपये किया है, वहीं दूसरी ओर राजकीय कोष उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित राजकीय कोष घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद 3 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर रखा गया है, यह बहुत ही स्वागतयोग्य है । महोदय, इस पर इन्होंने हंगामा नहीं किया क्योंकि यह तो बचत क्या होता

है, सकल अनुपात क्या होता है यह ये लोग समझते ही नहीं है । इस पर इनको हंगामा करना चाहिए, तो दिक्कत यह है, ये हमको पढ़ने के लिए कहते हैं । पढ़ाई और बजट इन लोगों को समझने की जरूरत है । अगर आप कहेंगे तो मैं इनको ट्यूशन दे दूंगा । इसी तरह इस बार बजट में उन्होंने शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करने का प्रावधान किया है । 7946.87 करोड़ रुपये के व्यय के लिए । महोदय, एक बात बता देता हूं कि उन्होंने, तेजस्वी यादव भी अपने भाषण में दशमलव के बदले प्वायंट कहते हैं, हद हाल है, बात है पढ़ाई से मतलब नहीं है । दशमलव बोलिए प्वायंट क्यों बोलते हैं । यह हाल तो इनके नेता का है, तो इनका क्या हाल होगा यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है ।...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपनी बात कहिए ।

श्री विनय कुमार चौधरी : स्वास्थ्य पर इस बार भी उन्होंने, सरकार ने 20035.80 रुपये का व्यय करने का प्रावधान किया है । यह तो उनके भाषण में है, यह हमारे कहने, नहीं कहने से क्या होगा । उन्होंने प्वायंट कहा था कि नहीं कहा था, यह आप भी देख लीजिएगा और आपके नेता..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे–बैठे जो लोग टीका–टिप्पणी कर रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, अपनी बात कहिए ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि शिक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने राज्य के सभी प्रखंडों और अनुमंडलों में अंगीभूत राजकीय डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है । यह बतलाता है कि हमारी सरकार, नीतीश बाबू के नेतृत्व वाली सरकार किस तरह से अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देने के लिए सोच रखती है । कृपया करके उसके लिए तो धन्यवाद दीजिए । आपलोग बराबर मांग कर देते हैं कि हमारे प्रखंड में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है और डिग्री कॉलेज खोलने की इन्होंने घोषणा की है और आप कहते हैं कि, हमको लगता है कि इन्होंने 2004–05 में जो अभिभाषण था उसको पढ़–लिख कर आये थे और कहे थे कि उसी अनुरूप इस बार भी है, तो बजट में उन्होंने हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए जो घोषणा की है, यह बहुत ही स्वागत योग्य है । इतना ही नहीं पढ़ाई के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने एक से दस तक के सामान्य श्रेणी के छात्रों को, अल्पसंख्यक भी है उसमें, आपलोग भर दिन कहते रहते हैं, उस दिन कह दिए कि घेराबंदी के लिए, भाई कब्रिस्तान की घेराबंदी किसने की ? आप कहते हैं कि मरम्मती की योजना नहीं, अरे घेराबंदी तो हमने ही किया । हमको तो याद है सब, महोदय, आप जब दरभंगा जाते थे तो उस समय मैं पत्रकार था और आपके समाचार को मैं बड़ी प्रमुखता से लिखता था । उस समय में मैं जब लिखता था तो एक

भी घेराबंदी के लिए, ये लोग बड़े—बड़े 15 साल तक जब इनके नेता सब कई हुए, उस समय में तो सब यही जीतते थे, एक भी अपने क्षेत्र में कब्रिस्तान की घेराबंदी ये लोग नहीं कराते थे और उस रोज पॉलिटिकल माइलेज के लिए कूदने लगें । कूद—कूद कर, हमारे ललित बाबू भी नहीं है कूद रहे थे उनसे मैं पूछता कि आप दरभंगा में..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन में कोई कूदता नहीं है अपनी बात कहता है । आप भी अपनी बात कहिए ।

श्री विनय कुमार चौधरी : कूद—कूद करके कहने लगें कि सरकार घेराबंदी के लिए कोई काम नहीं कर रही है, योजना नहीं बना रही है, तो यह मैं अभी बताता । छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक छात्रों के लिए भी, सामान्य वर्गों के लिए दोगुना कर दी गयी है, यह समझने की जरूरत है । इतना ही नहीं प्री—मैट्रिक की जो छात्रवृत्ति योजना की बात इन्होंने अभी की है, जो राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही है इसके तहत मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति को दोगुना कर दिया गया है । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच है कि जबतक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जबतक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक सही ढंग से समाज का विकास नहीं होगा । इसके लिए उन्होंने प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया है इसके लिए मैं सम्राट चौधरी का भी आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं । इसी तरह अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी के छात्रों के लिए आवासन के लिए 14 आवासीय विद्यालयों को खोला जा रहा है जिसमें अब 720 आवासन की व्यवस्था होगी । राज्य के प्रत्येक पंचायत में यह भी एक योजना बहुत ही अच्छी योजना चली है क्योंकि अभी वर्तमान में देखा जाता है कि गरीब कन्याओं के विवाह के समय में बच्चियों के अभिभावक को जगह नहीं मिलती है इसके लिए अभी सरकार ने कन्याओं के विवाह के लिए कन्या विवाह मंडल की स्थापना की जो घोषणा की है, यह बहुत ही स्वागयोग्य है ।..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब दो ही मिनट समय आपके पास बचा है ।

श्री विनय कुमार चौधरी : बस—बस महोदय, इसी तरह कहते हैं कि किसान के लिए कुछ नहीं किया । पढ़ाई तो करते नहीं हैं, जरा सम्राट जी का अभिभाषण तो पढ़ लीजिए । राज्य के कृषि उत्पादन बाजार प्रांगनों में आधुनीकीकरण के लिए जो उनहोंने 01 हजार 279 करोड़ रुपये की लागत का प्रावधान किया है यह बहुत ही स्वागतयोग्य है । बड़ी नदियों को जोड़कर जो नई योजनाओं, पुल बनाने की जो योजना चलायी जा रही है यह भी बहुत ही स्वागतयोग्य है और जिला मुख्यालयों को प्रदेश के मुख्यालय से चार लेन सड़क से जोड़ा जायेगा । जरा ताली तो बजा लीजिए, यह भी एक बहुत ही अच्छी योजना की शुरूआत की

जा रही है जिससे आवागमन की सुविधा हो जायेगी । अभी वर्तमान में, महोदय, आप भी पी0डब्लू0डी0 मिनिस्टर थे, जब आप ज्वाईन किये होइयेगा तब 2000 से पहले मात्र चार पुल गंगा पर थे आज बढ़कर 2005 के बाद 14 हो गये हैं । सुन लीजिए फिर से 14 हो गये हैं । कोसी पर मात्र 02 पुल थे बढ़कर अभी वर्तमान में 09 हो गये हैं और गंडक पर 03 पुल थे जो बढ़कर 08 हो गये हैं जिसमें दो फोर लेन का है । बागमती पर 04 थे जो अब बढ़कर 13 हो गये हैं । फलगु पर 01 था जो अब बढ़कर 04 हो गये हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, छोटी–मोटी नदियों पर तो पुल की गिनती ही नहीं है । संभव ही नहीं था हजारों पुल हो गये हैं । ये लोग कहते रहते हैं, अरे भईया धन्यवाद तो दीजिए मुख्यमंत्री जी को..

अध्यक्ष : आप समाप्त करिए न ।

श्री विनय कुमार चौधरी : तुरंत सर । उसके बाद राज्य के किसानों के लिए, राज्य के सभी अनुमंडलों में, सभी प्रखंड मुख्यालयों में कोल्ड स्टोरेज की जो स्थापना हुई है यह किसानों के लिए मिल का पत्थर साबित होगा । आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद और श्रवण बाबू के प्रति आभार कि उन्होंने मुझे मौका दिया ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सूर्यकांत पासवान । आपका समय केवल दो मिनट है ।

श्री सूर्यकांत पासवान : अध्यक्ष महोदय, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जबकि सरकार द्वारा यह एक चुनावी बजट पेश किया गया है । महोदय, देखा जाय तो बजट के आकार में सिर्फ वृद्धि हुई है लेकिन बढ़ती महंगाई और ऊंची मुद्रास्फीति दर से प्रतीत होता है कि यह बजट 2005 से भी पीछे है । किसानों द्वारा की जा रही खेती घाटे में जा रही है । उत्पादन हो रहा है, लेकिन उसके लिए रख–रखाव का साधन नहीं है । महोदय, बाजार का अभाव है ।

.... क्रमशः ....

टर्न–15 / हेमन्त / 06.03.2025

श्री सुर्यकांत पासवान : (क्रमशः) : किसानों के लिए उर्वरक की बढ़ती कीमत और कालाबाजारी चरम पर है । सिंचाई हेतु बिजली का कनेक्शन दिया गया, लेकिन तारपोल खेतों तक नहीं पहुंचा है । महोदय, किसानों का महंगा बिजली बिल आ रहा है, लेकिन सिंचाई कार्य नहीं हो पा रहा है । हरी सब्जी के रख–रखाव के लिए छोटे–छोटे कोल्डस्टोरेज की व्यवस्था नहीं है । महोदय,

बिहार के बजट में आशा, आंगनबाड़ी, रसोइया, सेविका, सहायिका, ममता, स्वच्छताकर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक को न्यूनतम मजदूरी की बात बजट में नहीं की गयी है । जीविका दीदी सारे सरकारी कार्यों को करती है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी तो दूर, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है । महोदय, आज पदाधिकारियों के द्वारा उनको अपमानित किया जा रहा है । आज आशा दीदी का भी वही हाल है । महोदय, चर्चा हमारे माननीय सदस्य कर रहे थे डिग्री कॉलेज की । डिग्री कॉलेज बनाने के लिए सरकार बजट में लायी है, लेकिन पिछले दो साल से हमारे विधान सभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज बन रहा है, लेकिन उसके एक फ्लोर का काम भी नहीं हो पाया है, इतनी धीमी गति से वह काम हो रहा है । हमारे अनुमंडल में अनुमंडल अस्पताल की घोषणा हुई ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री सुर्यकांत पासवान : महोदय, लेकिन अभी तक अनुमंडल अस्पताल नहीं बन रहा है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले सत्र में कहा था कि सारी प्रक्रिया हो गयी है अब आपके यहां बनने जा रहा है, लेकिन इस साल भी अता–पता नहीं है ।

अध्यक्ष : श्री भारत भूषण मंडल । आपके पास दस मिनट का समय है ।

श्री भारत भूषण मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी के यशस्वी नेता प्रतिपक्ष द्वारा समय निर्धारित किये जाने को लेकर उनके साथ–साथ आपको भी धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष जी, इस सदन को सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार मिसलीड किया जाता है । जो आंकड़ें, जो जानकारी सदस्यों को दी जाती है वह तथ्यपरक नहीं होती हैं । अभी मैं एक आंकड़े की बात आपसे करना चाहता हूं । लालू यादव जी के कार्यकाल के बारे में लगातार बताया जाता है कि उनका कार्यकाल बेहतर नहीं था । वह लोगों के जीवन में बदलाव लाने को लेकर समर्पित नहीं था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं लालू यादव का कार्यकाल पिछड़ों, दलितों, गरीबों, अतिपिछड़े, अक्लियतों का स्वर्णकाल था । उस जमाने में यह मैं दावे से बताता हूं लालू यादव जी का जब आगमन हुआ बिहार की राजनीति पर, राजनैतिक पटल पर, सत्ता पर, तो आपको मालूम होगा कि सामाजिक शक्तियों की जो ताकत था उसमें जबरदस्त विस्फोट हुआ । इस तरह का बदलाव हुआ कि जर्रा–जर्रा, जो बहुजन समाज के लोग थे उसमें एक आशातीत बदलाव हुआ । ऐसा बदलाव जिसकी कल्पना आज तक किसी मुल्क ने नहीं की थी । लालू यादव असाधारण प्रतिभा का नाम था । अभी मैं उनके बारे में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और ध्यान से सुनिये । स्वामीनाथन एंक्लेश्वर अय्यर ने लिखा है लालू यादव के कार्यकाल पर कि लालू यादव के समय में लालू यादव को जब सत्ता मिली थी उस समय में राज्य का खजाना खाली था

। चीजें बहुत अव्यवस्थित थी, लेकिन लालू यादव के आने के बाद बहुत तेजी से राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ और 1994–95 में जो बिहार का ग्रोथ रेट था, वह बहुत तेजी से बढ़ा । 11 दशमलव कुछ प्रतिशत और उसके बारे में देखिये, इस बात को समझने का प्रयास करिये कि जो स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर ने कहा है, बिहार का ग्रोथ मिरेकल, कहा कि लालू बीट्स नेहरू । यह देखिये, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जो स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर थे उन्होंने लालू यादव के कार्यकाल के बारे में लिखा कि जिस तेजी से बिहार में आर्थिक प्रगति प्रारंभ हुई लालू यादव के कुशल नेतृत्व में उसकी तुलना में उन्होंने कहा कि नेहरू से बेहतर काम किया । अंग्रेजी में उन्होंने लिखा कि लालू बीट्स नेहरू । इसलिए हम बताना चाहते हैं कि लालू यादव के कार्यकाल में जिस तेजी से सर्वांगीण विकास बिहार के 90 फीसदी आवाम का हुआ उसके बाद बिहार का कायाकल्प शुरू हो गया । पढ़ाई के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, बदलाव के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में पिछड़े, दलित, अक्लियतों ने अभूतपूर्व विकास किया ।

(इस अवसर माननीय सभापति महोदया श्रीमती ज्योति देवी ने आसन ग्रहण किया)

बिहार के बैंकों में लालू यादव के कार्यकाल में बहुत तेजी से पैसे जमा होने लगे । लगा कि बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है । यह नेतृत्व के कौशल का परिणाम था । नेतृत्व के सर्वांगीण विकास की समर्पित नीतियों का प्रभाव था और फिर मैं आपको कहना चाहता हूं । राबड़ी जी का कार्यकाल, जो 1990 से 2005 के बारे में, नीतीश कुमार जी के जो जीवनी लेखक हैं, अरूण सिन्हा ने अपनी किताब ''द नीतीश एंड द राईज ऑफ बिहार'' में उद्धृत किया है कि 2004 से 2005 के बीच में बिहार की ग्रोथ रेट लालू यादव के कार्यकाल से भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा । इसीलिए हम बताना चाहते हैं कि यह सच है जिसका खुलासा नीतीश कुमार जी के जीवनी लेखक अरूण कुमार सिन्हा ने भी बताया है । इसीलिए हम बताना चाहते हैं कि राबड़ी जी का कार्यकाल हो, लालू यादव का कार्यकाल हो वह पिछड़े, दलित, गरीबों का, जिसे भाजपा के लोग जंगलराज कहते हैं, वह पिछड़ों का स्वर्णकाल था । इसको इस रूप में जानने का प्रयास कीजिए । इसी दौरान मैं यह बताना चाहता हूं कि हॉर्वर्ड की पढ़ी हुईं चिराश्री ने भी, जो हॉवर्ड स्कूल में पढ़ी, उन्होंने एक किताब लिखी ''अनरिवीलिंग बिहार ग्रोथ मेरिकल'' । उसमें उन्होंने लिखा चिराश्री दासगुप्ता ने, जो आज जेएनयू में प्रोफेसर हैं, पहले हॉर्वर्ड में पढ़ी थी कि लालू यादव जैसा और असाधारण प्रतिभा का आदमी सैंकड़ों वर्ष बाद पैदा होता है ।

इसलिए बिहार के लोगों को शुक्र मनाना चाहिए । जब से मोदी और बिहार में भाजपा की सत्ता आयी है, बिहार का गरीब, बिहार का पिछड़ा, बिहार का दलित बेहाल हो रहा है । गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और जिस बजट की चर्चा करते हुए सत्ता पक्ष के लोग नहीं थकते हैं उसकी क्या हालत है यह हम जरूर बताना चाहते हैं और माननीय सदस्यों को भी बोलना चाहिए । 90 फीसदी आवाम के लिए इस सदन में क्या है भई ? ये बड़े आकार, बड़ी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं कि 3 लाख 17 हजार करोड़ का बजट हो गया । इकॉनोमिक्स का ठीक से आपको ज्ञान नहीं है । एक मेरे मित्र जो सत्ता पक्ष के हैं वह इस ओर इशारा कर रहे थे कि मुद्रास्फीती की दर को देखते हुए जरा लालू यादव जी के कार्यकाल को देखिये । 2004–05 में सोने का क्या भाव था 4 हजार रुपये प्रति दस ग्राम, मटन का क्या भाव था 30 रुपये किलो, आज क्या है 800 रुपये, 1 लाख रुपये । तो आज पूरे देश के बजट के आकार को देखिये । नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं । 2005 के मुकाबले 10 गुना बजट में वृद्धि हुई है । यह कौन सी वृद्धि है भई ? पूरे देश में वृद्धि हुई है । बिहार का, झारखंड का बजट क्या था 2004–05 में, 8.5 हजार करोड़ । वह बजट बढ़कर कितना हो गया है 1 लाख 45 हजार करोड़। इसीलिए उल्टे–सीधे आंकड़े प्रस्तुत करके सदन को गुमराह न करिये । मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि बिहार के बारे में ठीक से जानना चाहिए । बिहार को बहुत गलत जानकारियां प्रस्तुत की जा रही हैं । यह जो सवर्ण मीडिया है और यह जो सवर्ण राजनेता हैं, यह हमेशा झूठ की खेती करते हैं और यह झूठ की खेती अधिक दिन चलने वाली नहीं है । एक आंकड़े के साथ मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं । बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है । 70 फीसदी से अधिक लोग खेती पर जीते हैं बिहार में । उसके जीविकोपार्जन का माध्यम क्या है ? खेती और खेती से उनका कुछ नहीं होता है । आज वह पलायन करने के लिए, दर–दर भटकने के लिए विवश है । यही है सुशासन, यही है गवर्नेंस । यह जो विकास का और गवर्नेंस का मॉडल नीतीश कुमार जी का है वह सबसे खराब है, उसकी जितनी निंदा की जाय वह बहुत ही कम है । अभी मैं एक आंकड़ा और बताना चाहता हूं, जानकर खुशी होगी । लालू जी के जंगलराज के बारे में जो लोग हर दिन आलोचना करते हैं ।

(व्यवधान)

मित्र, जरा कृपया करके सुन लीजिए । लखेन्द्र भाई, आपके हित में ही बोल रहा हूं ।

तो आप यह जान लीजिए कि बिहार के बारे में, बिहार के जंगलराज के बारे में जो पूरी आलोचना होती है...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य संक्षिप्त कीजिए । आपका समय दो मिनट है ।

श्री भारत भूषण मंडल : अमेरिका के दो बड़े लेखक, जो बड़े रिपोर्टर हैं, जो बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं वॉल्टर होजैट और जेफ्री विट्सो, यह जनतंत्र का सबसे बड़ा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति है । उन्होंने कहा कि लालू यादव के कार्यकाल में जो ऊंची जाति और सामंती लोगों की जकड़न में कैद था 90 फीसदी लोग उसको लालू यादव ने आजाद करा दिया और उसके बाद चारों दिशा में बिहार की प्रगति शुरू हो गयी । इसीलिए विकास और गवर्नेंस का जो सड़ागला मॉडल बिहार का है, जो बिल्कुल बेकार है इसको पलट देना चाहिए और जो गरीबों का विजयोल्लास लालू यादव जी के साथ था, राबड़ी जी के साथ है उसी रास्ते पर चलकर बिहार को आगे ले जा सकता है ।

(क्रमशः)

टर्न–16 / धिरेन्द्र / 06.03.2025

...क्रमशः...

श्री भरत भूषण मंडल : महोदया, क्या है बिहार की स्थिति ? कृषि क्षेत्र पर 1.1 परसेंट खर्च किया जा रहा है । यह बिहार के गरीब लोगों के साथ, किसानों के साथ मजाक नहीं तो क्या है ? सारा जो बजट है यह केवल ऊंची जाति के टुटपुंजिये लोगों और जो बड़े पॉकेटमार हैं, जो ग्लोबल टेंडर जोतने वाले लोग हैं उन पर खर्च किया जा रहा है । यह बिहार में लोगों के आँख में धूल झोंकने का काम ये भाजपा लोग कर रहे हैं और एक उदाहरण देकर मैं बात खत्म करता हूँ । ये भाजपा कॉंग्रेस क्या है ? जरा इसको देखिये, श्री नीतीश मिश्रा अपनी राजनीति कहाँ से शुरू कियें ? कॉंग्रेस से, और कहाँ पहुँच गए ? भाजपा में, यह जरा देखिये क्लास कैरेक्टर....

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री भरत भूषण मंडल : महोदया, मैं एक मिनट में खत्म करता हूँ....

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी, अपना पक्ष रखें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया । अब बैठ जाइये ।

श्री प्रफुल्ल मांझी : सभापति महोदया, आपने बिहार सरकार की बजट पर हमें बोलने का मौका दिया बहुत–बहुत आभार और हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हम अपने नेता श्री जीतन राम मांझी जी का, संतोष मांझी जी का और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का....

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी, आप दो मिनट थोड़ा बैठ जाइये । उनको एक मिनट बोलने दिया जाय ।

श्री भरत भूषण मंडल : महोदया, मैं तो उठा कर देख रहा हूँ राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल से परेशान हैं । कॉंग्रेस में सारा स्लीपर सेल भरा हुआ है। जनता दल (यू) में भाजपा का सारा स्लीपर सेल भरा हुआ है, 90 फीसदी जनता दल में भाजपा का स्लीपर सेल है, इसीलिए दोनों एक जगह आ गए हैं...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी, अपना पक्ष रखें।

श्री भरत भूषण मंडल : इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर यही रफ्तार रहा तो बिहार को बचाना मुश्किल हो जायेगा....

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है, आप बैठ जायें ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : सभापति महोदया, आज हमें आपने बिहार के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत–बहुत आभार और हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं बिहार सरकार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और अपने उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का, साथ–ही–साथ हम अपने नेता श्री जीतन राम मांझी जी और संतोष मांझी जी का जिन्होंने हमें यहाँ तक लाने का और सिकंदरा की महान जनता को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं ।

आज बजट पर जो बातें चल रही हैं, यह सच बात है कि बजट चौमुखी विकास का द्योतक है और सभी क्षेत्रों में विकास का जो परचम लहराया गया है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में और उसको आगे बढ़ा रहे हैं सम्राट चौधरी जी । चाहे हम शिक्षा की बात करें, बिजली की बात करें, सड़क की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें तमाम महकमों में हम अगर महिलाओं की बात करें, आज व्यवस्था किया गया है महिलाओं के लिए, जो कर्मशील महिलाएं हैं उनके लिए प्रमुख शहरों में छात्रावास बनाया जायेगा, पिंक टॉयलेट बनाया जायेगा, पिंक बसों का परिचालन किया जायेगा जिसमें सारे

कर्मचारी महिला ही रहेगी और अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य की स्थिति में जितनी सुधार हुई है उसको हम गिनायेंगे तो 151 तरह का टेस्ट होता है और 138 तरह की दवाएं हॉस्पिटल में रहती है । हम शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा में निचले स्तर से ऊंचे स्तर तक जो व्यवस्था की गयी है वह काबिल–ए–तारीफ है । आज अनुसूचित जाति के बच्चे हों, चाहे एस॰टी॰ के बच्चे हों, चाहे पिछड़ा–अति पिछड़ा का बच्चा हो शिक्षा की ओर उन्मुख में है और इसी का कारण है कि हम, आई॰ए॰एस॰ पहले दूसरे राज्यों से यहाँ आकर सर्विस करते थे, आज हमारे राज्य के भी लड़के–लड़कियां आई॰ए॰एस॰ और बी॰पी॰एस॰सी॰ में अपना परचम लहरा कर सेवा देने का काम कर रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं । हम बात करते हैं अनुसूचित जाति का जो आज हम बजट में देख रहे थे, हम सुन रहे थे और उसमें पढ़ भी रहे थे कि बजट में जो अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए, अति पिछड़ों के बच्चों के लिए, एस॰टी॰ के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति दोगुनी की गई है, प्राक शिक्षा का प्रारंभ किया गया है, जो लड़के–लड़कियां बी॰पी॰एस॰सी॰ में पी॰टी॰ परीक्षा उत्तीर्ण करेंगी, प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करेंगी उसे सरकार 50 हजार रुपया देगी, जो मेन्स परीक्षा क्वालिफाई करेंगी उसे 01 लाख रुपया सरकार देने का काम करेगी । सरकार ने जो शिक्षा में आमूल–चूल परिवर्तन करने का काम किया है, यही बिहार के बजट का द्योतक है और साथ ही हम सड़क की बात करते हैं तो सड़क हम देखते हैं, हम पहले गड्ढा खोजते थे कि गड्ढा कहाँ–कहाँ है ? हम अपने मोटर साईकिल और साईकिल को बचा कर चलेंगे लेकिन आज जो सड़क की स्थिति है वह देखने लायक है । अगर हम रात में भी चलते हैं तो बत्तियां, जो बिजलियां, बताता है कि कहीं गड्ढा नहीं है, हम तारे आसमान में देखा करते थे, अब तो सड़क पर हम तारे का नजारा लेते हैं और साथियों को हम यह कहना भी चाहेंगे कि मानव भूल कर सकता है, वह झूठ बोल सकता है लेकिन दर्पण यथार्थ बताता है, दर्पण का काम है सत्य को बताना और सत्य को दिखाना । इसलिए साथियों आप जानना चाहते हैं कि बिहार का बजट जो चौमुखी बजट है उसमें सारे क्षेत्रों में जो विकास किया गया है, चाहे महिलाओं के बारे में, बिजली के बारे में, जल संसाधन के बारे में । हमारे क्षेत्र में अभी मुख्यमंत्री जी गये थे वहाँ उन्होंने बहुत घोषणाएं की....

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य, आपका समय पूरा हो गया है, अब समाप्त किया जाय ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : सभापति जी, आपका हमको संरक्षण चाहिए, एक मिनट हम चाहेंगे। हम अपने क्षेत्र की भी बातें रखना चाहते हैं । हम कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जब हमारे क्षेत्र में गए थे.....

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी जी । आप अपना पक्ष रखें । आपका समय 10 मिनट है ।

श्री विद्या सागर केशरी : सभापति महोदया, आज वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट सत्र के वाद–विवाद में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है ।

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्यगण, शांति बनाये रखिये ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदया, इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी का, माननीय सभापति महोदया का, अभिभावक तुल्य श्रद्धेय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री सम्राट चौधरी जी का एवं आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी का, मुख्य सचेतक श्री जनक सिंह जी का सहित फारबिसगंज विधान सभा के सम्मानित जनता को मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिनके कारण आज हमें सदन में बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है ।

माननीय सभापति महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि यह बजट न्याय के साथ विकास के संकल्प को मजबूत करेगा । सभापति महोदया, पिछले साल सरकार ने 02 लाख 78 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया था इस बार सरकार ने 03 लाख 17 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया है जो पिछली बार से 38 हजार 169 करोड़ रुपये अधिक है । सभापति महोदया, सेवा और सुशासन के मतलब को हमको सबसे पहले जानना होगा और उसके लिए हमें गुड गवर्नेंस की बात को भी समझना होगा चूंकि पिछले तीन दिन से आय–व्यय को लेकर बजट को सदन में लाया गया है, इस बजट में बहुत सारे हमारे माननीय लोगों ने अपनी–अपनी बात को रखने का भरसक, अच्छा प्रयास किया है लेकिन मैं भी कुछ अपनी बात अपनी ओर से रखना चाहता हूँ । गुड गवर्नेंस देने का काम, जहाँ अच्छा शासन प्रणाली, अच्छा शासन विधि सुनिश्चित हो उसे ही हम गुड गवर्नेंस कहते हैं । सुशासन का मतलब है किसी सामाजिक, राजनीतिक इकाई को इस तरह से चलाना कि वह वांछित परिणाम दे सके । सभापति महोदया, सुशासन के जरीय सरकार के कार्य प्रणाली में सुधार होता है और लोगों के जीवन में बेहतर परिणाम भी आते हैं । सभापति महोदया, सुशासन का मतलब ही है किसी सामाजिक, राजनीतिक इकाई को सही तरीके से चलाना, जहाँ सैद्धांतिक रूप से अच्छा बजट, सही प्रबंधन, कानून का शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, जिम्मेवारी, संवेदनशीलता, लोकतंत्र, नागरिक की भागीदारी, सदाचार इन मूल्यों की आवश्यकता होती है, तभी हम अच्छा सुशासन दे सकते हैं । अभी हमारे माननीय सदस्य ने सुशासन से संदर्भित बहुत सारी बातों को रखने का प्रयास किया था । लालू जी के जीवन से संदर्भित भी बातें इस सदन में इन्होंने रखा था, कोई माननीय का

नाम मैं नहीं बताना चाहता हूँ लेकिन किसी माननीय ने कहा था कि लालू जी को भी भारत रत्न से नवाजा जाय...

...क्रमशः...

टर्न–17 / संगीता / 06.03.2025

(क्रमशः)

श्री विद्या सागर केशरी : महोदया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारत रत्न से किसको नवाजा जाय । उसको जो अपने परिवार के लोगों को ही मुख्यमंत्री अपने नहीं रहने के बाद अपने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री बनाते हैं । उसको जो अपने परिवार के लोगों को ही उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, जो परिवारवाद को ही बढ़ावा देने का काम करते हैं तो ऐसे लोग जो जंगलराज के प्रणेता रहे हैं जो 15 साल के शासनकाल में हत्या, बलात्कार और जिस प्रकार से जो अपहरण का उद्योग चलाया करते थे ऐसे लोगों को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं लेकिन मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेन्द्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि बिहार के लिए जो उन्होंने काम किया और बिहार के श्रद्धेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो काम अभी वर्तमान समय में चलाया जा रहा है उनके प्रति मैं आभार प्रकट इसलिए करना चाहता हूं कि छोटा सा उदाहरण है कि जो काम दुनिया ने लंबे समय से जो देखने का काम किया उसमें आज हमलोगों को चरितार्थ हो रहा है । जैसे– गंगा जल को फल्गु नदी से मिलाना, फल्गु नदी से मिलाकर उसको संगम को स्थापित किए हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से वे काम किए हैं, यह सनातन संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा जीता–जागता उदाहरण है और सनातनी लोग उनको हृदय से आशीर्वाद देंगे कि गया में जिस प्रकार से पिंडदान किया जाता है तो वहां जो इस प्रकार का जो उन्होंने एक कदम बढ़ाया है यह बहुत ही एक अच्छा संदेश जाता है । प्रयागराज में इतना बड़ा कुंभ लगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम वहां दिखा, जो सनातन के इतिहास को दिखाया गया, वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इन लोगों के माध्यम से 15 साल की जो शासन व्यवस्था था उस शासन व्यवस्था को भी हमलोगों ने देखा है महोदया कि हमलोगों ने तो यहां तक देखा है महोदया कि नेपाल के जो प्रहरी होते थे जो आग्नेयास्त्र के साथ जाकर पूर्णिया में रैली में भाग लिया करते थे उनलोगों का इतना खौफ था कि पूर्णिया के रैली में नेपाल के लोग जाकर अपने आग्नेयास्त्र के साथ जाकर इनकी रैली में सम्मिलित होते थे, नेपाल के लोग, बॉर्डर एरिया के लोग भी डरते थे और मैंने उस समय में देखा था, इन लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से पूछता था कि भाई आपका क्या काम चल रहा है तो वे बोलते थे हमारा रोड का काम चल

रहा है, रोड पर हमारा व्यापार चल रहा है, भाई कैसा रोड पर व्यापार चल रहा है तो भर दिन सुबह 10 बजे जाते थे 4 बजे आते थे तो शिक्षक से पैसा वसूली करना और लोगों का अपहरण करना ये सारा काम इन लोगों के द्वारा किया जाता था और आज ये बढ़–चढ़कर बोलते थे । कल हमारे एक माननीय सदस्य, हमारे ही सदस्य बोल रहे थे कि जिस प्रकार से शिल्पी को, चंपा विश्वास के साथ बलात्कार किया गया क्या वह शासन आज फिर यह देश और यह राज्य दोहराना चाहती है, कभी दोहराना नहीं चाहेगी ।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो काम एन0डी0ए0 सरकार लगातार करती जा रही है उस काम के प्रति इन लोगों को आभार प्रकट करना चाहिए । सड़कों के संदर्भ में इन्होंने अपनी बात को रखा था कि किस तरीके की सड़कें बिहार में बनायी जा रही हैं तो सड़क कितना बन रहा है इनको अच्छी तरह से मालूम है कि जो जहां से 250 लोगों का भी बसावट था, वैसी सारी सड़कों को पूरा कम्प्लीट किया गया है । मुझे लगता है कि बहुत कम ही जगह पूरे बिहार में बचा होगा जहां 250 की संख्या हो, जहां बसावट 250 का था वह शेष बचा हुआ होगा । वैसे जो छूटे हुए बसावट थे, जहां एक सौ की संख्या लोगों की रही है, वैसे भी बसावटों को चयनित किया गया है और वहां भी रोड का काम किया जा रहा है । जो सड़के टूट–फूट गई थीं, जहां क्राउड ज्यादा था वहां ज्यादा उन्नयन का काम करके चौड़ीकरण–मजबूतीकरण का भी काम करवाया जा रहा है । सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है । पहले की जो स्थिति थी 2005 के बाद जो आज बिहार की स्थिति है उसको भी हमको समझना पड़ेगा ।

सभापति महोदया, शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने बताया कि शिक्षा का क्या स्तर है, लोग मध्याह्न भोजन की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं । पहले क्या था, इनकी शिक्षा की स्थिति कैसी थी, उसका भी चिंतन आपको करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि पहले 15 साल का जो कानून व्यवस्था इनका था, वह कैसा था, वह देखना पड़ेगा कि हमको किस प्रकार से बच्चों को किस ओर ले जाया करते थे ये लोग, छात्राएं घर से नहीं निकलती थीं, महोदया। छात्राएं पढ़ने से कतराती थीं और आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्रद्धेय नीतीश कुमार जी का जो शासनकाल रहा, ये जो 19 साल का शासनकाल रहा, आज गांव की लड़कियां साईकिल को टनटनाती हुई निकलती हैं और अच्छे स्तर की पढ़ाई करती हैं । पहले लोग बैंगलोर में, कलकत्ता में, पटना में, दिल्ली में इंजीनियरिंग करवाने के लिए, मेडिकल करवाने के लिए, ए0एन0एम0 करवाने के लिए बच्चों को भेजा करते थे । आज हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है, आई0आई0टी0 सेंटर खुल गया है, आज ए0एन0एम0 कॉलेज खुला हुआ है,

मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, डाइट सेंटर खुल रहा है, हर बच्चे जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम इंजीनियरिंग कर लेंगे, हम एम0बी0बी0एस0 कर लेंगे आज वह सब चीज गांव में भी देखा जा रहा है तो शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े हुए हैं, हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़े हुए हैं और स्वास्थ्य को लेकर जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही थीं कि स्वास्थ्य में बिहार बहुत पीछे रह गया है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार में जब महागठबंधन के साथ में जो सरकार थी उस समय में 6–6 या 7–7 विभाग हमारे प्रतिपक्ष के नेता को दिया गया था । मैं खुद इसका साक्षी हूं कि लगातार मैं इनके मंत्रालय में जाया करता था, मुझे अपने क्षेत्र का बहुत सारा काम करवाना था, चाहे वह ग्रामीण कार्य विभाग का हो या स्वास्थ्य विभाग का हो, अन्य विभाग का हो लेकिन कभी भी माननीय प्रतिपक्ष के नेता जो वर्तमान में हैं, कभी भी वे मंत्रालय में सुशोभित नहीं हुए और हमलोगों का चप्पल–जूता खिया गया लेकिन एक दिन भी हमलोग वहां मंत्रालय में नहीं देखे, इस तरह की इनकी व्यवस्था थी और आज जाकर देख लीजिए कोई भी मंत्रालय में जहां भी मंत्री जी का चैंबर है हमलोग जाते हैं, सब काम कराते हैं और एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि मुंह देखकर काम होता है, एन0डी0ए0 की जो सरकार है वहां मुंहदेखा काम होता है – बिल्कुल गलत बोल रहे थे । हमलोगों ने तो अनुभव किया है कि जहां भी काम हो रहा है चाहे प्रमंडल स्तर पर हो रहा है या विधान सभा स्तर पर हो रहा है सबको समान अधिकार दिया गया है...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य, अब समाप्त किया जाय ।

श्री विद्या सागर केशरी : सबलोग समान काम कर रहे हैं । हमारा...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य आपका समय हो गया, अब समाप्त किया जाय ।

श्री विद्या सागर केशरी : महिला सशक्तिकरण पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा फोकस रहा...

सभापति (श्रीमती ज्योति देवी) : माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार जी, अपना पक्ष रखें । माननीय सदस्य सतीश कुमार जी ।

श्री विद्या सागर केशरी : सारा फोकस महिलाओं पर ज्यादा से ज्यादा रहा । मखाना का जो क्षेत्र है बिहार, 85 परसेंट मखाना बिहार से जाता है इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री...

श्री सतीश कुमार : माननीय सभापति महोदया, आज हम विपक्ष की तरफ से बजट पर परिचर्चा में भाग लिए हैं इसके लिए प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद

यादव जी हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और बहुत दिनों के बाद ऐसा संयोग है कि इस रमजान के पवित्र महीने में बजट सत्र शुरू हुआ है, रमजान के पवित्र महीने में ही खत्म हो जाएगा इसलिए रमजान की भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं । महोदय, हम कहना चाहते हैं इस बजट के बारे में वित्त मंत्री यहां बैठे हैं एक गाने की लाइन है कि ''आंख है भरी–भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो'' तो बिहार के नौजवानों का, बिहार के किसानों का, बिहार के मजदूरों का आंख भरा हुआ है और ये बजट कह रहे हैं कि फिलगुड करो, कैसे फिलगुड कर सकता है महोदय, सबसे ज्यादा शिक्षा पर इन्होंने पैसा लिया है 19.24 प्रतिशत इन्होंने शिक्षा पर पैसा लिया है लेकिन शिक्षा पर जो बजट का पैसा तो दिया गया है लेकिन ये 20 साल की बात कर रहे हैं, 20 साल में एक एग्जाम लेने का ट्रांसपैरेंट व्यवस्था भी इन्होंने नहीं बनाया है । आज बी0पी0एस0सी0 जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आज बी0पी0एस0सी0 को लोग बोलते हैं कि बिहार पेपर स्कैम कमीशन बन गया है...

(क्रमशः)

टर्न–18 / सुरज / 06.03.2025

श्री सतीश कुमार : (क्रमशः) महोदय, इसके लिये बी0पी0एस0सी0 के जो छात्र हैं वह महीनों दिन से लगातार धरना पर हैं कि उनका जो पेपर हुआ है, जो चीटिंग हुआ एग्जाम उनका कैंसिल किया जाए । इस मांग को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और दूसरी तरफ महोदय, उन्होंने बापू परीक्षा केन्द्र पर 12 हजार छात्रों का परीक्षा तो कैंसिल किया । इस टेक्नोलॉजी के युग में एक जगह की परीक्षा तो कैंसिल करते हैं और बाकी जगह ट्रांसपैरेंट तरीके से कैसे परीक्षा हुआ यह तो बताना चाहिये । इसलिये हम चाहते हैं कि यहां परीक्षा को कैंसिल करके फिर से परीक्षा लिया जाए । क्योंकि उन 12 हजार छात्रों को अलग से विशेष अवसर दिया गया और यदि उनके परीक्षा केन्द्र का अध्ययन किया जाए तो बापू सभागार के 12 हजार छात्रों में 20 प्रतिशत बच्चे प्रिलिमनरी एग्जाम में पास किये हैं और जबकि ओवरऑल 6 प्रतिशत बच्चे पास किये हैं । तो किस तरीके का एग्जाम, एक समानता का अधिकार जो देता है आर्टिकल 14 उसका उल्लंघन हो रहा है । इसलिये हम चाहते हैं कि बिहार में यदि शिक्षा पर पैसा खर्चा हो तो एग्जामिनेशन लेने का भी ट्रांसपैरेंट व्यवस्था हो । तब यहां के छात्रों की उम्मीद जगेगी शिक्षा व्यवस्था पर और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में एक हजार करोड़ रुपया अलग से लिया गया है । स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में बताया गया है कि 3 लाख 70 हजार बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया है

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

लेकिन यह नहीं बताया गया कि कितने बच्चों को नौकरी में, कितने बच्चों को नियोजन उस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने की वजह से मिला है । यह नहीं बताया गया है । आज बिहार की स्थिति यह हो गयी है कि बेरोजगार नौजवान स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने के बाद नौकरी ढूंढ रहा है और सर्टिफिकेट केस हो गया है तो उसको पुलिस ढूंढ रही है । यह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आज हरेक नौजवान को कर्जदार बना रहा है इसलिये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को खत्म किया जाय और यदि सरकार चाहती है तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को स्टार्ट किया जाय ताकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता न हो । जैसे 2016 के पहले पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलता था, किसी को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं होती थी और गरीब घर के दलित पिछड़े बच्चे भी जाकर के हायर एजुकेशन में अपना दाखिला लेते थे । बहुत अच्छी बात है और सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि 358 कॉलेज इन्होंने प्रखंड लेवल पर खोलने की बात कही है लेकिन यह कब तक खुलेगा, क्या यह मिशन 2047 तक खुलेगा ? ये तो टाइम बाउंड बताया ही नहीं गया, यह तो गुमराह करने वाला बजट है । यह कॉलेज कब तक खुल जायेगा हम हरेक माननीय सदस्य, हरेक बिहार का नौजवान युवा जानना चाहता है कि यह कब तक खुल जायेगा ? इसलिये हम कहना चाहते हैं कि बगैर टाइम बाउंड के यदि कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं होता है ।

अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के बारे में बजट अलग से, महिलाओं को एड्रेस किये हैं इसके लिये धन्यवाद, मांझी आबादी है उनका एड्रेस भी होना चाहिये । लेकिन महिलाओं को एक पिंक सपना दिखाया गया है कि पिंक बस चलेंगे, पिंक टॉयलेट बनेगा लेकिन इस राज्य में जो कामकाजी महिलाएं हैं उनका तनिक भी ध्यान नहीं रखा गया है । आज 01 लाख 12 हजार 255 से ज्यादा आंगनवाड़ी सेंटर हैं और उसमें सेविका, सहायिका लगभग 2 लाख काम करती हैं । लेकिन उनका मानदेय क्या है, क्या सरकार ने उस तरफ कभी ध्यान दिया ? उनका मानदेय पूरे देश में बिहार में सबसे फिसड्डी है 1450 रुपया हम सेविका को देते हैं और 725 रुपया हम सहायिका को देते हैं । जबकि वहीं बगल के राज्य झारखंड में वहां की सरकार 5 हजार रुपया सेविका को देती है और 2.5 हजार सहायिका को देती है । जहां पर एन0डी0ए0 की सरकार है मध्य प्रदेश में 7 हजार सेविका को और 35 सौ रुपया सहायिका को देते हैं । लेकिन बिहार में मात्र 1450 रुपया यह बड़े शर्म की बात है । यदि पैसा ले रहे हैं तो अब महिलाओं को भी सशक्त किया जाए जब तक उनके घर में पैसा नहीं जायेगा तो ये सशक्त नहीं होंगे ।

दूसरा, हम कहना चाहते हैं सिपाही के मामले में बिहार पूरे देश में महिला सिपाही के मामले में सबसे अव्वल है । हम सैल्यूट करते हैं कि 35

प्रतिशत उनको अलग से आरक्षण दिया गया और महिला सिपाहियों की संख्या बढ़ी । लेकिन यह बात नहीं बताया गया कि सिपाही दम्पत्ति के मामले में भी बिहार सबसे अव्वल है । आज पति, पत्नी दोनों सिपाही में काम कर रहे हैं । हमारे साथ बॉडीगार्ड भी 24 घंटा परिवार छोड़कर हमारे साथ रहता है लेकिन शिक्षा विभाग ने उनके बच्चों को अलग से पढ़ने का कोई व्यवस्था किया ? क्या नेतरहाट, सैनिक, नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय की तरह कोई पुलिस स्कूल खोलने का इन्होंने उपाय किया कि उनके बच्चे भी सही से तालिम ले सकें और विपरीत परिस्थिति में भी सिपाही हमारी रक्षा कर सकें, हमारे लॉ एंड आर्डर का समाधान कर सकें । हम सरकार से चाहते हैं कि पुलिस विद्यालय की स्थापना हो कम से कम प्रमंडल लेवल पर जहां पर पुलिस के बाल–बच्चे आवासीय व्यवस्था में पढ़ सकें और जीविका दीदी के बारे में, अगर जीविका दीदी की चर्चा न हो तो बिहार का बजट अधूरा है । डेढ़ करोड़ से ज्यादा जीविका दीदी की महिलाएं इस योजना से जुड़ी हैं । प्रत्येक सप्ताह 10 रुपया जमा करती हैं, इसका मतलब हुआ कि 15 करोड़ रुपया प्रत्येक सप्ताह, महीने में 60 करोड़ रुपया । यदि साल में जोड़ा जाए तो 720 करोड़ रुपया जीविका दीदी जमा करती हैं बिहार के खजाने में । लेकिन जीविका दीदी को क्या मिलता है 1 लाख से ज्यादा जो कम्यूनिटी मोबिलाइजर जिसको सी0एम0 कहते हैं उससे मात्र 25 सौ रुपये पर हम काम ले रहे हैं । यह कैसा महिला सम्मान हम कर रहे हैं महोदय । यह दुःखद है, हम चाहते हैं कि उनका सम्मानजनक वेतन लागू किया जाए और नहीं तो यह नाटक जो आप कर रहे हैं, महिलाओं को ठगने का जो काम कर रहे हैं इसको बंद किया जाए । यह हम आपसे कहना चाहते हैं ।

स्वास्थ्य व्यवस्था का बजट 6.32 प्रतिशत टोटल बजट का स्वास्थ्य पर खर्चा किया जा रहा है लेकिन कैसा स्वास्थ्य व्यवस्था । क्या बिल्डिंग बना देने से, उसका पेंट पोचारा कर देने से क्या ईलाज हो जायेगा ? जब आप जाईयेगा तो वहां डॉक्टर नहीं हैं । आधे से ज्यादा डॉक्टर के पद खाली हैं, आधे से ज्यादा टेक्निशियन के पद खाली हैं, आधे से ज्यादा मशीन खराब हैं । जहां पर न अल्ट्रासाउंड हो रहा है न सिटी स्कैन हो रहा है तो कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था । बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरीके से आप प्राइवेट हाथों में ढकेलना चाहते हैं । यह आपकी मंशा साफ–साफ दिखाई देती है । यहां पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रूल के तहत प्राईवेट जी0एन0एम0 और बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेजें खोली गयी लेकिन वह रूल कहता है कि उनको 100 बेड का पैरेंट अस्पताल होना चाहिये । कितने निजी नर्सिंग कॉलेज के पास पैरेंट अस्पताल है । यदि 100 बेड का पैंरेट अस्पताल होता तो कोरोना में हम कितने लोगों की जान बचा पाते । यह सरकार सिर्फ उन निजी लोगों को

लाभ पहुंचाने के लिये 4 रूम, 8 रूम, 10 रूम के कमरों में उनको कॉलेज चलाने की इजाजत दे रहा है । इस पर भी रोक लगानी चाहिये । गया का डी0पी0एस0, जी0एन0एम0 और बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज या महोदय बेगूसराय जब हम गये थे तो बेगूसराय का यमुना इंस्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग जो है वहां पर हमारी कमेटी को कोई निजी नर्सिंग होम नहीं मिला । तो कैसी व्यवस्था, कैसा जी0एन0एम0, कैसा ए0एन0एम0 हम तैयार करना चाहते हैं?

दूसरी तरफ जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो आशा दीदी की यदि बात न करें तो अधूरा होगा । बिहार में संस्थागत प्रसवों में सबसे ज्यादा सहयोग आशा दीदी ने किया है लेकिन आशा दीदी को हम क्या देते हैं यदि 8 घंटे के अंदर डिलीवरी हुआ तो हम 3 सौ रुपया देते हैं । 8 घंटा 1 मिनट पर हुआ तो एक रुपया भी नहीं देते हैं । इस व्यवस्था को खत्म किया जाए । यदि वह आशा दीदी प्रसूता को लेकर अस्पताल में आती है और 8 घंटा 1 मिनट में डिलीवरी होता है तो 8 घंटे का मेहनत उसका बेकार चला जाता है । तो आशा दीदी को भी सम्मानजनक मानदेय तय करना चाहिये ।

दूसरी तरफ हम अपने क्षेत्र की भी बात करेंगे । बराबर एक विश्व पर्यटक स्थल है जहां पर दुनिया का पहला मानव निर्मित गुफा है जो सम्राट अशोक ने बनवाया था । वहां पर, उसके ऊपर में सावन में एक बड़ा मेला लगता है और सावन के मेले में 12 अगस्त, 2024 का वह काला दिन जहां पर भगदड़ हुई और सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त हताहत हुये, भगदड़ में मारे गये । क्योंकि वहां पर हम वर्षों से मांग कर रहे हैं कि वहां पर्यटक अस्पताल बनाया जाय । यदि बराबर में पर्यटक अस्पताल होता तो हम सैकड़ों लोगों की जान बचा सकते थे...

अध्यक्ष : केवल दो मिनट है आपके पास ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, दूसरी तरफ नगर एवं विकास विभाग की तरफ हम अपना इशारा करना चाहते हैं । 20 साल से नीतीश जी इस बजट को पेश कर रहे हैं लेकिन क्या नगर में बसने वाले गरीब लोगों को वासगीत पर्चा का अधिकार हम कब देंगे ? क्या नगर में जो नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत में जो रहते हैं क्या उनको वासगीत पर्चा का अधिकार है कि नहीं ? उनकी जमीन नहीं रहने की वजह से हम उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दे पाते हैं । तो हम चाहते हैं कि सरकार नगर में भी बसे हुये योग्य बसावट को यदि वह योग्य जमीन पर बसे हुये हैं तो उनको पर्चा निर्गत करें, जिससे प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ उनको मिल सके । लालू प्रसाद यादव जी ने सोचा था, रैन बसेरा बनाया था । मछुआ टोली में जाकर आप देखिये डुप्लेक्स बनाया था और गरीबों को

दिया था । यदि जमीन कम है तो अपार्टमेंटनुमा 2 बी0एच0के0 का फ्लैट बनाकर के हम गरीबों को दे सकते हैं । यह व्यवस्था शहरी गरीबों के लिये लेकर के सरकार को आना चाहिये ।

टर्न–19/राहुल/06.03.2025

श्री सतीश कुमार : (क्रमशः) हम यही कहना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यहां पर शिक्षा विभाग है । जो समावेशी शिक्षक हैं, वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 19 साल से काम कर रहे हैं और...

अध्यक्ष : सतीश जी, केवल एक मिनट है ।

श्री सतीश कुमार : 826 लोगों का अभी तक समायोजन नहीं किया गया जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है और हम दिव्यांग लोगों के लिए तीन महीने के कैंप वाली स्कूल खोलते हैं, तीन महीने के बाद वे घर चले जाते हैं जो कैंप में सीखते हैं वह भी भुला जाते हैं । इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि उनको सालों भर एक बोर्डिंग स्कूल की तर्ज पर डीफ एंड डंब छात्रों को शिक्षा देने का काम करें। यह सरकार को बजट में लेना चाहिए और हमारा...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, हम एक और बात बोलकर अपनी बात खत्म करेंगे । महोदय, राहत इंदौरी साहब की एक लाईन है उस लाईन को बोलकर के हम अपनी बात को खत्म करेंगे कि

सफर में आखिरी पत्थर के बाद आयेगा ।
मजा तो यार दिसंबर के बाद आयेगा ।।
मेरा जमीर, मेरा एतबार बोलता है,
मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है ।
साहब कुछ और काम जैसे आता ही नहीं,
मगर वह झूठ बहुत शानदार बोलता है ।

बहुत–बहुत धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : श्री पवन कुमार जायसवाल, 8 मिनट में अपनी बात समाप्त करिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचेतक जी और ढाका विधान सभा की जनता को बहुत–बहुत आभार है । महोदय, जंगलराज वाली सरकार ने अंतिम बजट 23885 करोड़ का प्रस्तुत किया था उस समय शिक्षा पर मात्र 1311 करोड़ का बजट था । इनकी शिक्षा में पहचान भवनहीन विद्यालय, भूमिहीन विद्यालय, जर्जर भवन, चरवाहा विद्यालय, 10–15 किलोमीटर की दूरी पर हाईस्कूल कार्यरत होते थे, ऐसे में थी और आज हमारी एन0डी0ए0 सरकार की पहचान सुंदर विद्यालय भवन, अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज खोल दिये गये और प्रखंड स्तर पर डिग्री

कॉलेज खोलने की हमारी सरकार ने घोषणा की है, बेहतर चहारदीवारी, पोशाक, छात्रवृति, मध्याह्न भोजन और हाईस्कूल को उत्क्रमण करना, प्रत्येक पंचायतों में हाईस्कूल की स्थापना हमारी सरकार की उपलब्धि है । महोदय, स्वास्थ्य के मामले में इनका बजट 811 करोड़ का होता था, आज हमारी सरकार का बजट 20335 करोड़ है, इनके समय मरीज अस्पतालों में जाने से डरते थे कि अगर सरकारी अस्पताल में जायेंगे तो जान चली जायेगी और आज सरकारी अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए विधायकों को पैरवी करनी पड़ रही है, हम लोग कभी–कभी नाराज हो जाते हैं कि हम लोगों की पैरवी का मरीज भर्ती नहीं हो पाता है । इनके समय में मरीज सरकारी अस्पतालों में जाने से डरते थे, हमारे समय में दवा फ्री में मिल रही है, डॉक्टरों की व्यवस्था हुई है, अनुमंडल अस्पताल ऐसे बने हैं, पी0एम0सी0एच0 का भवन जैसा पहले इनके समय में रहता था वैसा हमारा अनुमंडल अस्पताल, अनुमंडलों में बना है । पी0एच0सी0 दुरूस्त हो गये, ए0पी0एच0सी0 दुरूस्त हुए, अब एच0एस0सी0 तक को दुरूस्त करने की बात हो रही है ।

महोदय, सड़क के मामले में इनका 3200 करोड़ का बजट होता था आज 17000 करोड़ का बजट हमारी सरकार ने पेश किया है । इनके समय सड़क बनती नहीं थी, अलकतरा घोटाला होता था और इनके मंत्री जेल जाते थे और आज हमारी सरकार ने एक लाख सत्रह हजार किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया । 23500 एम0एम0जी0एस0वाई0 का और 7000 किलोमीटर लेफ्ट हाइड्रेशन की सड़क का टेंडर करने का काम किया है । महोदय, 5300 पुल–पुलिया का निर्माण हुआ और आज 600 पुल–पुलिया के निर्माण की स्वीकृति हई है, टेंडर होने जा रहा है । इनको काम से मतलब नहीं है, ये हमारी बनाई हुई सड़क पर चलेंगे, हमारी सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेंगे और सदन में बैठकर हम ही लोगों की शिकायत करेंगे । जिसका खायेंगे उसी की थाली में छेद करेंगे, कब तक चलेगा । अच्छा काम करते हैं तो प्रशंसा करनी पड़ेगी । महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में इनका बजट...

अध्यक्ष : एक मिनट, पवन जी । उन्होंने प्रशंसा की है, उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए बढ़िया–बढ़िया काम सरकार ने किया है । बोलिये ।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में इनका...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये । बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार जायसवाल : बजट 1609 करोड़ होता था और ऊर्जा के क्षेत्र में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप लोग बैठिये, बैठिये । स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : हमारी सरकार का बजट 13468 करोड़ है । इनके समय में इसी सदन में जब निर्दलीय विधायक 2010 में जीतकर आये थे तो ट्रांसफॉर्मर का मामला उठता था, तार, पोल का मामला उठता था, हमारी सरकार में, एन0डी0ए0 की सरकार में एक मामला ट्रांसफॉर्मर और तार, पोल बदलने का नहीं आता है । हमारी सरकार ने घर–घर बिजली पहुंचाने का काम किया है, हमारी सरकार ने हर खेत तक बिजली पहुंचाने का काम किया है । इनके समय जले हुए ट्रांसफॉर्मर को बदलने के लिए सदन में प्रश्न आते थे, इनके समय में बिजली नहीं मिलती थी, कब बिजली आयी, कब बिजली गयी लोगों को पता नहीं चलता था, हमारी सरकार 22 घंटे, 24 घंटे बिजली देने का काम कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग में इनका बजट 292 करोड़ था, हमारा बजट 17831 करोड़ है । आज ये माई–बहिन योजना लेकर घूम रहे हैं, इनके शासनकाल में आई0ए0एस0 की पत्नी, आई0ए0एस0 की मां, आई0ए0एस0 की भतीजी, और आई0ए0एस0 के दो–दो नौकर के साथ दो साल बलात्कार होते रह गया और ये सुनने वाले नहीं थे । आज बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, माई–बहिन योजना चला रहे हैं, उस समय सुशील मोदी जी नहीं होते, उस समय राज्यपाल का हस्तक्षेप नहीं होता तो उस महिला को, उस परिवार को न्याय नहीं मिल सकता था । आप कौनसी योजना लेकर आयेंगे । महोदय, इनके समय जंगलराज था, आप जातीय नरसंहार को उठाइये, 1999 में जहानाबाद के सेनारी में 34 अगड़ी जाति के लोगों की हत्या हुई, 1997 में लक्ष्मणपुर–बाथे में 58 दलित गर्भवती महिलाओं, बच्चों की हत्या हुई, 1999 शंकरबिगहा में 22 दलितों की हत्या हुई, 1996 में बथानी टोला में 22 मुस्लिम, दलित और पिछड़ी जाति के लोगों की हत्या हुई, 1992 में बारा नरसंहार में 35 अगड़ी जाति के लोगों की हत्या हुई और 2000 में मियापुर नरसंहार में 35 दलितों की हत्या हुई । आपकी सरकार में जातीय नरसंहार होते थे, आपकी सरकार में सांप्रदायिक दंगे होते थे, आप उनको प्रश्रय देते थे, आपके समय में सी0एम0 हाउस में अपराधी बैठते थे, अपहरणकर्ता को संरक्षण मिलता था और हमारी सरकार में, सुशासन की सरकार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है । आप हों या हम हों, जाइये मोतिहारी में स्वर्ण प्रभात एस0पी0 हैं एक दिन में दो–दो सौ घर की कुर्की जब्ती होती है और आपके समय में अपराधी मुख्यमंत्री के बगल में बैठते थे और आपसे न्याय की उम्मीद करेगा कोई, आपने राज्य के अपराधियों का मनोबल बढ़ाया, महिलाओं के साथ जो कुकृत्य हुए हैं आपके शासनकाल में...

अध्यक्ष : इधर देखकर बोलिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : आपको बिहार की जनता कभी माफ नहीं कर सकती है । महोदय, ये कब्रिस्तान के घेराबंदी की बात करते हैं, मठ, मंदिरों की घेराबंदी से

इनको मतलब नहीं है । हमारी सरकार ने कब्रिस्तान की भी घेराबंदी की और मठ–मंदिरों की घेराबंदी की भी अभी योजना लायी है । हमारी सरकार ने अक्लियत की जो महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके लिए 25000 रुपये बढ़ाकर कर दिये, आपकी सरकार ने कभी एक चॉकलेट देने का काम नहीं किया किसी भी तलाकशुदा महिलाओं को ।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रखंड कार्यालयों में भवन बना रही है, एक साथ पूरे बिहार में बचे हुए प्रखंड कार्यालय भवन निर्माण की योजना को स्वीकृत कर दिया 16 करोड़ का, 20–20 करोड़ की। अनुमंडल कार्यालय के भवन बन रहे हैं, अनुमंडलों में व्यवहार न्यायालय बन रहे हैं, उतना ही नहीं पंचायतों में महादलित, सामुदायिक भवन बन रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, नगर में सम्राट अशोक भवन का निर्माण हो रहा है । इनके समय में क्या होता था, इनके समय में पश्चिमी चंपारण के दियारा में अपहरणकर्ता लोगों का अपहरण करके बंद करने का काम करते थे, इनके समय में लालू जी, राबड़ी जी के शासनकाल में अपराधी इनके बगल में बैठते थे और बिहार में व्यवसायियों का शोषण होता था, हम व्यवसायी समाज से आते हैं, सैकड़ों, हजारों लोग दुकान बंद करके दूसरी जगह चले गये । हम लोग मुम्बई चुनाव में गये थे, भोपाल चुनाव में गये थे, लोग कहते थे कि यह पता होता कि नीतीश कुमार, भाजपा की एन0डी0ए0 सरकार अगर बिहार में रहेगी तो हम लोगों को बिहार छोड़ने की नौबत नहीं आती । शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों को जिसके राज–पाट में लोग अपनी जायदाद को कम पैसे में बेचकर बाहर में जाकर शिफ्ट करने का काम किये, आप किसकी बात करते हैं, किसको बढ़ावा देते हैं ? आज दल की बात सदन के अंदर करते हैं, बाहर में आप कहते हैं कि नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, कई विधायक कहते हैं बाहर में, आप कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार की सरकार को सजाने और संवारने का काम किया है । बाहर में आप एन0डी0ए0 की बड़ाई करते हैं, सदन में बैठकर आप एन0डी0ए0 के कार्यों की शिकायत करते हैं, यह दुधारी काम चलने वाला नहीं है । केन्द्र में नरेन्द्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हमारी सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और 2025 में...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : फिर से 225 जीतकर आयेंगे और बिहार में अपनी सरकार बनायेंगे ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक पर हुए सामान्य विमर्श पर अब सरकार का उत्तर होगा ।

टर्न–20 / मुकुल / 06.03.2025

सरकार का उत्तर

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025–26 के वार्षिक बजट के 3 तारीख को रखा गया और उस पर दो दिनों से लगभग 19 माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को रखा है । आज बिहार में लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सबका साथ–सबका विकास के साथ–साथ न्याय के साथ विकास । इस प्रदेश में आप सोचिए कि जहां 23 हजार करोड़ रुपये का बजट था, उसको आज बढ़ाकर 3 लाख 17 हजार करोड़ का बजट आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ और आप देखेंगे कि कई मानकों में जिस तरह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ वह अपने आप में अनोखा है लेकिन मैं जरूर यह कहना चाहता हूं प्रथम कि 2025–26 में जो कई चीजों का स्वरूप बनाने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है, आपने देखा कि जिस तरह किसानों की चिंता, क्योंकि हमारे प्रदेश में लगभग 57 परसेंट लोग आज भी खेती पर निर्भर हैं, उनको किस तरह से बाजार उपलब्ध हो, चाहे वह धान अधिप्राप्ति का काम हो, गेहूं अधिप्राप्ति का काम हो और अब तो इससे भी बढ़कर जो अरहर का, मूंग का, उरद का इसको भी हमलोग नेफेड और एन0सी0सी0एफ0 के माध्यम से इसको भी क्रय करने का काम इसी वित्तीय वर्ष से शुरू करने जा रहे हैं ये अपने आप में अनोखा है कि हमारे लोग जो किसान हैं उनको उचित मूल्य मिल सके उसकी व्यवस्था की जा रही है । अभी लगभग 1289 करोड़ से नाबार्ड के माध्यम से इस पूरे प्रदेश में कृषि उत्पादन बाजार समिति का जीर्णोद्धार का भी काम चल रहा है जो इस बजट में उसको और बढ़ाकर जो हमारे अड़तीसों जिले के कृषि उत्पादन बाजार समिति है उसको पूरी तरह जीर्णोद्धार करने का काम किया जायेगा और इसके साथ–साथ जो सभी प्रखंड हैं, प्रखंड के स्तर पर दो बड़े फैसले लिये गये हैं जिस तरह सुधा के दूध को, कल तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी शुरुआत करने वाले हैं, अभी तक तो हमलोग बिहार में बेचते थे, देश में बेचते थे, कल दूध बेचने का काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी शुरुआत करने वाले हैं । यह अपने आप में अनोखा है कि हम दुनिया के मार्केट में जा रहे हैं, हम प्रदेश के मार्केट में गये और आसाम से लेकर बंगाल तक हम दूध भेजने के काम की शुरुआत किये हैं । मछली उत्पादन का काम लगभग दोगुना, हमारा मछली उत्पादन हो चुका है, अंडा लगभग डेढ़ गुना से अधिक का उत्पादन हो चुका है तो इन सारी चीजों को प्रदेश के स्तर पर अपने प्रखंड में कैसे रखें, इसके लिए भी चिंता हमलोगों ने की है । अभी सभी अनुमंडल और सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए चरणबद्ध तरीके से इसकी पूरी

व्यवस्था की गयी और स्वाभाविक है इसके लिए पूरी समिति चाहिए तो अभी लगभग 300 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति का गठन हो चुका है, इसको 534 ब्लॉक में इसका निर्माण का काम शुरू किया जायेगा और उसके हो जाने के बाद हमलोग इसी वित्तीय वर्ष में जिस तरह सुधा का दूध उपलबध कराने की चिंता कर रहे हैं उसी तरह गांव में जो सब्जी उत्पादन का काम होता है, तरकारी सुधा आउटलेट भी सभी प्रखंडों में खोलने का काम किया जायेगा । इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि कई लोग यह चिंता करते हैं कि बिहार में बाजार कैसे मिलेगा और बाजार इसी के लिए हमलोगों ने महिलाओं के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो लंबे समय से स्वयं सहायता समूह के लिए, जीविका दीदी के लिए काम कर रहे हैं और जहां हजार की संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह में थी, आज 10 लाख स्वयं सहायता समूह बिहार में है और 1 करोड़ 31 लाख महिला उससे जुड़ी हुई हैं, यह अपने आप में अनोखा है कि जिस प्रदेश के 18 वर्ष से अधिक की जो महिला है उन सबमें से एक तिहाई से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं । उसकी भी चिंता हमलोगों ने अपने बजट में किया है, महिलाओं के लिए हाट का स्थापना करना, बड़े शहरों में वेंडिंग जोन पूरी तरह स्थापित करने का काम किया जायेगा, इसके साथ–साथ हम उनको फीट भी रख सकें, अपने जीवन को स्वाभाविक अपने परिवार के लिए जीती हैं, अपने पति और बच्चों को जब व्यवस्था करके वे जब फ्री होती हैं उसके लिए भी हमलोगों ने तय किया है कि अभी हमलोग प्रयोग के तौर पर वे फीट कैसे रहें जिम ऑन व्हील उनको उपलब्ध कराने का काम करेंगे जिससे कि वे फीट रहने का काम कर सकें। इसके साथ–साथ उद्योग, क्योंकि स्वाभाविक है उद्योग जबतक नहीं बढ़ेगा हम आर्थिक रूप से समृद्धि नहीं हो पायेंगे, हमारे यहां कोई माहौल नहीं था, कई साथी कहते हैं लालू जी का राज–लालू जी का राज, मैं उसको भी विस्तार से बताऊंगा कि उनके राज में क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है । आज पूरी स्थिति को आप समझिए कि आज बिहार जैसे प्रदेश में 1 लाख 81 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि सिंग्ल विंडो सिस्टम से इसको तुरंत जमीन उपलब्ध कराने का काम कीजिए तो लगभग 72 हजार करोड़ की राशि के लिए हमलोगों ने जमीन भी उपलब्ध कराने का काम किया है और इसके साथ–साथ लगभग 3 हजार एकड़ जमीन लैंड लॉक स्टेट माना जाता है बिहार । इसके बावजूद कई जगहों पर माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से जमीनों को क्रय करने का काम राज्य सरकार ने किया, कई जगह गैर मजरूआ, आम जमीन को भी लिया गया और लगभग हमलोगों का टारगेट है कि इस वित्तीय वर्ष में अभी 3 हजार एकड़ जमीन हमलोगों ने उपलब्ध कराया है, आगे के

दिनों में इसको 10 हजार एकड़ उपलब्ध कराकर बिहार में पूरी तरह उद्योग का माहौल बनाने का काम किया जायेगा । इसके साथ–साथ बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2025 लाने की सहमति हमलोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, साथ–साथ किसानों की आय वृद्धि हो इसके लिए भी वायोफिल्स के लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति–2025 लाने का निर्णय लिया गया है और मैं इस मंच के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं । अभी भागलपुर आये थे, दो बड़ी घोषणा उनके बजट में भी हुआ था, एक मखाना बोर्ड का निर्माण जो आदरणीय कृषि मंत्री जी स्वयं आये और दरभंगा जाकर अपने से किसानों के बीच में कैसे खेती होती है उसको देखने का काम किया और उसके लिए भी 100 करोड़ रुपया अलॉट करने का काम केन्द्र की सरकार ने किया है । फूड प्रोसेसिंग इंस्टिट्यूट के तौर पर कैसे हमारे यहां केला है, हमारे यहां जो मकई है, हमारे यहां और जो फल हैं, ड्रेगन फ्रूट हमारे यहां होते हैं, इनको कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, मक्का का, लीची का इन सब चीजों को कैसे और आगे बढ़ाने का काम किया जायेगा तो इन पूरी चीजों का अध्ययन किया गया । अभी प्रधानमंत्री जी ने तीन और बड़ी घोषणा की है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर भागलपुर में जर्दालू आम के लिए, मुंगेर में और बक्सर में टमाटर और प्याज की ऊपर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया है, जिससे की स्वाभाविक है कि हमारे जो किसान हैं वह कैसे आत्म निर्भर हो सकें, उसका पूरा अध्ययन करने का काम किया गया है । बिहार में एक बड़ा उद्योग बन सकता है, क्योंकि हमारी 14 करोड़ की आबादी है और मैं एहसास करता हूं, मैं जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक–डेढ़ महीने के लिए स्वास्थ्य विभाग का काम दिया था तो मैं बता सकता हूं कि जब हमलोगों ने एक नीति लागू की कि जो जिस व्यक्ति को भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा मुफ्त अनाज देने का काम किया जाता है और वैसे व्यक्ति को इलाज के लिए भारत की सरकार के द्वारा 6 करोड़ 29 लाख परिवार को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सहयोग से लगभग 2.5 करोड़ लोगों को दोनों मिलाकर लगभग 9 करोड़ लोगों को एक तरह से आयुष्मान भारत कार्ड देने का निर्णय लिया, मैं जानकर आश्चर्य करता हूं कि जब मैंने यह फैसला 2 मार्च, 2024 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से लिया तो 15 दिनों में मैं 17 तारीख को, दूसरे माननीय मंत्री मंगल जी हो गये और इन 15 दिनों में 2 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन इसी बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड में गरीबों का होने का काम हुआ है । यह स्वाभाविक है, आज गरीबों को इसकी जरूरत थी और इसके लिए हमलोग फार्मासुटिकल के सेक्टर में उपकरण खरीदने के लिए जो एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है उसको भी हमलोग 2025 में, अभी तुरंत हमलोग तैयार कर चुके हैं इसको भी लाने का काम करेंगे । प्लास्टिक के सेक्टर में

लौहिया स्वच्छता अभियान के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लौहिया स्वच्छता अभियान चलाया गया, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मिलकर इस पूरे काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इसको भी पूरी तरह व्यवस्थित करना, कैसे हम वेस्ट टू वेल्थ आगे बढ़े, कचरा का प्रबंधन कैसे करें ।

....क्रमशः.....

टर्न–21 / यानपति / 06.03.2025

(क्रमशः)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, कचरा का प्रबंधन कैसे करें, शहरों के अंदर कैसे कचरा प्रबंधन करें और ग्रामीण इलाके में भी कचरा का कैसे प्रबंधन करें और उसके बाद उससे प्लास्टिक का निकालकर उसको एक नए उद्योग के रूप में खड़ा करें इसकी चिंता भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है इसलिए......

श्री महबूब आलम : उद्योग–धंधे सब बंद हो गए हैं, बर्बाद हो गए ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं, यह ठीक कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : यह भी तो बताना चाहिए महबूब साहब आपको कि बंद कब हुआ, 1990 से लेकर 2005 के बीच में बंद हुआ, यही तो कहना है । अच्छी बात आप कह रहे हैं । आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें बताया कि चीनी मिल बंद हो गया, चीनी मिल बंद होने का कारण भी बताना चाहिए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मैं यह बताना चाहता हूं......

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : कि लगभग 36 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट इतना प्लांट में आया और आज किसान जो है अपना मक्का, अपना गन्ना उसमें बेचने का काम कर रहे हैं । आपको पता ही नहीं है और अब तो लगातार, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में गए थे और सीतामढ़ी में रीगा सुगर मिल की

चिंता रोज करते थे, रीगा सुगर मिल की भी शुरुआत करने का काम किया साथियों । कुछ लोग आजकल गलतफहमी फैलाने में लगे हैं......

(विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

क्योंकि ये लोग भागने वाले हैं, तो मैं यह बताना चाहता हूं, अब देखिए ये लोग अब भागने वाले हैं तो मैं यह बताना चाहता हूं कि लोगों ने इसी सदन में भ्रम फैलाने का काम किया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने यह नहीं बताया कि उनके पिताजी ने क्या–क्या किया ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए)

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2001 में जहां बिहार जैसे राज्य में मात्र 6 हजार रुपया आमदनी थी प्रति व्यक्ति आय की और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 6 हजार से बढ़कर यह 66 हजार हो गया, 11 गुणा अधिक आज आमदनी हो चुकी है और जिस तरह ये लोग कहते हैं, लालू जी के राज में 1990 से लेकर 2005 तक यदि काम हुआ होता तो आज बिहार में नीतीश जी को काम करने की जरूरत नहीं होती । क्योंकि वह पूरा गैप मिला, 15 साल तक काम ही नहीं हुआ, सिर्फ नाच–गाना होता रहा, यही था लालू जी का बिहार । कोई विकास की बात नहीं हो रही थी, बिहार में विकास की चर्चा भी नहीं होती थी आप समझिए, आज नीतीश कुमार जी के 20 साल में पूछते हैं कि क्या हुआ ? आप समझिए कि वर्तमान में 34 परसेंट गरीबी रेखा के लोग हैं और जब इनको सत्ता मिली थी तो 54 परसेंट बिहार के लोग गरीब थे । पता नहीं कौन किताब लेकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन आए थे । लालू जी ने तो पढ़ाया नहीं यह तो हम नहीं बताएंगे लेकिन लालू जी का पूरा परिवार पता नहीं किस असत्य में जुटा हुआ है और किस भ्रम में अपने जीवन को जी रहा है । अब सोचिए, ये लोग कहते हैं कि हम दुनिया के गरीब प्रदेश हैं और जब 2000 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो कल उन्होंने कहा कि 4 हजार करोड़ रुपया हमको मिला, बिहार को और लगभग 9 हजार करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश को मिला और 6 हजार करोड़ रुपया गुजरात को मिला लेकिन जब एक्चुअल फिगर देखिएगा 2001 और 2002 में तो बिहार को लगभग साढ़े 7 हजार करोड़ रुपया श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देने का काम किया । इसलिए असत्य बताने के लिए, ये लोग सिर्फ असत्य फैलाना क्योंकि पता नहीं कौन–कौन डाटा, कौन किताब पढ़ रहे हैं क्योंकि बचपन में पढ़े नहीं । क्रिकेट खेलते वक्त तो पानी ढोते रह गए बेचारे, खेलने का भी मौका नहीं मिला, अरे खेलते तो एक बात थी । पूरे जीवन काल में मात्र 37 रन जो बनाता हो वह अपने जीवन में क्या करेगा ? भला इतना दिन क्रिकेट खेला हो और 37 रन

बनाता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य अपने जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकता और आप सोचिये कि यह कहते हैं कि साक्षरता दर 1994 में 3 प्रतिशत थी । 3 प्रतिशत तो अभी केरल में है, उस समय कहां से बिहार में आ गयी, ये सिर्फ भ्रम फैलाने वाले लोग हैं । आज बिहार की स्थिति मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि जो प्राथमिक विद्यालय का ड्रॉप आउट रेट 9.6 है, प्राथमिक अपर विद्यालय में 26 प्रतिशत है और जब लालू जी का राज था तो आपको जानकर आश्चर्य होगा यह 60 प्रतिशत से अधिक था । यह आज जो बता रहे हैं यह 3 प्रतिशत, जो सबसे समृद्ध राज्य जहां सबसे ज्यादा पढ़ने की बात होती है केरल, उस केरल में 3 परसेंट अभी है । इसलिए सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, ये लोग कभी विकास की बात नहीं कर सकते हैं, ये लोग हारने वाले लोग हैं और देखिये पूरा इतिहास है । वर्ष 1990 में भारतीय जनता पार्टी का, नीतीश कुमार जी का समर्थन नहीं होता तो लालू यादव जी मुख्यमंत्री होते क्या ? एकदम भाजपा और जनता दल का सपोर्ट था इसलिए लालू जी मुख्यमंत्री हुए लेकिन वे मुख्यमंत्री बनने के बाद बदल गये । वे आज भी कहते हैं कि हमको डराने का काम भाजपा कर रही है। याद कीजिए, यहां कई वरिष्ठ साथी बैठे हैं, 1996 में किसकी सरकार थी ? 1996 में जब चार्जशीट हुआ तब देश में देवगौड़ा जी की सरकार थी, जो जनता दल की सरकार थी । न नीतीश कुमार जी उसके भागीदार थे, न भारतीय जनता पार्टी भागीदार थी । 1997 में जब लालू जी जेल गये पहली बार रिक्शा पर चढ़कर कहा कि राजा जेल जा रहा है, किला में रहेगा, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ? इन्द्रकुमार गुजराल जो पटना से चुनाव लड़ रहे थे, वे भी जनता दल के थे, किसी दूसरी पार्टी के नहीं थे लेकिन उनको लगता है क्योंकि सबूत तो उसी समय आये । कोई सबूत तो अभी आया नहीं । सारे सबूत उसी समय इक्कट्ठा किये गये और वे जेल गये इसलिए मैं जरूर यह बताना चाहता हूँ कि बिहार के विकास में लालू प्रसाद जी का कोई योगदान नहीं है और स्वाभाविक है कि जिस उप मुख्यमंत्री को यही नहीं पता हो कि बिहार में या किसी देश में दो ही तरह की ताकत होती है जिसमें पूरी पावर एक तरह से एलॉट होती है । ये लोग कहते हैं हमारी सरकार और हम भाजपा और जदयू के लोग कहते हैं नीतीश कुमार की सरकार । अध्यक्ष महोदय, फर्क देखिये, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है और वे कहते हैं कि हमारी सरकार है । उस बेचारे को तो ज्ञान ही नहीं है संविधान का, करें क्या हमलोग ? क्योंकि उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि कैबिनेट का डिसीजन बिना मुख्यमंत्री के नहीं हो सकता है और सरकार का कोई भी निर्णय, मंत्री को एक तरह से काम मुख्यमंत्री देते हैं और मुख्यमंत्री काम देकर कहते हैं कि इस काम को बढ़ाइये और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सारी सहमति होती है । जिसको संविधान का ज्ञान नहीं हो और ये लोग कहते हैं मेरी पार्टी । स्वाभाविक है पिता की पार्टी है इसको तो मैं डिनाय नहीं कर

सकता हूं । स्वाभाविक है 1997 से लेकर आजतक एक ही व्यक्ति चाहे वह चार्जशीटेड हो या अपराधी की तरह पंजीकृत अपराधी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही आदमी हैं । पार्टी उन्हीं की है लेकिन मैं 2010 में जब चुनाव जीतकर आया, उनके परिवार के एक भी सदस्य सामने बैठने वाले नहीं थे, एक भी सदन में जीतकर नहीं आए, मैं जीतकर आया । यहां राघवेंद्र जी बैठे हैं जो उस समय हमलोगों के साथ भी चुनाव जीतकर आए थे, इसलिए एकदम स्पष्ट है, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए लालू प्रसाद जी के परिवार का कोई योगदान नहीं है । आज बिहार के बजट पर मैं जरूर स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, ये लोग कहते हैं कि बिहार में पैसा खर्च नहीं होता है । यह भी हम बताना चाहते हैं । आदरणीय बिजेन्द्र बाबू फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, आदरणीय विजय चौधरी जी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, आदरणीय सुशील जी रहे हैं, आदरणीय तारकिशोर जी रहे हैं लेकिन जब–जब एन0डी0ए0 की सरकार रही है तो जब मैं देखता हूं पूरी रिपोर्ट, बिहार में जो खर्च की स्थिति रही है वह 95 से 98 परसेंट राशि बिहार की जनता के लिए खर्च करने का काम किया गया और पिछले वित्तीय वर्ष में भी हमलोगों ने 96.26 प्रतिशत खर्च किया था, उसके पहले भी 97.57 प्रतिशत राशि खर्च करने का काम किया था ।

(क्रमशः)

टर्न–22 / अंजली / 06.03.2025

(क्रमशः)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : और अभी भी हमारी, जबकि हम एक महीने से सी0एफ0एम0एस0 का जो नया वर्जन है उसको लाने में हमको थोड़ी कठिनाई हुई लेकिन उसको भी हमने ठीक किया और आज की स्थिति में आपको जानकार आश्चर्य होगा कि लगभग 84 परसेंट राशि हमने खर्च कर ली है और हम विधान सभा के सभी सदस्यों को एश्योर करते हैं कि 31 मार्च तक पूरी राशि को खर्चा करके बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कल तक आप सोचते भी नहीं थे, नॉर्थ बिहार में 1990 के मुख्यमंत्री कहा करते थे कि उत्तर बिहार में जो गरीब है उसको मछली खाने के लिए बाढ़ आ जाता है तो उसके घर में मछली आ जाती है लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से लेकर 2025 तक इस तरह विकास के आयाम को बढ़ाने का काम किया है । याद कीजिए, 2007–08 में जब बाढ़ आया, 21 जिले में 14 जिले में बाढ़ का पानी घुस गया और आज 2024 में जब 1 लाख 92 हजार क्यूसेक पानी नेपाल से छोड़ा गया

तब स्थिति थी और आज साढ़े 6 लाख क्यूसेक पानी कोसी के माध्यम से आया तब भी 50 पंचायतों से अधिक पानी नहीं मिला, सभी पंचायतों में बाढ़ तक नहीं आता है । इसलिए अब तो फ्लड फाइटिंग की जगह पर, यहां विजय बाबू बैठे हैं, ये इरिगेशन का काम देख रहे हैं, भारत सरकार भी लगभग साढ़े 11 हजार करोड़ रुपया हमको इरिगेशन के फैक्टर में देने का काम किया और पूरे नॉर्थ बिहार में कैसे इरिगेशन को और सिस्टमैटिक किया जा सकता है और इंटरलिंकिंग, नदियों को जोड़ने का काम, कोसी–मेची लिंकिंग को जोड़ने का काम, कोसी को ठीक करने का काम कई जगह हाई लेवल डैम बनाने का काम और मैं यह गर्व से कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कल तक फ्लड फाइटिंग का काम किया जाता था, अब सिंचाई का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और सिर्फ उत्तर बिहार नहीं, दक्षिण बिहार में भी ।

आप देखिए कई आपको डैम्स मिलेंगे चाहे वह राजगीर हो, नवादा हो, गया हो, इंद्रपुरी बराज को जोड़ा जा रहा है औरंगाबाद से, सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव डैम पानी ले जाने का काम किया जा रहा है और खड़गपुर झील ले जाने का काम किया जा रहा है, चैनल की सफाई करने का काम किया जा रहा है, ओढ़नी डैम को पूरी तरह जीर्णोद्धार करने का काम किया जा रहा है तो पूरी तरह कैसे विकसित हो, हम कैसे सिंचाई में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सकें, किसानों को कैसे अधिक से अधिक सिंचाई के लिए व्यवस्था देने का काम कर सकें इस पर भी काम किया जा रहा है । इसके साथ–साथ श्रमिक भाई हमारे देश के कई प्रदेशों में रहते हैं उसकी भी चिंता हमलोगों ने की है, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली एन0सी0आर0, कोलकाता, गोवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर, चेन्नई में हमलोगों ने Migration Counselling cum Registration Centres खोलने का भी निर्णय लिया है । यह स्वाभाविक तौर पर लाखों की संख्या में जो अपराध किया है राष्ट्रीय जनता दल ने 15 वर्षों तक, उन 15 वर्षों के चलते जो गैप हुआ, लोग पलायन किए, जो पवन जायसवाल जी बोल रहे थे, वे आज पलायन करके दूसरे राज्य में गए हैं वहां काम करके आते हैं, हम आत्मनिर्भर खड़ा हो रहे हैं और हमलोग अब चाहते भी हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर दो दिन पहले इसी सदन में कहा कि अब हम लोग दस लाख सरकारी नौकरी, दस लाख रोजगार नहीं देंगे, हम बारह लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार देने का काम करेंगे और यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि नीतीश कुमार जी ने जब काम शुरू किया तो सभी फैक्टर्स में लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया और जानकर आश्चर्य होगा कि अभी मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे थे अभी तक तो 24 लाख रोजगार की बात हो रही थी, अभी तक हमलोग तीस लाख लोगों को रोजगार देने में पूरे बिहार में सफल हो चुके हैं । साढ़े 9 लाख से अधिक लोगों को पूरे प्रदेश में सरकारी नौकरी देने का काम किया है । आदरणीय

मुख्मयंत्री जी 9 तारीख को फिर जो बिहार में शिक्षक टीयर थ्री की परीक्षा हुई, उसके बाद नौकरी देने की पूरी एक व्यवस्था, नियुक्ति पत्र बांटने का काम 9 तारीख को गांधी मैदान में होने जा रहा है, उसमें भी लगभग 50 हजार से अधिक लोगों को सीधे सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा । इसके साथ–साथ हमलोगों ने छात्रवृत्ति सब का, किसी एक वर्ग का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं, एक जाति का नहीं, सब के लिए क्योंकि सब का साथ, सब के विकास की चर्चा हमलोगों ने की है, अल्पसंख्यक सहित छात्रवृत्ति सब की दोगुनी करने का निर्णय चाहे वह एस0सी0 / एस0टी0 वर्ग हो, अतिपिछड़ा हो, पिछड़ा हो या सामान्य छात्र हो सब को छात्रवृत्ति देने काम नीतीश कुमार की सरकार करने जा रही है । मैं जरूर बताना चाहता हूं, इन लोगों ने कहा कि छात्रवृत्ति लालू जी ने बढ़ाने का काम किया था वह भी मैं थोड़ी जानकारी दे दूं क्योंकि ये लोग सिर्फ असत्य फैलाना चाहते हैं, छात्रवृत्ति, ये कहते थे कि 1998–99 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसको 100 रुपए कर दिया था, एकदम यह सफेद झूठ है, असत्य है और मैं स्पष्ट तौर पर चुनौती देता हूं, उस समय 1998 और 1999 में मात्र 9 रुपया छात्रवृत्ति था मात्र 9 रुपये और पांचवे क्लास से लेकर छठे क्लास तक के लिए 18 रुपए था और सातवें से दसवें तक के लिए 36 रुपए था यह आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने इसको बढ़ाकर 150 करने का काम किया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन की राय से आज के निर्धारित कार्य के पूरा होने तक बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है । माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, और कई फैक्टर्स हैं जिसमें आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है । ये लोग कहते रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज हमने बनाया है, हमारे समय में बना, 2005 के पहले क्या था और आप याद कीजिए, पटना मेडिकल कॉलेज 1925 में बना, दरभंगा मेडिकल कॉलेज 1946 में बना, नालंदा मेडिकल कॉलेज 1970 में बना, जवाहर लाल नेहरू कॉलेज और अस्पताल भागलपुर में 1970 में बना, ए0एन0एम0सी0एच0 कॉलेज, गया, 1979 में बना और मुजफ्फरपुर में एस0के0एम0सी0एच0 1979 में बना और 1990 से लेकर 2005 तक जीरो मेडिकल कॉलेज बिहार में बनने का काम किया, एक भी कॉलेज नहीं खुला और मैं आपको बताता हूं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व का 2008 में बेतिया में मेडिकल कॉलेज खुला, पावापुरी में, नालंदा में 2010 में मेडिकल कॉलेज खुला, पटना में आई0जी0आई0एम0एस0 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2011 में करने का काम किया । 2019 में पूर्णियां में मेडिकल कॉलेज खोला गया । मधेपुरा में 2020 में मेडिकल कॉलेज खोला गया । 2024 में समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज खोला गया, छपरा में 2025 में मेडिकल कॉलेज खोला गया और अभी मैं गर्व से कह सकता हूं कि आदरणीय

मुख्यमंत्री जी जब प्रगति यात्रा पर चल रहे थे तो इन्होंने 7 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति देने का काम किया और ये लोग बात करते हैं, इनको क्या पता है ? अरे ये बउआ हैं, बउआ को जो लिख–पढ़ के दे देता है, बच्चा आकर वही पढ़ देता है, इनको ज्ञान तो होना चाहिए । इसके लिए कोई दोषी नहीं है कि तुम 36 वर्ष के हो लेकिन हम यह स्पष्ट बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी आज भी 74 वर्ष की उम्र में तुमसे चार गुना ज्यादा काम कर सकते हैं इतना स्पष्ट है । ये कौन गलतफहमी में हैं लालू प्रसाद का परिवार, मौका मिला बिहार को लूट लिया, बिहार में मेडिकल की पढ़ाई उनकी बेटी करेगी, कोई गरीब का बच्चा नहीं करेगा । उनका कोटा उन्हीं की बेटी को मिलेगा, उन्हीं के बच्चे को, यही तेजस्वी यादव थे जब 13 वर्ष, 14 वर्ष के होंगे तो इनको खेल पुरस्कार मिला बताइए, जो व्यक्ति 4 वर्ष की उम्र से घोटाला कर रहा हो, जमीन लिखवा रहा हो वह व्यक्ति को खेल पुरस्कार, अपने आप में दुर्भाग्य है और ये लोग कभी सामना नहीं कर सकते हैं यह मैं जरूर कह सकता हूं, मैं जानता हूं इनको भी जानता हूं, उनके पिताजी को भी जानता हूं और इनकी माता जी को भी जानता हूं और जो लालू जी कहते थे कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा यह मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार की जनता कभी भी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होने देगा ।

(क्रमशः)

टर्न–23 / पुलकित / 06.03.2025

(क्रमशः)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : लालू जी ने तो कहा कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा लेकिन पहले रानी लाये, फिर राजकुमार लाये और फिर राजकुमारी लाये। साथियों, यह लोकतंत्र है । अध्यक्ष जी, एकदम आज बिहार में बिहार की जनता सिर्फ नीतीश कुमार जी की तरफ देखती है और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की तरफ देखती है । महोदय, यह स्पष्ट है आदरणीय नीतीश कुमार जी 1996 से लगातार बिहार का काम कर रहे हैं । एन0डी0ए0 के साथ मिलकर और लम्बे समय से ये तो छात्र जीवन से ही बिहार के लिए काम कर रहे हैं इसलिए मैं जरूर आपसे आग्रह करूंगा और सभी सदस्यों से कि बिहार के बजट में आप सभी लोग क्योंकि आप सभी ने अपनी बातों को भी रखा है और एक अच्छा बजट बिहार में एक प्रयास किया है। नीतीश कुमार जी ने 20 साल तक बिहार को सींचने का काम किया है और आगे के 20 साल बिहार

कैसे खड़ा होगा इस बजट ने आपको उपस्थापित करने का काम किया है । इसलिए हम सभी सदस्यों से, माननीय सदस्यों से और विरोधी दल के भी सभी सदस्यों से जरूर आग्रह करेंगे कि आपलोग इस बजट को पास करके बिहार के उन्नत बिहार को जो पहले खटारा बिहार था, नीतीश कुमार जी को खटारा गाड़ी मिली थी और उस खटारा गाड़ी को आज मर्सिडीज बनाकर घूमा रहे हैं, इसके लिए मैं नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूँ । इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इस बजट को सभी लोग मिलकर पारित करने का काम कीजिएगा । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ और वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक पर सामान्य विमर्श भी समाप्त हुआ ।

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद–205 के अनुसरण में बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम, 2024, बिहार विनियोग (संख्या–3) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या–4) अधिनियम, 2024 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावे वर्ष 2024–25 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में, मैं तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 06 मार्च, 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 39 (उनतालीस) हैं । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 07.03.2025 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।